हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 2007

खण्ड–1, अंक–7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 19 मार्च, 2007

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7) 19
अतारांकित प्रश्न	(7) 29
राज्यपाल से संदेश	(7) 33
अनुपस्थिति की अनुमति	(7) 34
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(7) 34
न्यायाधीश भल्ला जांच आयोग की रिपोर्ट	(7) 35

मूल्य : 92

	पृष्ठ सख्या
सदस्य का नाम लेना	(7)36
बैठक का स्थगन	(7)38
श्री ओम प्रकाश चौटाला को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध	(7)39
विधान कार्य—	(7)41
1. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2007	(7)41
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007	(7)45
3. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन)विधेयक, 2007	(7)46
सदस्य का नाम लेना	(7)48
सदस्यों का निलम्बन	(7)50
इन्डियन नैशनल लोक दल के सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार की निन्दा करना ।	(7)52
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी प्रस्ताव	(7)59
वर्ष 2007-2008 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा	(7)63
बैठक का समय बढ़ाना	(7)85
वर्ष 2007-2008 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)85

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 19 मार्च, 2007

विधान सभा की बैठक, विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सवाल-जवाब होंगे।

Uncultivable Waste Land

*627. Dr. Sushil Indora : Will the Minister for Revenue be pleased to state the details of district-wise wasteland in the State which can not be made cultivable ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, the requisite information is placed on the table of the House.

Statement

Details of district-wise wastelands in the State which cannot be made cultivable :

Sr. No.	Name of district	Wastelands which cannot be made cultivable (area in hectares)
1	2	3
1.	Ambala	135
2.	Bhiwani	1,270
3.	Faridabad	1,427
4.	Fatehabad	46
5.	Gurgaon	1,782
6.	Hisar	505
7.	Jhajjar	1,663
8.	Jind	52
9.	Kaithal	742
10.	Karnal	319
11.	Kurukshetra	333
12.	Mahendergarh	5,960

1	2	3
13.	Mewat	5,295
14.	Panchkula	34,243
15.	Panipat	82
16.	Rewari	3,117
17.	Rohtak	263
18.	Sirsa	-
19.	Sonepat	787
20.	Yamuna Nagar	9,352
	Total area	**67, 373**

(Source : National Waste Land Development Board, Govt. of India and National Remote Sensing Agency, Hyderabad).

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से रिकार्ड के आधार पर मंत्री जी ने बताया है कि 67373 हैक्टेयर भूमि हरियाणा प्रदेश में वेस्ट लैंड है जो कृषि योग्य नहीं है जिसमें सिरसा जिले में सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जिसके तहत इस वेस्ट लैंड को डिवैल्प किया जा सके ? क्या इस वेस्ट लैंड पर सरकार कोई एस०ई०जैड० या उद्योग लगाने बारे विचार कर रही है जिससे इस वेस्ट लैंड का यूज हो सके और वहां रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके।

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, यह एरिया वह है जो रिवाईन है, बहुत गहरी है, उससे कम गहरी है और उससे भी कम गहरी है तथा इसमें वो एरिया भी है जो अंडर फोरैस्ट आता है जिस जमीन को हम टच नहीं कर सकते। इस लैंड में कुछ मार्सी लैंड है और कुछ सलाईन लैंड भी है। सलाईन और मार्सी लैंड को हम डिवैल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस जमीन को किस तरह से डिवैल्प किया जा सकता है इस बारे में उनके साथ मीटिंग की जाये और इस जमीन को डिवैल्प करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी किए हैं। मैं माननीय सांथी को बताना चाहूंगा कि हमारा विभाग इस जमीन को डिवैल्प करने के लिए प्रोजैक्ट बनायेगा उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि इस जमीन को डिवैल्प करने की कोशिश की जायेगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि सरकार इस हालत में नहीं है कि इस जमीन को डिवैल्प नहीं किया जा सकता तो क्या यह जमीन गरीब तबके के लोगों को देने बारे सरकार विचार करेगी ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, जमीन अलौटमैंट की बात नहीं हो रही है, जमीन को आबाद करने की बात हो रही है। यह तकरीबन 67373 हैक्टेयर जमीन है जिसको आबाद करने की बात है और सरकार इसको आबाद करने की पूरी कोशिश करेगी और जितनी जमीन डिवैल्प हो पायेगी और उसको डिवैल्प किया जायेगा।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का वेस्ट लैंड डिवैल्पमैंट विभाग है जो बंजर भूमि को ठीक करने के लिए सहायता करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में ऐसे कितने किसान या उपभोक्ता हैं जिन्होंने वेस्ट लैंड डिवैल्पमैंट विभाग से बैनीफिट लिया है और उसके तहत कितने एकड़ वेस्ट लैंड को ठीक किया गया है ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, यह सवाल वेस्ट लैंड को ठीक करने का नहीं है। यह सवाल उस जमीन के बारे में है जो ठीक नहीं हो सकती।

Construction of Roads in Narnaund Constituency

***665. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the State Government to construct the following roads in Narnaund constituency :—

1. from Dhani Kumbaran to Sisai-Lohari road;
2. from Majra to Madha ; and
3. from Rajli bridge to Datta via Khanpur ?

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : 1, 2, एवं 3 नहीं, श्रीमान् जी।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो हम बी०जे०पी० के एम०एल०ए० बन गये, कांग्रेस पार्टी के नहीं बने तो क्या सरकार में हमारा भी कोई हक है या नहीं है ? ये मामूली सी सड़कें थीं और लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि ढाणी कुम्हारान से सिसाय-लोहारी तक की सड़क बनाई जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : आपकी जो सड़कें बना दी हैं उनके बारे में तो बता दो।

श्री रामकुमार गौतम : सर, हमारी जो सड़क बनी है वो है पेटवाड़ से बास उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सड़क 12 फुट चौड़ी बनी है। इस रोड के ऊपर बड़े-बड़े गांव हैं इसलिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको 18 फुट चौड़ा बनाया जाये। ढाणी कुम्हारान से सिसाय रोड तक और माजरा से माढ़ा एक की लम्बाई तो 1.70 किलोमीटर और दूसरी 3.70 किलोमीटर की दूरी है जो कि ज्यादा दूरी नहीं है एक सड़क राजली ब्रिज से वाया खानपुर डाटा है। खानपुर जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है अगर आप इसको बनवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लोग आपका गुणगान करेंगे। कर दो दरियादिली हुड्डा साहब। जिस तरह किसी के घर बच्चा होता है तब थाली बजाते हैं उसी तरह लोग थाली बजायेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने अपने इलाके के साथ पक्षपात का प्रश्न उठाया है। मुझे लगता है कि इस सदन के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी फरमाया है और इनका यह मानना था कि कहीं इनके इलाके के साथ पक्षपात तो नहीं किया जा रहा है। स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा पिछले 2 साल में केवल नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के अन्दर सरकार ने 39.81

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

किलोमीटर की 14 नई सड़कें मंजूर की हैं। स्पीकर सर, इनकी जो नई सड़कें और रिपेयर वाली सड़कें हैं उनका कुल खर्च 2006-07 में 1583 लाख रुपये है। स्पीकर सर, नारनौंद की अगर मैं बात करूं तो मैं यह भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2003-04 में नारनौंद विधान सभा क्षेत्र में 451 लाख रुपये मात्र खर्च किया गया है। 2004-05 में कम करके यह राशि 233.86 हजार रुपये रह गई। पिछले 2 साल के आंकड़े बड़े रुचि वाले हैं जो कुछ और ही कहानी को दर्शाते भी हैं। वर्ष 2005-06 में पी०डब्ल्यू०डी० बी०एण्डआर० विभाग ने 690.76 हजार रुपये और वर्ष 2006-07 में फरवरी, 2007 तक 1621.98 हजार रुपये का खर्च हुआ है। जो मेजर वर्क्स इनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं उनकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा ताकि पता चले कि सदन के नेता की और सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल स्पष्ट है खास तौर से बी०जे०पी० के हमारे साथियों का तो सरकार विशेष ख्याल रखती हैं और गौतम साहब तो बहुत तजुर्बेकार भी हैं। फोर लेनिंग का सर, हांसी जीन्द रोड़ नारनौंद टाऊन में 2.2 किलोमीटर के टुकड़े पर 162.95 हजार उसके ऊपर खर्चा आयेगा। अपग्रेडेशन ऑफ हांसी, खुम्बा, थुराना, पेटवाड़ रोड, सर 20.70 किलो मीटर 368.71 हजार रुपये खर्च होगा। अपग्रेडेशन ऑफ हांसी-महजी डाटा रोड़ 19 किलोमीटर पर 406.97 हजार रुपये खर्च होगा और अपग्रेडेशन ऑफ खाण्डा खेड़ी उगलान रोड़ 10.70 किलोमीटर पर 316.26 हजार रुपया खर्च होगा। सर, एक बात मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 2000-2001 से लेकर 2004-05 तक की सरकार के ये जो भाई बैठे हैं उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में बी एण्ड आर विभाग ने सड़कों पर और ब्रिजिज पर मात्र 1744.83 हजार रुपया खर्च किया। इस सरकार के कार्यकाल में अब तक हम 1422.73 हजार मात्र 2 साल में खर्च कर चुके हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 7000 करोड़ रुपये का टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने तय किया है।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, काले आम का पुल ज्यादा फ्लड आने से गिर कर तबाह हो गया था। यह पुल हरियाणा स्टेट तथा हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के साथ जोड़ता है, अभी तक इस पुल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पुल को बनाने का काम विचाराधीन है और यदि हां तो यह पुल कब तक बन जाएगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न इस मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है। क्या इन्होंने इसके बारे में कभी माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिख कर दिया है (विघ्न) मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने इस पुल को बनाने के लिए कभी कोई पत्र लिखा है कि यह समस्या इतनी गम्भीर है ?

श्री अध्यक्ष : साढौरा साहब, आप इस प्रश्न के बारे में लिख कर भिजवा दें।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस पुल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ था। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यदि ये इस पुल के निर्माण के लिए सिंसियर और सीरियस होते तो इनको चाहिए था कि इस बारे में अलग सवाल देते या फिर कोई चिट्ठी सरकार को लिखते लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी इन्होंने जो विषय उठाया है, मैं इनकी तथा सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे ही यह पुल डैमेज हुआ था मुख्य मन्त्री जी ने खुद इसका नोटिस लिया और उन्होंने अपने कमरे में एक मीटिंग

बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने यह आदेश दिए कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इस पुल के टैंडर हमें रिसीव हो चुके हैं और बहुत जल्दी इस पुल को बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए इनको यह बताना चाहूंगा कि नौ महीने के अन्दर यह काम पूरा हो जाएगा।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या रादौर हल्के में कोई नई सड़क बनाई गई है या बनाने की कोई योजना है ? यह सड़क चाहे पी०डब्ल्यू०डी० की हो, चाहे मार्कीटिंग बोर्ड की हो क्या कोई सड़क बनाई गई है ?

श्री अध्यक्ष : पलाका साहब, यह सवाल नारनौंद हल्के से सम्बन्धित है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए आप सैपरेट क्वैश्चन दें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह सैपरेट सवाल लिख कर भेजें उनको पूरी जानकारी भिजवा दी जाएगी।

श्री साईदा खां : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के माध्यम से मैंने तीन दफा रिपीट करवाया था कि मेरे अपने गांव की सड़क की हालत बहुत खराब है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ओलावृष्टि का मुआयना करने के लिए कल-परसों मेरे हल्के में गए थे मेरे उस ऐरिया में सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है। मुख्य मन्त्री जी हैलीकॉप्टर से गए थे अगर वे बाई रोड जाते तो उनको सड़क की हालत का पता चलता, हो सकता है उन्होंने वह सड़क देखी हो (विघ्न) जहां तक मैं समझता हूं इस सड़क की कोई रिपेयर नहीं हुई ये तीन रोड्ज हैं नैशनल हाई वे नं० 71, 71-ए तथा 71-बी, यह सड़क पलवल नारनौल को जाती है यह खाली फोर लेनिंग ही बना रहे हैं जो पलवल से नारनौल रोड जाती है उस सड़क का बुरा हाल है। मुख्य मन्त्री जी जब वहां पर गए थे तो सड़क पर मिट्टी डलवाई गई थी उन्होंने स्वयं उस वक्त वहां पर देखा होगा (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, गौतम साहब ने भी यह कहा है कि सरकार भेदभाव कर रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यहां पर सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को मजबूर होकर खेतों में से घूम कर जाना पड़ता है जो कि बड़े दुख की बात है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सड़क की रिपेयर का काम करवाएंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सड़कों के बारे में चर्चा की है, जैसे कि माननीय सदस्य श्री पलाका जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैंने दिया था। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एक प्रश्न से सारे हरियाणा की सड़कों की जानकारी नहीं मिल सकती। इन्होंने जो सप्लीमैंट्री पूछी है इसके लिए सैपरेट सवाल पूछें हम उसका पूरा जवाब देंगे। मैंने पूरे आंकड़े दे कर यह बताया है कि पांच साल के अरसे में क्या हुआ। यह इनका कसूर नहीं है इनके नेता ने सड़कों और ब्रिजिज बनवाने पर कभी फोकस ही नहीं किया। आंकड़े यह कहते हैं कि 1744 लाख रुपये इन्होंने खर्च किये थे जब कि 1422 लाख रुपये हम खर्च कर चुके हैं और 700 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किया है। माननीय सदस्य अपने हल्के की किसी व्यक्तिगत समस्या के लिए लिख कर देने के लिए स्वतन्त्र हैं, वे माननीय मुख्य मन्त्री जी को अपनी समस्या लिख कर भेजें। ये आपके नेता की सरह नहीं हैं पूरी सदभावना और अच्छे तरीके से जांच करवा कर उसका हल निकलवाएंगे।

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी यहां पर बिखेड़ी के नाम से एक सड़क जानी जाती है। पिछले सदन में मैंने मुख्यमंत्री जी से इसको ठीक करने के बारे में रिक्वैस्ट की थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं इसको बनवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, उस रोड पर क्रैशर लगे हुए हैं और वहां पर बड़ी-बड़ी गाड़ियां हजारों की संख्या में चलती हैं जिसकी वजह से कार, स्कूटर, मोटर साईकल इत्यादि छोटी गाड़ियां तो वहां से गुजर ही नहीं सकती हैं। मंत्री जी यह बताएं कि उस सड़क की रिपेयर कब तक करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में लिखकर भिजवा दें।

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस सड़क को हमने बी०ओ०टी० के आधार पर टेकअप कर लिया है।

चौ० अर्जन सिंह : धन्यवाद जी।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी हांसी और तोशाम की सड़क के बारे में प्रश्न पूछा था लेकिन अभी तक उस सड़क का कुछ नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर हजमपुर से तोशाम के बीच में सड़क की बहुत ही बुरी हालत है। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन भी दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है। ये इस बारे में लिखकर दे दें, मैं इस बारे में इनको जानकारी दे दूंगा ।

Wind up of Sugar Mills in Haryana

***687. Shri Dharmapal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) wether there is any proposal under consideration of the Government to wind up any Co-operative Sugar Mill in Haryana due to financial losses or short supply of sugarcane ; and

(b) if so, what steps are being taken to save the interest of the employees and farmers ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Co-operative Sugar Mills Bhuna and Sirsa are under winding up/Liquidation Process.

(b) Following steps are being taken to save the interests of the employees and farmers :—

Employees

(i) Co-operative Sugar Mills Bhuna has been sold to a private enterpreneur with the condition that the buyer of the mills will retain entire staff (permanent as well as seasonal) as it is.

(ii) Permanent staff of the Sirsa Sugar Mills has been/is being adjusted in other Coop. Sugar Mills/Institutions, whereas the seasonal staff has been paid off.

Farmers

(i) The Co-operative Sugar Mills Bhuna has been sold to a private entrepreneur with the condition that buyer will run the Mills to purchase and crush the cane of the assigned area of the Mills at the cane price fixed by State Govt.

(ii) The area under sugarcane crop in Sirsa Mills zone is negligible. Therefore, the farmers of Sirsa area face no problem in the disposal of their crop.

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में एक भूना को-आप्रेटिव शूगर मिल और दूसरी सिरसा को-आप्रेटिव शूगर, मिल्य दो शूगर मिलों का जिक्र किया है जिनको लिक्विडेट किया जा रहा है और which have been transferred to some private parties. भूना शूगर मिल में जो परमानैंट और सीजनल इम्पलाई थे उनको रिटेन किया गया था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिरसा को-आप्रेटिव शूगर मिल का सवाल है, तो इस बारे में यह बात तो साफ हो गई है कि इसको बंद किया जा रहा है। लेकिन बंद करने के बाद इसमें जो मशीनरी है उसका क्या किया जाएगा, यह मशीनरी कहां पर जा रही है ? इसके साथ ही वहां पर जो इम्पलाईज हैं उनके बारे में यह सुना जा रहा है कि उनको पे-आफ किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 10 को-आप्रेटिव शूगर मिल्ज हैं और 3 प्राईवेट शूगर मिल्ज हैं। तीनों की तीनों प्राईवेट शूगर मिल्ज प्रोफिट में चल रही हैं। ऐसा क्या कारण है जो हरियाणा को-आप्रेटिव शूगर मिल्ज घाटे में चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : मलिक जी, नरायणगढ़ वाली जो प्राईवेट शूगर मिल है वह घाटे में चल रही है। वह प्रॉफिट में नहीं है।

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिपोर्ट के अनुसार तीनों प्राईवेट मिलें प्रोफिट में चल रही हैं। शूगर मिल्ज तब प्रोफिट में चलती हैं जब बारों महीने उसमें गन्ने की पिराई हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो को-आप्रेटिव शूगर मिल्ज हैं क्या उनमें चारों महीने गन्ने की पिराई चलती है। जो मिले घाटे में हैं उनके घाटे का कारण ही यही है कि वहां पर चारों महीने गन्ने की पिराई नहीं होती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से माननीय साथी जी ने दो प्रश्न किए हैं एक तो सिरसा मिल के स्टाफ के बारे में किया है। इस मिल में जो सैंक्शड स्टाफ था वह 422 था और इसमें से 288 कर्मचारी इन-पोजीशन में थे। 43 कर्मचारियों को दूसरे सैक्टर्ज को-आप्रेटिव शूगर मिल्ज में भेज दिया गया है। बाकी में से जो 95 परमानैंट इम्पलाईज थे उनको नहीं निकाला गया है जैसे कि जो लोग सामने बैठे हैं इन के समय में निकाला जाता था। जो दूसरी को-आप्रेटिव शूगर मिल्ज के कर्मचारी हैं उनको हमने इनमें एडजैस्ट कर लिया है और सीजनल

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

इम्प्लाथी जो 150 के करीब थे, उनको पेड ऑफ किया गया है। इस तरह से यह तो इनके पहले सवाल का जबाव था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न था वह यह था कि जिस तरह से पिछली मिल भूना के बारे में फैसला किया गया है तो सिरसा मिल के बारे में क्या करेंगे। सर, इनके दूसरे प्रश्न का जबाव यह है कि हमने जो न्यूज पेपर में इस बारे में बिड दी थीं उसमें यही शर्तें रखी गयी थीं कि आप इस शुगर मिल को चलाएंगे। परन्तु तीन टैंडर ही हमें रिसीव हुए हैं उनमें से दो टैंडर वाले तो केवल इस प्लांट और मशीनरी को खरीदना चाहते हैं जबकि एक टैंडर वाले लैंड को खरीदना चाहते हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति सिरसा की शूगर मिल को चलाने के लिए आगे नहीं आया है। स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि इस शूगर मिल को चलाने के लिए क्यों कोई आगे नहीं आया इसका कारण यह है कि इस बारे में कहीं न कहीं यह बात छिपी है कि जैसे वर्ष 2004-05 में इस शुगर मिल के अंडर आने वाली मात्र 130 एकड़ जमीन में ही गन्ना लगाया गया, 2005-06 में यह फिगर निल हैं और 2006-07 में भी यह फिगर निल हैं जबकि वर्ष 2003-04 के अंदर भी अगर हम देखें तो 1680 एकड़ जमीन में ही वहां पर गन्ना लगाया गया था। स्पीकर सर, जो हमारे इस बारे में नोर्म्ज हैं उनके मुताबिक किसी भी शुगर मिल को रीजनेबली वायबल होने के लिए 1750 टन कैपेसिटी क्रशिंग गन्ने की प्रतिदिन की होनी चाहिए यानि एक सीजन में 27 लाख क्विंटल गन्ना अगर कोई शुगर मिल में पीड़े तो वह शुगर मिल वायबिलिटी के नजदीक आ जाती है या वह स्कीम वायबल हो जाती है। स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि वहां पर 2003-04 में टोटल गन्ना 1680 एकड़ में लगा, 2004-05 में 130 एकड़ में लगा जबकि उसके बाद के वर्षों में वहां पर गन्ना लगा ही नहीं इसलिए शायद इस शुगर मिल को चलाने के लिए कोई भी प्राईवेट पार्टी सामने नहीं आ रही है।

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने जो जबाव दिया है उसके मुताबिक जिस दिन यह शुगर मिल इन्स्टाल हुई उस दिन भी यह वायबल यूनिट नहीं थी। मैं जानना चाहूंगा कि who was at fault, कैसे रिपोर्ट दी और इससे सरकार को कितना घाटा हुआ ? इसके अलावा जो शेयर होल्डर्ज को-आप्रेटिव सोसायटी में थे उनको कितना घाटा हुआ ? क्या इस घाटे को शेयर होल्डर्ज के ऊपर डाला जाएगा या फिर सरकार कोई और इलाज करेगी? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि यह ठीक है कि अब यह यूनिट बंद हो गयी है क्योंकि वहां पर गन्ना नहीं है इसलिए क्या वह मिल अब चलेगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप इस बारे में सारी बातें जानते ही हैं।

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमने पढ़ा था कि सरकार की असंध में भी नयी शूगर मिल बनाने की योजना है क्या सिरसा की शुगर मिल की मशीनरी को असंध में बनने वाली शुगर मिल में अगर वह ठीक बैठती हो, ले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्होंने तीन प्रश्न पूछे हैं। इनका पहला प्रश्न यह है कि भूना तथा सिरसा की जो शूगर मिल हैं उनका क्या करेंगे और गैर जिम्मेवाराना तरीके से ऐसे इलाकों में जहां पर गन्ने की पैदावार नहीं थी, शूगर मिल लगाने के लिए कौन जिम्मेवार हैं। स्पीकर सर, जो जिम्मेवार हैं वह इस सदन से भाग गए हैं। जो जिम्मेवार हैं उनमें से हमारे कुछ साथी तो यहीं बैठे है। लोकदल की सरकार ने वहां चीनी मिल लगाने का निर्णय लिया था। हमने

सारा रिकार्ड देखा है सबसे रोचक बात यह है कि इन दोनों चीनी मिलों को न चलाने का फैसला भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ही लिया था क्योंकि जब चीनी मिल लगायी गयी वहां पर गन्ना था ही नहीं। उन्होंने लोगों का करोड़ों अरबों रुपयों का पैसा लगाकर पहले तो वह चीनी मिल वहां पर लगायी और फिर उस चीनी मिल को बंद करने का निर्णय भी उन्होंने खुद ही किया था। स्पीकर सर, भूना और सिरसा की शूगर मिल की जो फाईल है उसकी नोटिंग मेरे पास है। भूना और सिरसा दोनों शूगर मिल्ज का केस उनके सामने 9-11-2004 को पेश किया गया और तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री औम प्रकाश चौटाला ने भूना की मिल को बंद करने का निर्णय लिया। 6-11-2004 को जाते-जाते वे अपने इलाके की दोनों मिल्ज को बंद कर गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ही फाईल पर सिरसा की मिल को भी बंद करने का निर्णय लिया। माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि 2005-06 में भूना शूगर मिल का कितना नुक्सान हुआ तो मैं बताना चाहूंगा कि 197 लाख 70 हजार रुपये का नुकसान हो गया था और इसी प्रकार से सिरसा में भी चीनी मिल है उसका नुकसान 2005-06 तक बढ़कर 39 करोड़ 12 लाख 82 हजार रुपये हो गया था। तीसरा प्रश्न असंध की मिल के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को उसके बारे में बताना चाहूंगा कि यह मिल हैफेड लगाएगी और हमने इस बात के लिए बिड दिया है और यह विधार किया है कि सिरसा के प्लांट की मशीनरी पर विपक्ष के साथियों ने हरियाणा की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई का जो करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया उसको तो हम प्रयास करके बचा लें और उस मशीनरी को हम असंध की मिल में इस्तेमाल कर लें। इसका प्रावधान करने का हमने प्रयास किया है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कोई सरकार या उस सरकार के मुखिया अगर ऐसा कोई निर्णय ले जो उसकी जानकारी में हो कि उससे सरकार और जनता के पैसे का बहुत नुकसान होगा लेकिन फिर भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वह निर्णय लेता है। जैसे भूना की शूगर मिल की घोषणा 2000 के चुनावों के समय में की गई थी और इन दो इलाकों के वोट बटोरने के लिए यह घोषणा की गई थी। बाद में खुद ही उसे बंद कर दिया। उस वक्त उनको यह पता भी था कि यह वायबल नहीं है। रिकार्ड भी यही है और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की रिपोर्ट भी यही है कि यहां पर इस एरिया में शूगर केन नहीं होता इसलिए उस एरिया में यह मिल कामयाब नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी ऐसा करके सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान डैलीबरेटली किया गया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सारे पैसे की रिकवरी उनकी जायदाद से करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उनकी कद्र करता हूं। जब हम इस सदन के अंदर चुनकर आते हैं और सत्ता में बैठते हैं तो हमें इस जिम्मेदारी के बारे में भी सोचना होगा कि जो पैसा हम खर्च करते हैं या जो करोड़ों रुपये की इन्वैस्टमैंट हम करते हैं वह यह सोचकर खर्च करना चाहिए कि वह आखिरी पंक्ति में खड़े गरीब आदमी का पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग कैसे हो, साधारण आदमी को लाभ कैसे पहुंचे ? इस बात की पारदर्शिता दिखनी चाहिए। कुछ न कुछ अपने अंतरमन में उन सभी व्यक्तियों को जो कि सत्तासीन रहे हैं, झांक लेना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक तो उनको यही सजा मिली है कि लोगों ने उनको नकार दिया। जनता की अदालत ने भी उनको सजा दी है और कानून भी उनको अवश्य सजा देगा।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब देते समय मंत्री जी ने बताया कि भूना मिल के सारे इम्प्लौयीज को ऐडजस्ट कर दिया गया है buyers as well as permanent. लेकिन मेरी इन्फर्मेशन के अनुसार उनको एक साल के लिए रखा और फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। 20-25 आदमी मेरे पास आए थे उनमें से 5-6 आदमी मेरे हल्के के थे। अब वे भटक रहे हैं। जब से वह मिल लगी थी तब से वे उसमें लगे हुए थे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूना का प्रश्न है, उसमें 688 कर्मचारी थे जो प्राइवेट बायर हो गए। बाकी सभी कर्मचारियों ने ज्वायन कर लिया है सिर्फ 120 कर्मचारी हैं जो इनके पास आए होंगे जिन्होंने हाईकोर्ट में रिट पैटीशन दायर की है जो प्राइवेट बायर के पास काम न करके को-आप्रेटिव शूगर मिल में नौकरी लगना चाहते हैं, यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो कर्मचारी नौकरी ज्वायन करने के लिए आप्शन देना चाहते हैं उनको अगर प्राईवेट मिल वाले नौकरी पर नहीं रख रहे हैं तो उनको सरकार ऐडजस्ट करवायेगी। जो कर्मचारी कोर्ट में चले गये हैं उनका तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता लगेगा कि ऐडजस्ट करना है या नहीं ?

Setting up of 33 K.V. Sub-station

***697. Prof. Chhattar Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any proposal is under consideration of the Government to set-up 33 K.V. sub-station in Pabra and Kharar Alipur Village of Hisar Distt; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No, Sir.

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन दोनों गांवों की बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी ली है ? क्या मंत्री जी बता पायेंगे कि यहां पर बिजली की व्यवस्था करने की सरकार आवश्यकता महसूस नहीं करती या कुछ डिले हुई है। मेरी जानकारी में जहां तक बात है, विभाग को इस बारे में प्रोपोजल बनाकर भेजी जा चुकी है और एस०ई०लेवल तक मामला पहुंच चुका है। क्योंकि खरड़ अलीपुर और पाबड़ा दोनों बड़े गांव हैं और बिजली के कारण परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रो० साहब, आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा स्पेसिफिक क्वैश्चन यह है कि इन दोनों विलेजिज में बिजली की हालत बुरी है। वहां पर 33 के०वी०ए० का ट्रांसफारमर लगाने के लिए मामला प्रोसैस में है, क्या वहां पर 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन बनाने के लिए मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि पाबड़ा और खरड़ अलीपुर दोनों बड़े गांव है। पांवड़ा गांव को 33 के०वी०ए के सब-स्टेशन बरवाला से बिजली फीड की जा रही है। वहां पर इन्सटाल कैपेसिटी 16 एम०वी०ए० है जबकि वहां पर जो टोटल बिजली की रिक्वायरमेंट है वह 15.2 एम०वी०ए० हो रही है। मैं माननीय सदस्य की

जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरसौद गांव में 11 के०वी०ए० की एक नई फीडर लाईन सरकार जोड़ने जा रही है उसके कार्य को पूरा होने में करीबन 3 महीने लग जायेंगे। इसके चलने से पावड़ा की बिजली की व्यवस्था काफी इम्प्रूव हो जायेगी। इसलिए पावड़ा में नया सब-स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इसके इलावा चैनल ढूंढ रहे हैं। खरड़ अलीपुर गांव को भाटला से जो 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन है वहां से बिजली प्रदान की जा रही है। जिसकी टोटल इन्सटाल कैपेसिटी 12 एम०वी०ए० की है और वहां पर जो बिजली की रिक्वायरमैंट है वह 10.12 एम०वी०ए० की है। यह सदन जानता है कि बिजली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार समय समय पर इस बारे में ऐनालिसिस करती रहती है और जहां पर सब-स्टेशन को अपग्रेड करने की जरूरत होती है या ऑगमैंटेशन की जरूरत होती है वहां पर सरकार अवश्य कार्यवाही करती है।

प्रो० छतरपाल सिंह : थैंक यू, स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरसौद से पावड़ा गांव के लिए एक नई फीडर लाईन निकली जा रही है। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस लाईन का काम पिछले 3-4 साल से पैंडिंग है। एक लाईन को सरसौद से पावड़ा तक जोड़ने में इतना समय क्यों लगा है ? क्या हमारे विभाग के लोगों ने यह महसूस नहीं किया कि इस लाईन में इतना विलम्ब क्यों हुआ है। यह लाईन इतनी लम्बित क्यों हुई क्या विभाग ने इस बारे में कभी जानने की कोशिश की ? यदि किसी अधिकारी के पार्ट पर यह डिले हुई है तो क्या उसको दोषी ठहरा कर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और काम पूरा करवाएंगे ताकि हम अपनी वर्किंग को स्ट्रीमलाईन कर सकें ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक इन्होंने डिले के बारे में कहा है उसका तो पता करवा लेंगे अगले तीन महीने के अन्दर-अन्दर हम इस लाईन को अवश्य जोड़ देंगे जिसके कारण इनके गांवों की जो पावर की स्थिति है वह काफी सुधर जायेगी। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में दो 32 के०वी०ए० का एक सब-स्टेशन बहबलपुर और भाटला गांव में एक करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जिसकी ऑगमैंटेशन प्रोगैस में है। इस साल के अन्त तक उसको पूरा कर देंगे। दूसरा मार्च 2005 से मार्च, 2007 तक जिला हिसार में एक 33 के०वी०ए० के सब-स्टेशन कमीशन किया है उनमें चार तो ऐग्जिस्टिंग सब-स्टेशन हैं उनको हम अगमेंट कर रहे हैं जिससे 24 एम०वी०ए० की 10 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाईन के लिए 2.25 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।

Purchase of Medicines

***657. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Health be pleased to state:—

(a) the criteria adopted for purchase of medicines by Health Department; and

(b) the effect of the medicines purchase by Health Department as compared to the medicines of the Standard companies ?

स्वास्थ्य मन्त्री, (बहिन करतार देवी) : श्रीमान जी,

(क) विभाग दवाईयों की खरीद साल्ट नेम (जैनेरिक नाम) से उन फर्मों से करता है जो सरकार के रेट कन्ट्रेक्ट पर होती है। दवाईयों की खरीद निर्धारित आवश्यकता अनुसार की जाती है।

(ख) स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई दवाईयों का वही प्रभाव होता है जो कि मानक कम्पनियों की दवाईयों का होता है क्योंकि दोनों में एक जैसे तत्व होते है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि दवाईयों की खरीद निर्धारित पॉलीसी के हिसाब से उन्हीं फर्मों से करते हैं जो हमारे रेट कंट्रेक्ट पर होती हैं और उन दवाईयों का साल्ट जैनरिक होता है। विशेषज्ञों द्वारा ये दवाईयां जांच करके ही खरीदी जाती हैं और इन दवाईयों का वहीं प्रभाव होता है जो कि स्टैंडर्ड कम्पनियों की दवाईयों का होता है क्योंकि दोनों में एक जैसा साल्ट ही होता है। इस तरह जो दवाईयां हमारे विभाग की तरफ से खरीदी जाती हैं उनके साल्ट में कोई फर्क नहीं होता।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जवाब में कहा की वही साल्ट होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनग्रेडियंट्स सेम होना कोई क्राईटेरिया नहीं है कि उसकी अफीकेसी कितनी होगी। इसलिए मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई अफीकेशन टैस्ट है जिसके आधार पर यह कह सकें कि जो दवाईयां सरकार द्वारा खरीदी जाती हैं उनके और स्टैंडर्ड की कंपनियों की दवाईयों के रिजल्टस सेम हैं। दूसरा सवाल मैं यह करना चाहता हूं कि आज भी हमारे सरकारी हास्पिटल्ज हैं उनके अंदर डाक्टर्ज गरीब मरीजों को ऐसी दवाईयां लिखते हैं जो हास्पिटल में उपलब्ध नहीं होतीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह के प्रावधान करेगी कि जो दवाईयां मरीजों को दी जायें उनको ओ०पी०डी० रजिस्टर में इंटरी की जायेगी कि कितनी दवाईयां हास्पिटल से दी गई हैं और कितनी दवाईयां बाहर प्रिसक्राइब की गई हैं। क्योंकि डाक्टर्ज का बाहर कमीशन होता है इसलिए वे ज्यादातर दवाईयां बाहर से ही प्रिसक्राइब करते हैं। इस तरह से गरीब मरीजों को अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। क्या सरकार इस तरह की डाक्टर्ज की मनमानी पर रोक लगाने पर विचार करेगी ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर अपनी तरफ से सीधी कोई भी दवाई नहीं खरीदते। अप्रैल के महीने में डी०जी० एच०एस० की अध्यक्षता में मीटिंग होती है जिसमें सभी सिविल सर्जन और प्रोग्राम आफिसरज भाग लेते हैं। वे बताते हैं कि उनके यहां किन-किन दवाईयों की आवश्यकता है। जो आवश्यकता होती है उन दवाईयों को लिखकर डायरैक्टर सप्लाईज एंड डिस्पोजल को भेजा जाता है। वे टैण्डर काल करते हैं और जिन फर्मज का लोवैस्ट टैण्डर होता है उन फर्मज के साथ नैगोसियेशन करके उन्हीं के साथ रेट कंट्रैक्ट फिक्स किया जाता है तथा उन्हीं से सारी दवाईयां खरीदी जाती हैं। उसके बाद ऐसा भी नहीं है। कि दवाईयां आ गई और उनकी देखभाल नहीं होती। उसके बाद भी जो हमारे ड्रग इन्सपैक्टर उनकी सैम्पलिंग करते हैं अगर मेजर कोई डिफैक्ट पाया जाता है तो पूरा लौट उनको वापिस किया जाता है और उनके ऊपर मुकदमें चलाये जाते हैं और यदि माईनर कोई डिफैक्ट है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाती है। एक बात माननीय सदस्य ने और पूछी है शुरू-शुरू में तो कुछ शिकायतें आई थीं कि मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखते हैं लेकिन अब ऐसी कोई

बात नहीं है। मैं एक बात माननीय सदस्य के ध्यान में और भी लाना चाहूंगी यह पॉलिसी 2004 की बनी हुई है। हमने तो यही सोचा था कि यह मरीजों के हित में है क्योंकि जैनरिक दवाईयां उनसे 1/3 रेट पर मिल जाती हैं और उनका फायदा भी मरीजों को उतना ही होता है जो स्टैंडर्ड दवाईयों का होता है। उस वक्त कोई कंडीशन भी नहीं थी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्वालिटी अच्छी हो हमने उनके ऊपर एक तो बढ़िया काम करने के सर्टिफिकेट की कंडीशन लगाई है और यह भी कंडीशन है कि 3 साल के अन्दर उनका टर्न ओवर 5 करोड़ रुपये के करीब होना चाहिए ताकि हमें यह लगे कि यह फर्म किसी ने बोगस लगाकर नहीं रखी है बल्कि पहले से कार्यरत है और उनकी दवाईयां ठीक पाई जायेंगी। उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया है कि जो ड्रग इन्सपैक्टर, ड्रग कंट्रोलर हैं बराबर इस बात की सैंप्लिंग करते रहते हैं कि कहीं कोई दवाई सब-स्टैंडर्ड न हो। इसलिए अब इस प्रकार की शिकायतें बहुत कम ही मिलती हैं एक आध बार तो यह हो जाता है कि कोई डॉक्टर अपने किसी जानकार आदमी को यह कह दे कि ये साधारण दवाईयां हैं और कम काम करती हैं इसलिए कोई बढ़िया दवाई लिखवा लो।

श्री आनन्द सिंह दांगी : बहन जी, कोई विदेशी दवाई इनके लिए जरूर मंगवा दो।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक ऐसी बात करेंगे तो उसकी दोबारा जांच करवा लेंगे और जो कोई ऐसा अपराध करते हैं, अपराध के हिसाब से उनको सजा जरूर मिलेगी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या पी०एच०सी०, सी०एच०सी० या जनरल हॉस्पीटल के लैवल पर कुत्ते के काटने की दवा, साँप के काटने की दवा या हैपेटाईटिस बी०के० इंजैक्शन अवेलेबल होते हैं क्योंकि आसपास के मैडिकल स्टोर पर भी इस तरह की दवाई की अवेलेबिलिटी नहीं होती हैं। क्या हमारी सरकार इसके बारे में कोई प्रावधान कर रही है ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर तो इन दवाईयों की एवेलैबिलटी होती है लेकिन इस बात के फैक्टस अगर माननीय सदस्या को चाहिएं तो वो बाद में मेरे से मिल लें डिपार्टमैंट से पता करवा कर बता दूंगी या सैपरेट प्रश्न पूछ लें तो उसकी जानकारी दे दी जायेगी।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह सुनिश्चित करेंगी कि ओ०पी०डी० में कितने मरीजों को दवाई हॉस्पीटल से दी जाती है और कितने मरीजों को बाहर से लिखी जाती है ?

Mr. Speaker : It is very difficult to give the answer.

डॉ० सीता राम : इसके बारे में कोई नॉर्म्स होना चाहिए कि कितने लोगों को हॉस्पीटल से दवाई दी गई है क्योंकि डॉक्टर बाहर की दवाईयाँ लिखते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आप सैप्रेट प्रश्न पूछिये।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि शुरू में कुछ शिकायत आती थी लेकिन हम बराबर सिविल सर्जन की मीटिंग लेते हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले गरीब आदमी को हॉस्पीटल से दवाईयाँ मिलें। फिर भी अगर किसी हॉस्पीटल की शिकायत इनके नोटिस में हो तो ये लिख कर दे दें उसकी जाँच हम करवा लेंगे।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दवा निर्माता कम्पनियों के द्वारा जो सैम्पल डॉक्टरों को हॉस्पीटल में दिये जाते हैं वो लाखों रुपये की दवाई होती है, क्या कोई ऐसा प्रावधान सरकार करेगी कि वो दवाईयाँ गरीब लोगों को दी जायें ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, जो डॉक्टरज़ सैम्पलज होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि not for sale कोई जानकार मरीज तो वैसे ही नहीं लेगा और जो अच्छा डॉक्टर है वो भी फ्री देने की कोशिश करेगा। मैं माननीय सदस्य को पहले ही कह चुकी हैं कि कोई खास शिकायत उनके नोटिस में हो तो वो लिख कर दें दे। हम उसकी जाँच करवा लेंगे। सैम्पल ऐसे नहीं दिये जाते हैं। इमरजैंसी तथा एक्सीडैंट केसिज में सिविल सर्जन को पावर हमने दी हुई है कि वो इम्मीडियेट दवाई खरीद सकते हैं लेकिन उन्हीं फर्मों से जो रेट कंट्रैक्ट पर हैं।

Repair of Bridges on Canal

***680. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the bridges on canal passing through the Bhatol Jatan to Thurana and from Sulchani to Kagser roads in Narnaund Constituency ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : हां, श्रीमान जी।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि यह पुल दो साल पहले टूट गये थे और वहां पर हर वक्त हादसा होने का अन्देशा बना रहता है। यहां पर कई हादसे हो चुके हैं कभी कोई भैंस यहां पर गिर गई और कभी कोई गाड़ी यहां पर पलट गई। अभी तक इन पुलों का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका काम शुरू होने में कितना समय और लगेगा। स्पीकर सर, मुण्ढाल और बास के बीच में एक पुल है जिसको टूटे हुए छः साल हो गए हैं। (विघ्न) मैं सोचता हूं कि सरकार के नॉलेज में इसके बारे में ला दूं। यहां पर लोहे का एक पुल किराये पर ले रखा हुआ है छः साल इसको टूटे हुए हो गए हैं लेकिन इसका थोड़ा सा काम भी नहीं किया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कारगुजारी कर रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । लोहे का पुल मुण्ढाल से बास जाएं तो उस रास्ते पर यह पुल बन रहा है और अभी वहां पर लोहे का पुल लगा हुआ है लेकिन दूसरा पुल बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है और काम बीच में ही रुक जाता है। दूसरे जो दो पुल हैं वहां पर बहुत खतरा बना रहता है लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पुल को कब तक बनवा देंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा हैं मैं इनकी जानकारी के लिए इनको बताना चाहता हूं कि सुल्चानी कासर जो रोड है यह मैटल रोड कन्वर्ट हो गई थी और इसमें जो पेटवाड़ डिस्ट्रिब्यूटरी है उस पर इसकी विड्थ 9.5 फुट है और न्यू सिवानी पर यह विडथ 14 फुट है लेकिन जब यह सड़क बनी थी इसके साथ थुराना, भटोल जाटान में भी दोनों सड़कें मार्कीटिंग बोर्ड ने बनवाई थी, जब मैटल रोड कन्वर्ट हुई थी उन्होंने उस वक्त यह पुल

नहीं बनाया था। मैं इनकी जानकारी के लिए इनको बताना चाहूंगा कि जो माईनर रिपेयर हैं उनको हम दो महीने में पूरा कर देंगे लेकिन साथ ही साथ सुल्वानी कासर रोड़ और थुराना भाटोल रोड के पुल का रिप्लेसमैंट करेंगे और अगले छः महीने में 20 लाख रुपये की लागत से एक पुल बनेगा और 40 लाख रुपये इस पर खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, अगले छः महीने में इनके दोनों पुल तैयार कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सारी दिक्कत इसलिए आई कि यह जो हमारे सामने साथी बैठे हुए हैं अकल दल वाले, उन्होंने कभी भी पिछले पांच साल में कोई पुलिया तक रिपेयर नहीं की। स्पीकर सर, अब हालत यह है कि प्रदेश में करीबन 2 हजार ब्रिजिज ऐसे हैं जिनकी मुरम्मत की जरूरत है और पुलों की मुरम्मत पर अढ़ाई करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने बी० एण्ड आर० को यह काम दे दिया था और उनके पास काम ज्यादा था इसलिए यह काम नहीं हो पाया । इस सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि नैशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज पर पुलों की रिपेयर बी० एण्ड आर० करेगी और बाकी की जो रोड़ज हैं उन पर पुलों की रिपेयर इरिगेशन डिपार्टमैंट करेगा जिससे स्थिति बहुत ही जल्दी सुधर जाएगी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि निर्जापुर बासोद में एक पुल बनना था जिसका प्रस्ताव भी हो गया था इसके साथ ही धाबड़ा, अटेली, नीरपुर मीलवाड़ हैं जिनका प्रस्ताव पास हो गया था पिछले करीब एक साल से इसकी फाईल घूम रही है। इस पुल के न बनने के कारण चार किलो मीटर का चक्कर काट कर लोगों को खेतों में से होकर जाना पड़ता है। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर पुल कब तक बन जाएगा जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा न हो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सैपरेट सवाल दें इनको जवाब दे देंगे।

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पुल पिछले काफी अरसे से टूटे पड़े हैं जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, आप लिख कर भिजवा दीजिए। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि ये मुझ से पर्सनल मिल कर बता दें जितना भी सम्भव हो सकेगा कोशिश करके इनके पुलों को बनवा देंगे। (विघ्न)

Extend of limits of Municipal Committee in Haryana

***688. Ch. Dharampal Singh Malik :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to extend the limits of Municipal Committees in Haryana ; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to be implemented ?

शहरी विकास राज्य मंत्री, (श्रीमती सावित्री जिंदल) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) ये प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। जैसे ही, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 4 तथा 6 में निहित व्यवस्था अनुसार सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी त्यों ही सम्बन्धित नगरपालिका की सीमावृद्धि बारे अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से पूछना चाहूंगा कि जो प्रपोजल म्यूनिसिपल कमेटी की सीमा की एक्सटैंशन के लिए आती है उसको किस आधार पर एक्सटैंड किया जाता है, इसका क्या क्राईटेरिया है अथवा नगर पालिका जो प्रपोजल भेजती है उसी के आधार पर सीमा बढ़ाई जाती है ?

श्रीमती सावित्री जिंदल : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका की सीमावृद्धि करने की प्रणाली निम्न प्रकार से है :--

1. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति में जो वह अब अवधारित करे, किसी नगरपालिका-क्षेत्र के भीतर उसके पड़ोस में स्थित तथा अधिसूचना में परिनिश्चित किसी स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकती है।

2. किसी ऐसे नगरपालिका क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र का, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है, कोई निवासी, यदि वह परिस्थापित परिवर्तन के प्रति आक्षेप करना चाहे, तो अधिसूचना के प्रकाशन से छह सप्ताह के भीतर, लिखित रूप में अपना आक्षेप उपायुक्त के मार्फत् से राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है और राज्य सरकार ऐसे आक्षेप पर विचार करेगी।

3. जब अधिसूचना के प्रकाशन से छह सप्ताह हो गए हों और राज्य सरकार ने आक्षेपों पर, यदि कोई हों, जो उपधारा (2) के अधीन उसे प्रस्तुत किए गए हों, विचार कर लिया हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना उसे प्रस्तुत किए गए हों, विचार कर लिया हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका-क्षेत्र में सम्मिलित कर सकती है।

4. जब उपधारा (3) के अधीन कोई स्थानीय क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, तब यह अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा, अधिसूधना द्वारा, अन्यथा यथानिर्दिष्ट किए जाने के सिवाय, सभी अधिसूचनाएं, नियम, उपविधियां, आदेश, निदेश तथा शक्तियां, जो इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, बनाए गए, बनाई गई, किए गए या प्रदत्त की गई हों और उस समय सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में प्रवृत्त हों, ऐसे क्षेत्र में लागू होंगी।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी जी ने पूछा है कि जो विधान सभा क्षेत्र है उसके एरिए की एक्सटैंशन के बारे में जो प्रस्ताव है उसका क्या होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी जी को और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गोहाना नगरपालिका का प्रस्ताव आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अनुमोदन कर दिया है और जल्दी ही गोहाना की नगरपालिका की लिमिट बढ़ा दी जाएगी।

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि गोहाना की नगरपालिका की लिमिट बढ़ा दी जाएगी लेकिन मेरा प्रश्न सारी स्टेट के बारे में है। हमारी स्टेट में जो गैर कानूनी कालोनीज़ की ग्रोथ हो रही है और जब उनको गिराया जाता है तो हाहाकार मचाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के समय में इस तरह की गैर कानूनी कालोनिज़ डिवैल्प होती हैं क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, आफिसर्ज की मिली भगत के बिना गैर कानूनी कालोनिज़ बन ही नहीं सकती हैं। गोहाना तो देहात का एरिया है और उसका एरिया बढ़ जाएगा यह अच्छी बात है लेकिन यह जो गैर कानूनी तौर पर कॉलोनीज़ जिन अधिकारियों के समय में डिवैल्प होती हैं उस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वैसे तो प्रश्न का जवाब दे दिया है और जो प्रश्न मलिक साहब पूछ रहे हैं वह पृथक प्रश्न का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ़ से और आपकी अनुमति से मलिक साहब को यह बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई इन्सटांस जहां जहां हमारे नोटिस में आता है कि जो इललीगल कालोनाईजेशन है वह किसी अधिकारी की मिलीभगत से हुआ है तो सरकार उस बारे में कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है। अगर माननीय मलिक साहब के यहां पर कोई भी ऐसा इन्सटांस हो तो वे माननीय मंत्री जी को उस बारे में लिखकर भेजें। माननीय मंत्री जी उस बारे में मुख्यमंत्री जी को लिखकर भेजें, हम उस पर अवश्य कार्यवाही करवाएंगे। जहां तक एक्सटैंशन आफ म्यूनिसिप्ल कारपोरेशन का प्रश्न है, हरियाणा में म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कौंसिल, म्यूनिसिपल कारपोरेशन चुनी हुई बॉडीज़ है, They are elected body sir. यह उनके उपर निर्भर है कि चुनी हुई जो बॉडी है वह अपनी लिमिट को बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लेती है। सरकार ने बार-बार यह कहा है कि जहां-जहां हमें इललीगल कॉलोनाइजेशन मिलेगी हम उस पर रोक लगाएंगे। चाहे छोटे शहर में हो या बड़े शहर में अगर किसी को कोई सुविधा कालोनी बनानी है तो उसके लिए बाकायदा नियम हैं वह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट को ऐप्लाई करें, हमारे नोर्म्ज को पूरा करें तथा उसके लिए निर्धारित फीस दें। 25 एकड़ के करीब छोटे शहरों में इस बारे में नोर्म्ज हैं इसलिए पहले वह इन नोर्म्ज को पूरा करें, एप्लाई करें। अगर वह ऐसा करता है तो हम जरूर उसको फवरेबली कंसीडर करेंगे।

Special Admission facilities to Poor Students in HUDA Sectors

***698. Prof. Chhatter Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the students belonging to the poor families are not being provided special admission facilities in private schools in HUDA Sectors; and

(b) if so, the steps taken by the Government in this regard ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No. Sir.

(b) Question does not arise.

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा सवाल यह था कि हुडा सैक्टर्ज में बने हुए प्राईवेट स्कूलों के अंदर गरीब बच्चों को दाखिला ठीक से मिलता है या नहीं अगर नहीं तो क्या इस बारे में कोई शिकायत सरकार के पास आयी है ? सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन प्राईवेट स्कूलों के अंदर कितने परसैंट गरीब बच्चों को ऐडमिशन लेने की सुविधा है और हुडा सैक्टर्ज में प्राईवेट स्कूलों के अलावा जो दूसरे प्राईवेट स्कूल्ज हैं, जिनको खोलने की परमिशन सरकार ने दी है, क्या उनमें भी यह सुविधा है या नहीं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने उन सारी साईटस, जो हुडा ने अलौट की हैं, उनमें दो तरह का आरक्षण दे रखा है। कुल सीट्स का दस प्रतिशत आरक्षण इकोनोमिकली वीकर सैक्शनज़ के बच्चों के लिए हैं। इसके अलावा दस प्रतिशत आरक्षण मीन्ज एंड मैरिट के आधार पर रखा हुआ है। परिवार के मीन्ज क्या हैं छात्र और छात्रओं की गुणवत्ता क्या है उसके आधार पर ही दस प्रतिशत सीटों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से जो संस्थाएं हुडा सैक्टर्ज में स्कूल साईट्स के लिए अप्लाई करती हैं वह 20 प्रतिशत का आरक्षण मानने के लिए बाध्य हैं। यह टर्म्ज एंड कंडीशन्ज़ का हिस्सा है। स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से इनको बताना चाहूंगा कि कुल 1 लाख 20 हजार बच्चों में से 16187 के करीब छात्र इस आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं। यह ठीक है कि जहां जहां पर इस तरह की समस्याएं आयी हों या शिकायतें आयी हों, उन सबको एक जबाव के अंदर इकट्ठा करना शायद संभव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य के नोटिस में अगर किसी स्पैसिफिक स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत है तो वह हमें बताएं, शिक्षा विभाग उस पर कार्यवाही करेगा, हुडा उस पर कार्यवाही करेगा।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, मंत्री जी मेरे दूसरे सवाल का उत्तर देना छोड़ गए हैं कि हुडा सैक्टर्ज में जो प्राईवेट स्कूल्ज हैं उनके अलावा जो प्राईवेट स्कूल्ज हैं उनमें यह आरक्षण की सुविधा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर साहब, आपका प्रश्न तो हुडा सैक्टर में जो स्कूल्ज़ हैं उनके बारे में था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्होंने केवल हुडा के सैक्टर्ज में जो प्राईवेट स्कूल्ज़ हैं उनके बारे में ही प्रश्न पूछा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो हुडा सैक्टर्ज के प्राईवेट स्कूल्ज़ के अलावा बाकी जो प्राईवेट स्कूल्ज हैं उनमें आरक्षण नीति क्या है वह बता दें। स्पीकर सर, मैं इनको बताना चाहूंगा कि हुडा की तो उनके लिए ही नीति है जिनको हुडा ने इस तरह के स्कूल्ज खोलने के लिए जमीन दी है बाकी स्कूलों के बारे में क्या नीति है वह शिक्षा मंत्री जी बताएंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की ऐफीलिएशन कई जगहों से होती है। एक तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हरियाणा का है, इससे ऐफीलिएशन होती है, दूसरा सैंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो केन्द्र सरकार का है, से भी ऐफीलिएशन होती है और तीसरा जो इंडियन काउंसिल ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन है, उसकी तरफ

से भी ऐफिलिएशन होती है। जो स्कूल्ज हमारे एजुकेशन बोर्ड से ऐफीलिएटेड हैं उनमें तो हम पूरा प्रावधान करते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा जब दाखिला लेने के लिए जाए और यदि उसके मार्क्स अच्छे हों तो उसको दाखिला लेने में कोई दिक्कत न हो। जहां तक सी०बी०एस०ई० की बात है, यदि वहां से इस बारे में कोई शिकायत आती है तो उसकी भी हम पूर्णत: जांच करवाते हैं जो सी०बी०एस०ई० से ऐफीलिएटेड स्कूल होते हैं वे यह मापदंड तय करते हैं कि हम मैरिट के आधार पर ही दाखिला देंगे। लेकिन यदि उनकी भी हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसका भी निराकरण करवा देंगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Steps taken to clean Yamuna

***622. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to initiate any action to clean Yamuna running through Faridabad Distt., if so, the details of steps taken in this regard ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान्। जिला फरीदाबाद में बादशाहपुर, प्रसोपगढ़ तथा मुझेरी गांवों में यमुना कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत स्थापित मल शोधक संयत्रों को अपग्रेड करने की कार्यवाही की जा रही है। इन संयंत्रों को अपग्रेड करने के लिए मास्टर प्लान, औचित्यता रिपार्ट एवं विस्तृत परियोजना लोक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति एवं सैनीटेशन विभाग हरियाणा द्वारा यमुना कार्य योजना-II में तैयारी के अन्तर्गत है। उनके द्वारा अपग्रेड करने का कार्य यमुना कार्य योजना III में शुरू किया जाएगा। अपग्रेड होने पर इससे जिला फरीदाबाद में नदी यमुना में पानी की गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

Construction of Malls

***628. Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state, the details of malls proposed to be constructed upto December, 2006 in the state along with the names of the cities in which these Malls are to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान जी, विवरण विधान सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

हरियाणा राज्य में 31 दिसम्बर 2006 तक अनुमोदित वाणिज्यक कम्पलैक्स की विवरणी

क्र० सं०	परियोजना का नाम गुड़गांव	क्षेत्र एकड़ में
1	2	3
1.	डी०एल०एफ० फेस-1	2.274
2.	डी०एल०एफ० फेस-1	2.110
3.	डी०एल०एफ० फेस-1	4.040
4.	डी०एल०एफ० फेस-1	3.200
5.	डी०एल०एफ० फेस-2	5.780
6.	डी०एल०एफ० फेस-2	1.950
7.	डी०एल०एफ० फेस-2	1.161
8.	डी०एल०एफ० फेस-2	0.270
9.	डी०एल०एफ० फेस-3	3.650
10.	डी०एल०एफ० फेस-3	33.090
11.	डी०एल०एफ० फेस-3	1.152
12.	डी०एल०एफ० फेस-3	0.328
13.	डी०एल०एफ० फेस-3	0.200
14.	डी०एल०एफ० फेस-4	3.773
15.	डी०एल०एफ० फेस-4	1.083
16.	डी०एल०एफ० फेस-4	2.302
17.	डी०एल०एफ० फेस-4	0.486
18.	डी०एल०एफ० फेस-5	2.650
19.	साउथ सिटी-1	4.995
20.	साउथ सिटी-1	0.680
21.	साउथ सिटी-1	2.695
22.	साउथ सिटी-1	0.470
23.	साउथ सिटी-1	0.440
24.	साउथ सिटी-2 फेस-1	0.603
25.	साउथ सिटी-2 फेस-1	5.990
26.	साउथ सिटी-2 फेस-1	0.570

1	2	3
27.	साउथ सिटी-2 फेस-1	0.647
28.	साउथ सिटी-2 फेस-2	6.081
29.	साउथ सिटी-2 फेस-2	2.809
30.	ग्रीनवुडस सिटी	3.398
31.	ग्रीनवुडस सिटी	0.680
32.	ग्रीनवुडस सिटी	0.946
33.	उप्पल हाउसिंग	2.629
34.	उप्पल हाउसिंग	0.876
35.	उप्पल हाउसिंग	1.056
36.	उप्पल हाउसिंग	0.256
37.	शीतल एनक्लेव	1.000
38.	शीतल एनक्लेव	1.143
39.	शीतल एनक्लेव	7.835
40.	शीतल एनक्लेव	2.162
41.	विपुल वर्ल्ड	1.000
42.	विपुल वर्ल्ड	1.000
43.	विपुल वर्ल्ड	3.750
44.	सन सिटी	3.000
45.	सन सिटी	0.580
46.	सन सिटी	0.860
47.	रोजवुड सिटी	3.380
48.	रोजवुड सिटी	0.690
49.	मालिबू इस्टेट	2.345
50.	मालिबू इस्टेट	3.465
51.	मालिबू इस्टेट	0.900
52.	पालम विहार	0.452
53.	पालम विहार	2.600
54.	पालम विहार	1.200
55.	पालम विहार	1.980
56.	पालम विहार	0.170
57.	पालम विहार	0.188

1	2	3
58.	पालम विहार	0.707
59.	पालम विहार	4.867
60.	पालम विहार	1.391
61.	पालम विहार	0.570
62.	पालम विहार	0.650
63.	पालम विहार	0.350
64.	पालम विहार	0.337
65.	पालम विहार	4.000
66.	पालम विहार	0.480
67.	सुशांत लोक-1	2.078
68.	सुशांत लोक-1	1.470
69.	सुशांत लोक-1	0.810
70.	सुशांत लोक-1	0.460
71.	सुशांत लोक-1	2.762
72.	सुशांत लोक-1	7.200
73.	सुशांत लोक-1	0.316
74.	सुशांत लोक-1	3.090
75.	सुशांत लोक-1	1.490
76.	सुशांत लोक-1	0.208
77.	सुशांत लोक-1	1.820
78.	सुशांत लोक-2	0.400
79.	सुशांत लोक-2	1.110
80.	सुशांत लोक-2	0.293
81.	सुशांत लोक-2	0.647
82.	सुशांत लोक-2	0.949
83.	सुशांत लोक-2	0.860
84.	सुशांत लोक-2	0.211
85.	सुशांत लोक-2	0.125
86.	सुशांत लोक-3	0.310
87.	सुशांत लोक-3	0.593
88.	सुशांत लोक-3	0.555

1	2	3
89.	सुशांत लोक-3	3.300
90.	सुशांत लोक-3	0.464
91.	सुशांत लोक-3	1.460
92.	आर०डी० सिटी	1.650
93.	आर०डी० सिटी	5.100
94.	ग्रीन लाईन	2.410
95.	ग्रीन लाईन	1.200
96.	ग्रीन लाईन	0.600
97.	मै० क्लासिक रियल इस्टेट	3.188
98.	मै० कृष्णा बिल्डवैल	3.944
99.	मै० उप्पल होटल्स	2.500
100.	मै० नीलगिरी कल्टीवेशन	2.434
101.	मै० त्रिपुल एक्स पोर्टस प्रा० लि०	2.380
102.	मै०मून लाईट कन्सट्रक्शन	1.669
103.	मै० डी०एल०एफ० यूनिवर्सल	4.438
104.	एच०एल०एफ०	16.000
105.	मै० डिस्कवरी होलीडेज	3.000
106.	मै० विक्टर एलैक्ट्रोनिक्स	4.390
107.	मै० वानी टैक्टनॉलिजी	2.120
108.	श्री किशन चन्द	3.125
109.	श्री गजराज सिंह	1.970
110.	श्री तारा चन्द	3.047
111.	मै० पैगासस बिल्डटैक लि०	2.739
112.	श्रीमती सुशिला देवी एण्ड अदर्स	2.257
113.	मै० डी०डी० रिसोर्टस	3.884
114.	मै० पी०एन०बी० कन्सट्रक्शन	2.059
115.	मै० एक्टीव सक्यूरिटी	2.220
116.	एम०बी०जी०जी०	4.039
117.	मै० आनंत दृष्टि बिल्डर	1.881
118.	मै० यूनिटैक	1.500
119.	मै० एस्सल हाउसिंग	4.000

1	2	3
120.	महावीर सिंह	8.031
121.	मै० एटलांटिक रिलेटरस	2.031
122.	मै० विपुल इन्फ्रासट्रक्चर	2.453
123.	मै० विपुल इन्फ्रासट्रक्चर	2.592
124.	सनसिटी रियल इस्टेट प्रा० लि०	3.562
125.	विनोद कुमार मंगला परसनाथ रिलेटर्स प्रा० लि०	2.420
126.	मै० पारस बिल्डटैक प्रा० लि०	2.293
127.	राहेजा डिवैलपरस प्रा० लि०	2.718
128.	मै० ए०एल०एम० इन्फोटैक प्रा० लि०	3.305
129.	मै० जे० सी० लैंड बेस प्रा० लि०	3.650
130.	मै० अजय अग्रवाल	2.000
131.	मै० आशुतोष डबलपरस	2.768
132.	मै० हरियाणा ओर्वड	2.485
133.	मै० साना रिलेटरस	3.375
134.	मै० पाल मोटर्स	2.968
135.	श्री भरत सिंह	2.181
136.	मै० एनरजेटिक कन्सट्रक्शन	11.470
137.	मै० होमेज बिल्डरस	2.158
138.	मै० गोड गिफट प्रोप ०	2.066
139.	मै० सर्वमंगलम	3.743
140.	मै० एसबी डबलपरस	4.248
141.	मै० जय यातायात	3.619
142.	मै० डी०एल०एफ० हाउसिंग लि०	3.272
143.	मै० दिल्ली लैंड एण्ड फाईनैंस	2.121
144.	मै० मंत्री आउसिंग	4.068
145.	मै एन०एस०आर० फार्मस प्रा० लि०	3.669
146.	श्री अनुमोद शर्मा	4.731
147.	मै० सहारा इंडिया	3.789
148.	डी०एल०एफ०	2.188
149.	मै० मोनिका प्रोपर्टी डीलर	3.192
150.	मै० ऐरियंस इन्फोटैक	3.953

1	2	3
151.	मै० कृष्ण प्रोपर्टीज	3.250
152.	मै० इ०एम०सी०आई०पी०आई० इलैक्ट्रोनिक	2.400
153.	डी०एल०एफ०	2.153
154.	मै० डी०एल०एफ०	2.756
155.	मै० विपुल इन्फ्रास्ट्रक्चर	3.131
156.	वैनया डबलपरस प्रा० लि०	2.490
157.	मै० वाटिका लैंड बेस प्रा० लि०	2.143
	कुल	**406.535**
	फरीदाबाद	
158.	कन्ट्रीवाईड	1.260
159.	कन्ट्रीवाईड	1.270
160.	कन्ट्रीवाईड	2.012
161.	कन्ट्रीवाईड	1.000
162.	कन्ट्रीवाईड	1.151
163.	कन्ट्रीवाईड	1.722
164.	कन्ट्रीवाईड	1.700
165.	कन्ट्रीवाईड	2.500
166.	कन्ट्रीवाईड	3.000
167.	कन्ट्रीवाईड	1.900
168.	मै० परसुनाथ लैंड मार्क डबलपरस प्रा० लि०	1.297
169.	मै० अजय इन्टरप्राईजिज प्रा० लि०	1.383
170.	मै० न्यू होरीजोन बिल्डवैल प्रा० लि०	0.640
171.	मै० इरोज कन्सट्रक्शन प्रा० लि०	1.608
172.	मै० वर्धमान प्रापर्टीज लि०	1.297
173.	मै० एल०डी० को इन्फ्रासट्रक्चर एण्ड प्रोपर्टीज	1.575
174.	मै० पारसनाथ डबलपरस	1.630
175.	मै० एस०एम०जी० इस्टेट	0.850
176.	मै० निताशा आउसिंग एण्ड अर्बन डबलैपमैंट	0.880
177.	मै० रूपा कन्सट्रक्शन प्रा० लि०	0.555
178.	मै० जी०एस० डबलपरस	0.993
179.	मै० वर्लफूल इंडिया	0.743
180.	मै० क्राउन इन्टरनैशनल	2.710

1	2	3
181.	मै० क्राउन बिल्डटैक प्रा० लि०	4.730
182.	मै० कन्ट्रीवाईड प्रोमोटर्स	3.806
183.	मै० एम०बी० मालस	3.688
	कुल	**45.900**
	पंचकूला	
184.	अमरावती	3.122
185.	अमरावती	0.132
186.	मै० शालीमार इस्टेट प्रा० लि०	1.734
187.	मै० संतूर	1.734
	कुल	**6.772**
	कुरुक्षेत्र	
188.	मै आर०आर० एसोसिएट	0.611
	करनाल	
189.	सी०एच०डी० डबलपरस	0.840
190.	टरू जोन	1.000
191.	ग्रेन्डुअर	4.390
192.	ग्रेन्डुअर	1.000
193.	टरू जोन	2.150
194.	सुपर माल प्रा० लि०	0.608
	कुल	**9.988**
	भिवानी	
195.	युधवीर सिंह	0.444
	हिसार	
196.	डफोडिल	2.620
	यमुनानगर	
197.	सुरभि बिल्डकॉन	1.810
	रोहतक	
198.	शरद फार्म	3.580
199.	शरद फार्म	2.500
200.	उदार गगन	2.050
201.	उदार गगन	2.400
202.	ओमैक्स	3.070
	कुल	**13.600**

1	2	3
	पानीपत	
203.	एलडीको	1.800
204.	सुशांत सिटी फेस-1	2.990
205.	सुशांत सिटी फेस-1	3.360
206.	सुशांत सिटी फेस-1	1.200
207.	सुशांत सिटी फेस-2	1.100
208.	सुशांत सिटी फेस-2	2.000
209.	तनेजा डवलपरस	2.740
210.	मै० डी०ए०पी० इस्टेट प्रा० लि०	0.934
211.	कोसमस बिल्डरस	0.899
212.	कोसमस बिल्डरस	0.899
213.	मै आंसल प्रोपर्टीज	3.600
	कुल	**21.522**
	सोनीपत	
214.	रंगोली	3.900
215.	सुशांत सिटी फेस-2	1.000
216.	सुशांत सिटी फेस-1	3.900
217.	सुशांत सिटी फेस-1	2.115
218.	सुशांत सिटी फेस-1	1.000
219.	मकसद	1.650
220.	मकसद	1.170
221.	मेपक्सो	3.350
222.	परसुनाथ	0.960
223.	परसुनाथ	1.670
224.	परसुनाथ	1.980
225.	परसुनाथ	3.300
226.	टी०डी०आई० सिटी	6.360
227.	टी०डी०आई० सिटी	3.230
228.	टी०डी०आई० सिटी	1.562

1	2	3
229.	टी०डी०आई० सिटी	1.390
230.	टी०डी०आई० सिटी	1.090
231.	टी०डी०आई० सिटी	1.120
232.	टी०डी०आई० सिटी	1.000
233.	टी०डी०आई० सिटी	1.000
234.	टी०डी०आई० सिटी	1.200
235.	टी०डी०आई० सिटी	1.440
236.	टी०डी०आई० सिटी	1.570
237.	टी०डी०आई० सिटी	1.260
238.	टी०डी०आई० सिटी	1.710
239.	टी०डी०आई० सिटी	1.150
240.	टी०डी०आई० सिटी	1.250
241.	टी०डी०आई० सिटी	2.370
242.	टी०डी०आई० सिटी	1.380
243.	टी०डी०आई० सिटी	1.900
244.	टी०डी०आई० सिटी	1.150
245.	टी०डी०आई० सिटी	1.080
246.	टी०डी०आई० सिटी	1.200
247.	ओमैक्स	1.456
248.	ओमैक्स	0.887
249.	ओमैक्स	0.970
250.	ओमैक्स	1.730
251.	ओमैक्स	1.140
252.	ओमैक्स	1.900
253.	ओमैक्स	1.860
254.	ओमैक्स	1.180
255.	मै० इनटाईम प्रोमोटरस	4.431
256.	मै० इनटाईम प्रोमोटरस	3.870
257.	मै० डिजाईन प्रोमोटरस	4.316

1	2	3
258.	मै० प्रसटिज एसोसिएटस	2.050
259.	मै० पारकर बिल्डवैल	4.062
	कुल	**91.259**
	सिरसा	
260.	बी०पी०एन०	1.000
261.	ड्रीम बिल्डकॉन	1.370
	कुल	**2.370**
	कुल जोड़	**603.381**

Regarding shifting of Public Health Division

***656. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether it is a fact that Public Health Division as well as Sub-division has been shifted from Dabwali; if so, what are the reasons thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : जी हां श्रीमान् । लोक निर्माण विभाग (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) मण्डल के साथ-साथ उप-मण्डल डबवाली से बदले जा चुके हैं क्योंकि वर्तमान कार्यभार के अनुसार इस मण्डल और उप-मण्डल को वहां रखने का कोई औचित्य नहीं बनता था।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cases of Murder Registered in the State

78. Prof. Chhattar Pal Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases of murder, attempt to murder and rape that have been registered in Haryana State during the period from 1st April, 1996 to February, 2007;

(b) the number of male and female accused out of aforesaid cases separately togetherwith the number of accused punished by the Courts out of the said accused alongwith the nature of punishment awarded therein; and

(c) the number of cases are pending for hearing in the District Courts, High Court and Supreme Court at present alongwith the brief detail thereof ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : (क) (ख) तथा (ग) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

भाग (क)

वर्ष	दर्ज मुकदमों की कुल संख्या		
	हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
1	2	3	4
1 अप्रैल, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक	467	244	249
1997	614	416	371
1998	807	403	362
1999	825	482	370
2000	784	523	418
2001	781	465	385
2002	763	486	363
2003	705	441	355
2004	732	432	387
2005	782	432	461
2006	873	583	607
2007 (28-2-2007)	115	84	75
कुल	**8248**	**4991**	**4403**

भाग (ख)

वर्ष	गिरफ्तार किए पुरुष दोषियों की कुल संख्या		
	हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
1	2	3	4
1 अप्रैल, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक	1131	1181	380
1997	1298	1335	485
1998	1767	1136	465
1999	1731	1308	494
2000	1608	1764	535
2001	1737	1301	524
2002	1605	1516	499
2003	1371	1531	526
2004	1365	1264	591
2005	1526	1328	590
2006	1485	1406	677
2007 (28-2-2007)	137	90	64
कुल	**16761**	**15160**	**5830**

वर्ष	गिरफ्तार किए महिला दोषियों की कुल संख्या		
	हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
1	2	3	4
1 अप्रैल 1996 से 31 दिसम्बर 1996 तक	66	24	11
1997	83	35	13
1998	82	50	12
1999	78	51	27
2000	81	56	22
2001	97	41	26
2002	105	41	33
2003	93	69	26
2004	60	32	35
2005	74	27	32
2006	87	51	28
2007 (28-2-2007)	2	0	0
कुल	**908**	**477**	**265**

वर्ष	सजा किए गए दोषियों की कुल संख्या		
	हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
1	2	3	4
1 अप्रैल 1996 से 31 दिसम्बर 1996 तक	321	267	86
1997	440	249	111
1998	527	176	93
1999	447	285	96
2000	483	245	124
2001	524	271	116
2002	555	263	126
2003	380	215	139
2004	315	182	112
2005	282	126	78
2006	99	74	34
2007 (28-2-2007)	8	0	0
कुल	**4381**	**2353**	**1115**

दोषियों को दी गई सजा की प्रकृति

हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
जुर्माने सहित आजीवन कारावास	अधिकतर दोषियों को जुर्माने सहित 5 से 10 वर्ष का कारावास	अधिकतर दोषियों को जुर्माने सहित 5 से 10 वर्ष का कठोर कारावास व कुछ मुकदमों में जुर्माने सहित 2 से 5 वर्ष का कारावास

भाग (ग)

वर्ष	जिला न्यायालयों में सुनवाई के लिए लम्बित मुकदमों की कुल संख्या		
	हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
1	2	3	4
1 अप्रैल 1996 से 31 दिसम्बर 1996 तक	11	18	4
1997	15	34	10
1998	31	33	8
1999	50	50	19
2000	67	52	26
2001	92	83	44
2002	116	91	48
2003	155	122	59
2004	236	187	99
2005	417	287	187
2006	494	337	348
2007 (28-2-2007)	15	4	12
कुल	**1699**	**1298**	**864**

वर्ष	उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लम्बित मुकदमों की कुल संख्या		
	हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
1	2	3	4
1 अप्रैल 1996 से 31 दिसम्बर 1996 तक	2	0	0
1997	1	0	0
1998	1	0	1
1999	1	0	0
2000	0	0	0
2001	2	0	0
2002	2	2	0

1	2	3	4
2003	0	0	1
2004	2	4	2
2005	3	3	4
2006	2	1	0
2007 (28-2-2007)	0	0	0
कुल	**16**	**10**	**8**

वर्ष	सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लम्बित मुकदमों की कुल संख्या		
	हत्या	हत्या का प्रयास	बलात्कार
1	2	3	4
1 अप्रैल 1996 से 31 दिसम्बर 1996 तक	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007 (28-2-2007)	0	0	0
कुल	**0**	**0**	**0**

राज्यपाल से संदेश

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a communication from His Excellency, A.R. Kidwai, Governor of Haryana on 16th March, 2007 which reads as under :—

"I have received your demi-official communication dated 18th March, 2007, No. HVS-LA-38/2007/3244, alongwith a copy of "Motion of Thanks" passed by the Haryana Vidhan Sabha on my address on 14th March, 2007.

Please do convey my sincere appreciation and acknowledgement regarding the same to all the esteemed Members of the Haryana Vidhan Sabha."

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Shri Anil Thakkar, Parliamentary Secretary dated 19th March, 2007 which reads as under :—

> "I am unable to attend the current Budget Session from 20th March, 2007 to 22nd March, 2007 due to personal reason. Therefore, I may be permitted accordingly."

Mr. Speaker : Question is—

That permission for leave of absence from 20th March, 2007 to 22nd March, 2007 from the Budget Session be granted.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज़पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will lay the paper on the Table of the House.

Parliamentary Affairs Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 117/ H.A. 6/2003/S. 60/2006, dated the 29th December, 2006, regarding the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2006, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Town and Country Planning Department Notification No. DS-II-07/2717, dated the 29th January, 2007, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (First Amendment) Rules, 2007, as required under section 24 (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 4/Const./Art. 320/2007, dated the 27th February, 2007, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2007 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Report of Commission of Inquiry (G.C.Garg Commission) Relating to clash between industrial workers and Police at Gurgaon on 25-7-2005 alongwith Memorandum, as required under sub-section (4) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

न्यायाधीश भल्ला जांच आयोग की रिपोर्ट

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी इंग्लिश ट्रिब्यून में जस्टिस भल्ला कमीशन रिपोर्ट की जानकारी अखबार के माध्यम से लोगों को दी गई। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही घिनौना अपराध था जो उस वक्त की सरकार और सरकार के मुखिया श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जानबूझ कर किया अपनी और अपने परिवार की राजनीति को बढ़ाने के लिए किया और हरियाणा के बेरोजगार नवयुवकों को गुमराह करने के लिए इस विधान सभा में वे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बिल लेकर आए थे। अध्यक्ष महोदय, उस समय आप भी यहां बैठा करते थे। आपने और हमने इनको समझाया भी था कि जो ये बिल राजनीतिक मंशा से इस विधान सभा में लेकर के आए हैं, इससे प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं होगा। स्पीकर सर, इस बारे में अखबार में हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक जस्टिस भल्ला ने व्यापक जानकारी और प्रदेश में जगह जगह सुनाई करने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी है। उस पर एक तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को सदन की टेबल पर रखें जिससे कि यह पता लगे कि क्या-क्या गुस्ताखियां इन्होंने की, जो कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज कराई,ताकि उनकी जानकारी प्रदेश के लोगों को मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक धर्म की पालना ओमप्रकाश चौटाला जी ने नहीं की इनके सहयोगियों और इनके चहेते अधिकारियों ने भी जो संवैधानिक धर्म की पालना करनी थी, वह नहीं की। इनके इस व्यवहार ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर प्रजातंत्र के नियमों का मखौल उड़ाया । अध्यक्ष महोदय, देश के लोग यह कहकर मखौल उड़ाते हैं कि हरियाणा में कैसी सरकारें बनती हैं, वे क्यों नहीं संवैधानिक धर्म की पालना करती हैं । कोई भी बिल लाने से पहले कानून के उन तमाम पहलुओं पर गौर क्यों नहीं करतीं, जिन पर गौर करना चाहिए ? उस बिल में साफ लिखा हुआ था कि बिना गवर्नर की इजाजत के प्रदेश के अंदर भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि उस वक्त की सरकार के मुख्यमंत्री जी उन दिनों अभिमान और अहंकार की दुनिया में एक नयी जिंदगी जी रहे थे, धरती से 50 फुट ऊपर चलने का उनका इरादा होता था। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में माननीय सदस्य को अनपार्लियामैंटरी बातें नहीं कहनी चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अनपार्लियामैंटरी बात नहीं कही है।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, जिस व्यक्ति विशेष के बारे में जो बात कही जा रही है वह माननीय सदस्य अपनी पर्सनल एक्सपलेनेशन में अपनी बात कह सकता है। जब उस माननीय सदस्य को कोई ऐतराज नहीं है तो इन दोनों सदस्यों को खड़े होकर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा और डॉ० सीता राम जी पहले आप चेयर से परमिशन लें उसके बाद आप अपनी कोई बात सदन में कह सकते हैं। अगर किसी माननीय सदस्य के बारे में कोई पर्सनल बात कही जा रही है तो वह माननीय सदस्य अपनी स्थिति अपनी पसर्नल एक्सपलेनेशन द्वारा स्पष्ट कर सकता है। What is from your side ? (Interruption)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी बात कह लूं कि अभी तो मैंने काफी कुछ कहना है फिर ये बीच में उठेंगे। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात सदन में नहीं कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये बातें आप बाहर कहना सदन में ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है।

सदस्य का नाम लेना

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में यह बात कही थी कि जस्टिस भल्ला जांच आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर तभी रखी जायेगी जब सरकार इस रिपोर्ट को एग्जामिन कर लेगी इसलिए उससे पहले इस विषय पर बात करने का इस समय कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य एक अखबार का जिक्र कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात को सरकार ने लीकेज किया है या अखबार की लीकेज को सही माना है। अब तक सदन के पटल पर कोई चीज नहीं आई और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। पहले तो यह बताया जाए कि इसके लिए दोषी कौन है ? इस मामले में सरकार दोषी है या अखबारात जबकि मुख्यमन्त्री जी कह रहे हैं कि इस मामले को एग्जामिन कर रहे हैं, इस रिपोर्ट की लीकेज में किसका कसूर है ? गैर जरूरी तौर पर आप लोगों को बोलने की छूट दिये जा रहे हैं। आप को तो इस बारे में सोचना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौटाला साहब कुछ बात कह रहे थे। इनका यह अधिकार है यह कह सकते हैं लेकिन बगैर कारण चौटाला साहब द्वारा चेयर पर ऐसपर्शन करना ठीक नहीं है। (विघ्न) मेरी आपसे दरखास्त है कि इन शब्दों को एक्सपैंज किया जाए। These unwarranted allegations should be expunged.

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, ऐसा कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं था, कोई अखबार का नाम नहीं था। आप भी परसों इस सदन में एक अखबार की खबर की कटिंग दिखा रहे थे जिस अखबार का कोई नाम नहीं था। कोई बात नहीं थी, कोई अखबार आप सदन में ला नहीं सकते।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह कोई सदन के पटल पर रखी जाने वाली चीज नहीं थी। जिस पर चर्चा हो वही चीज सदन में पटल पर रखी जाती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह अखबार तो माननीय सदस्य ने अपने घर पर ही छपवा लिया होगा।

श्री अध्यक्ष : हां, जी, दलाल साहब, आप कन्टीन्यू कीजिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब आज इतने बेबस नजर आ रहे थे। (शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर है, मैम्बर को अपनी बात कहने का अख्तियार है। (शोर)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने इस माननीय सदस्य को कैसे छूट दे रखी है कि कोई मामला सदन की पटल पर आया ही नहीं है और यह मामला लीक हो गया है। सरकार इस बारे में स्पष्ट करे कि क्या यह मामला अखबार के द्वारा एग्जामिन होगा या सरकार एग्जामिन कर रही है ? मैंने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था यह मामला सरकार ने लीक किया है या अखबार ने लीक किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में यह कहा था कि पहले हम इस मामले को एग्जामिन करवायेंगे उसके बाद यह मामला सदन के पटल पर रखा जायेगा। आप गैर जरूरी तौर पर किसी को छूट दे देते हैं। इस तरह की परम्पराएं सदन में कायम मत करो अन्यथा यह ठीक नहीं होगा। आप शुरू से ही गलत परम्पराएं कायम कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जीरो आवर है। आप कौन सी परम्पराओं की बात कर रहे हैं चौटाला साहब, आप बैठ जाइये। वरना आपको मुझे नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप अपनी सीट पर बैठिये। (शोर)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सदस्य सदन की वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे)

Mr. Speaker : Please take your seats. Nothing is to be recorded. (Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * **

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * **

Mr. Speaker : Chautala ji, I warn you.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * **

Mr. Speaker : I warn you. Please go to your seat, otherwise, I will have to name you.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * **

Mr. Speaker : I name Mr. Om Parkash Chautala. He may please leave the House.

(Shri Om Parkash Chautala did not leave the House.)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी को आपने नेम कर दिया वह आदमी अभी भी सदन में मौजूद है। क्या यह सदन की गरिमा है ? इनको हाउस से बाहर जाना चाहिए। यह जिन्दा लोगों की बात है जो लोग सच्चाई नहीं सुन सकते वे ही मुर्दा लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान)

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Marshal, take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took Shri Om Parkash Chautala out of the House.)

बैठक का स्थगन

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बोलें। (शोर एवं व्यधान) आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही। (शोर एवं व्यधान)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का व्यवहार विपक्ष के साथी सदन की वैल में आकर कर रहे हैं यह इनको शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान) इनको सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद ओढ : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

श्री साइदा खान : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Please go to your seats. आप इस तरह से सदन की वैल में आकर शोर न मचायें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इनको सदन की वैल में आकर सदन की कार्यवाही नहीं रोकनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इनको अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर इंदौरा जी, प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठें। मैं आपको बोलने के लिए समय देता हूं। प्लीज डॉक्टर साहब आप अपनी सीट पर जाकर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, ये लोग सदन की गरिमा की पालना नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलने के लिये समय दे रहे हैं फिर भी ये नहीं बोलना चाहते। सदन की वैल में आकर इनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बात ये कहना चाहते हैं वह बात अपनी-अपनी सीटों पर जाकर कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, ** * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ** * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please go to your seat.(Interruptions) आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही! डॉक्टर सीता राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं ? प्लीज आप अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान) यहां सदन की वैल में खड़े होकर कोई बात कहेंगे तो वह रिकार्ड नहीं की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जायें और जो बात कहना चाहते हैं वह कहें। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर इंदौरा जी आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या रीजैंटमैंट है ? पहले आप अपनी सीट पर जायें और फिर अपनी बात कहें, मैं आपको बोलने के लिए समय देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

(इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य वैल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे)

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर इन्दौरा जी व डॉक्टर सीताराम जी आप अपनी सीट से बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आज इनका पाठ इतना ही था, यही था। आज यह अपने नेता से इनके नेता इनको सीट से बोलने की इजाजत लेकर नहीं आये हैं आज ये सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं बल्कि नारेबाजी करके सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए ही आये हैं। इनको यही पाठ पढ़ाया गया है इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं सिखाया है। (शोर व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the sitting of the House is adjourned for 10 minutes today the 19th March, 2007.

*15.16 hrs. (The Sabha then *adjourned for 10 minutes on Monday, the 19th March, 2007)

श्री ओम प्रकाश चौटाला को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के हाउस में उपस्थित सभी सदस्यगण वैल में आकर खड़े हो गये और नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें और जो भी कहना है वह अपनी सीटों से कहें। (विघ्न एवं शोर) इन्दौरा साहब, आप अपने नेता को बताइये वे खुद मुख्य मन्त्री रहे हुए हैं और इतने पुराने आदमी हैं, उनको पता होना चाहिए कि चेयर को कैसे ऐड्रैस करते हैं। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) आप लोग क्या चाहते हैं ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

आवाजें : हम चाहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी को हाउस में वापिस बुलाया जाए। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे इन साथियों ने कहा है मेरा भी निवेदन है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को हाउस में बुला लिया जाए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप चौटाला साहब को बुलवा लें। (विघ्न एवं शोर) वे चेयर को ऐड्रैस करें। (विघ्न एवं शोर) He should mend himself. वे चेयर को चैलेंज नहीं कर सकते। (विघ्न एवं शोर) डॉ० साहब आप चौटाला साहब को बुलवा लें। (विघ्न एवं शोर)

आवाजें : अध्यक्ष महोदय, हमारी शर्त है। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हाउस में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती। (विघ्न एवं शोर) आप लोग उनको हाउस में बुलवा लें। (विघ्न एवं शोर) Mr. Chautala may come into the House.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी दरियादिली है कि आपने श्री चौटाला जी को हाउस में दोबारा वापिस बुलाया है। (विघ्न एवं शोर) इन लोगों का तो एकमात्र ध्येय है कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना है और सदन की कार्यवाही नहीं चलने देनी है। इनके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं इसलिए ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जाएं। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता की तरफ से उदारता दिखाई गई है कि उनको हाउस में वापिस बुलाया जाए और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने उनको दोबारा हाउस में आने का मौका दिया है और आपने कहा है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को हाउस में आना चाहिए और उनकी पार्टी के सदस्यों को भी चाहिए कि वे अपना व्यवहार दुरूस्त करें। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इनको अपने नेता को हाउस में बुलाना चाहिए लेकिन उनको बुला कर लाने की इनकी हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत ये लोग नहीं कर सकते हैं। (विघ्न एवं शोर) स्पीकर सर, हरियाणा के लोग इनका व्यवहार देख रहे हैं। किस तरह से उद्दण्ड व्यवहार ये लोग सदन के अन्दर दिखा रहे हैं तथा सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डाल रहे हैं। (विघ्न एवं शोर) ये लोग अपने इस व्यवहार से हरियाणा की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। स्पीकर सर, अपने इसी व्यवहार की वजह से इन लोगों की संख्या 8-9 तक सिकुड़ गई है और आने वाले समय में इनकी संख्या और भी कम होने वाली है। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Please go to your seats. डॉक्टर साहब, अपने साथियों के साथ अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी ने जो भी बात बोलनी है आप अपनी सीटों से बोलें । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको इनके नेता के जाने से खुशी है और ये सदन की वैल में हंस हंस कर नारे लगा रहे हैं। इनको उनके जाने का दुःख नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर सर, ये सभी मन से तो बहुत खुश हैं कि इनके नेता सदन से चले गए हैं। ये यहां पर हंस हंस कर नारे

लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यदि इनका मन उदास होता तो ये यहां पर हंस हंस कर नारे नहीं लगाते। (शोर एवं व्यवधान) अगर मन दुःखी होता है। तो मन में और चेहरों पर मायूसी होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस० एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है। इनका गुरू इनको सिखा कर गया है कि इस सदन को चलने नहीं देना है और इसी तरह से शोर मचाते रहना है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर सुशील इन्दौरा जी, आपकी रिक्वैस्ट थी कि आपके नेता को सदन में वापिस बुला लिया जाए और मैंने उनको वापिस बुला लिया है। (शोर एवं व्यवधान) आप उनको बुला लें। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता किस बात की माफी मांगे। (शोर एवं व्यवधान) आप सदन की गरिमा की क्या बात करते हैं ? (शोर एवं व्यवधान) आपके नेता को तमीज नहीं है कि चेयर के साथ किस तरह से बात की जाती है। (शोर एवं व्यवधान) उनको बोलने का कुछ पता नहीं है कि किस तरह से सदन में बोला जाता है। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता किस लिए माफी मांगे ? (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * *

डॉ० सीता राम : * * * * * *

श्री बलवन्त सिंह : * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * *

डॉ० सीता राम : * * * * * *

श्री बलवन्त सिंह : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पांच मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, तानाशाह तो बाहर चले गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय * * * * * *

डॉ० सीता राम : * * * * * * *

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाए।

विधान कार्य--

दि पंजाब विलेज कॉमन लैण्डस (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2007

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, जो पंजाब विलेज कॉमन लैंड ऐक्ट के तहत अमैंडमैंट इस हाउस में लाई गई हैं उसमें सैक्शन 2-3 और 4 तो फॉर्मल हैं (शोर एवं व्यवधान) सैक्शन 5 के बारे में कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। सैक्शन 5 जो हैं उसमें क्लॉज बी "(b) the maximum and minimum area to be sold, gifted, exchanged or leased to any single person,". इसमें minimum or maximum area के बारे में लिखा है। Who will decide about minimum or maximum area ? अगर किसी को कॉमन लैंड देनी है तो उसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट स्थापित करनी चाहिए कि कितनी जमीन दी जा सकती है। पंचायत की अपनी जमीन के रेशो में कि किस पंचायत के पास कितनी जमीन है, उस रेशो में उसकी लिमिट स्थापित की जाए कि ग्राम पंचायत विलेज कॉमन लैंड गिफ्ट सेल लीज तक किसको कितनी जमीन दे सकती है और दूसरी बात यह है कि जमीन किन शर्तों पर दी जा सकती है। इसमें लिखा है कि कुछ शर्तों पर जमीन दी जा सकती है उन शर्तों को ऐक्सप्लेन किया जाए। Who will decide and what will be the terms and conditions ? (Noises and interruptions) कितना हिस्सा मॉर्टगेज हो सकता है और कितना हिस्सा सेल हो सकता है इसके लिए कोई न कोई क्राईटेरिया तो स्थापित किया जाए। दूसरा यह है कि इसके अन्दर जो प्रोविजन किया है इसमें टर्म्ज एण्ड कंडीशंज प्रिसक्राईब की हैं वे क्या हैं और इन टर्म्ज एण्ड कंडीशंज को कौन प्रिसक्राईब करेगा ? अपने गांव की जमीन के बारे में या तो अलग-2 पंचायतें करेंगी या सरकार करेगी या रूरल

[चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक]

डिवैल्पमैंट के तहत ये बातें आयेंगी। पहले तो इसमें एक बात के लिए प्रोविजन था लेकिन अब उसको निकाल दिया है। होस्पिटल को या गांव में कोई सुविधा देने के लिए कॉमन लैंड केवल किसी इन्स्टीच्यूट को दी जा सकती थी। अब गिफ्ट की जगह बाकी चीजें उसमें शामिल कर दी हैं, मेरी यही प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपकी बात क्लीयर हो गई है। इसमें सारी बातें आ गई हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह की बेहूदगी इनैलो के सभी सदस्य कर रहे हैं। ये लोग जानबूझकर शरारत कर रहे हैं ये लोग नहीं चाहते कि जस्टिस भल्ला की रिपोर्ट इस सदन में आए। अखबार में पढ़ा है कि आदरणीय जस्टिस भल्ला साहब ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को, उस वक्त के डी०जी०पी० को और उनके सहयोगियों को इस रिपोर्ट में इनलिस्ट किया है जिन्होंने मिलकर बेरोजगार युवकों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया और ये नौजवान आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाईये,सदन के नेता खड़े हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जिस भल्ला कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सदन में चर्चा माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा की जा रही है वे एक अखबार की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अभी सरकार द्वारा सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। अखबार की रिपोर्ट स्पैकुलेटिव हो सकती है उस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कल इस रिपोर्ट के बारे में पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी लेकर इस रिपोर्ट को कल सदन के पटल पर रखा जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में कहा है कि कल इस रिपोर्ट को एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद सदन में रखा जायेगा यह बहुत ही प्रशंसा का कार्य है। यह कार्य करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के नौजवानों को एक भरोसा दिलाया है कि यदि कोई सरकार अपने कार्यकाल में पद का दुरूपयोग करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगी तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को यथायोग्य सजा दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से सरकारी खजाने का करोड़ों रूपया इन्होंने जानबूझकर खर्च किया । सारी मर्यादाओं को ताक पर रख कर एप्वार्यटमैंट लैटर जेब में रखकर अपने चहेतों को इस फोर्स के लिए भर्ती किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट कल सदन में रखी जायेगी। यह प्रशंसनीय कार्य है और हरियाणा की जनता इस रिपोर्ट का इन्तजार कर रही है। इन लोगों ने जो कसूर और गुस्ताखियां की हैं उनके लिए इन्हें सजा दिलाने का इससे बेहतर कार्य और कोई हो नहीं सकता। थैंक यू सर। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन ऐरियाज (अमैण्डमैंट) बिल, 2007.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि हुड्डा और प्राईवेट कालोनाईजर जिस समय कोई स्कीम प्लोट करते हैं उस समय वे स्कीम को बड़ी बढ़ा-चढ़ाकर एडवर्टाईज करते हैं कि सभी तरह की सुविधाएं दी जायेंगी। लेकिन जब आम जनता उसमें पैसे लगा देती है और प्राईवेट कालोनाईजर्स तथा सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तब भी वे बिजली, पानी और सड़क आदि की परोपर सुविधा नहीं दे पाते। इस तरफ हमारी जो हाई पॉवर परचेज कमेटी है उसको ध्यान देना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब शैडयूल्ड रोडज़ एण्ड कण्ट्रोल्ड ऐरियाज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैण्डमैंट) बिल, 2007.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, जो कंट्रोल्ड ऐरिया कायम करने के बाद जितने भी हाईवेज बनाये जाते हैं चाहे नैशनल हाईवे हों या स्टेट हाईवे हों उनके दोनों तरफ वॉयलेशन शुरू हो जाती है। करोड़ों अरबों रुपये लगाकर जो हाईवे बनाये जाते हैं, वॉयलेशन करके लोग उनके साथ मकान बना लेते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं यहां तक कि ग्रीन बैल्ट भी नहीं छोड़ते और बाद में ऐसे अनाधिकृत निर्माणों को हटाना पड़ता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश पारित किए हैं। सरकार इन आदेशों को लागू करने की कोशिश भी करती है, लेकिन सरकार उन आदेशों को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाती । मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस तरह की वॉयलेशन के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए। शुरू से ही जो हाईवेज हैं उनके साथ किसी को कोई वॉयलेशन न करने दें। उस विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना चाहिए ताकि हमारे यहां कोई भी वॉयलेशन न हो और दुनिया के मुल्कों की तरह हमारे हाईवेज अच्छी तरह से कामयाब हों और लोगों को उनसे फायदा पहुंचे।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सदस्य वैल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे)

सदस्य का नाम लेना

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा जी, आप लोगों की रिक्वैस्ट थी कि हमारे नेता को वापिस बुलाया जाये, सदन के नेता ने जबरदस्त ग्रेस दिखाई और सदन की तरफ से उन्होंने यह कहा कि उनको हाउस में वापिस बुलाया जाये। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग अपनी सीट पर जा कर बोलिए। पानी पीना है क्या ? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने इनसे पानी पीने के लिए कहा ये पानी नहीं पी रहे, आपने बोलने के लिए कहा तो बोल नहीं रहे। सीट पर बैठने के लिए कहा तो सीट पर नहीं बैठ रहे। आपने इनको बोलने की इजाजत दी तो ये लोग बोल भी नहीं रहे। आपसे निवेदन है कि आप इनसे यह पूछ लीजिए कि ये लोग क्या चाहते हैं ? हरियाणा की जनता इनको देखने लग रही है कि किस प्रकार से अपने उस्ताद के इशारों पर नाचने का काम कर रहे हैं। इनको कुछ तो पार्लियामेंटरी सिस्टम आना चाहिए और इन्हें पार्लियामेंटरी सिस्टम को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो समझदार आदमी हैं, आपको तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए आपकी सारी बातें मान ली गई हैं अब आप और क्या चाहते हैं ?

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री बलवन्त सिंह, श्री ज्ञान चन्द, श्रीमती रेखा राणा, डॉ० सीता राम, डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा आदि वैल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे)

Mr. Speaker : Please take your seats (Interruptions). डॉ० साहब, आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें और जो भी आप कहना चाहते हैं वह अपनी सीट पर खड़े होकर कहें। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० छतरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने उनको समझाया था कि सदन के अन्दर किस तरह का बिहेव करना चाहिए लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। (विघ्न एवं शोर)

सुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि इनका मुद्दा क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं ? (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : ये लोग अपने नेता को हाउस में बुलाने की मांग कर रहे हैं। उनको हाउस में वापिस आने के लिए रूलिंग दे दी है लेकिन फिर भी वे हाउस में नहीं आ रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बताया है वह आपने कर दिया तो उसके बाद इनका कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। (विघ्न एवं शोर) ये लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं यह इनको हाउस को बताना चाहिए लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनकी मन्शा केवल इतनी है कि हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देनी है। (विघ्न एवं शोर) ये लोग वैल में खड़े हुए हैं ये क्या चाहते हैं और इनकी मन्शा क्या है यह बात इनको हाउस को बतानी चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, आप सभी लोग सदन की गरिमा का थोड़ा ध्यान रखें। बगैर सीट पर गए आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं होगा। (विघ्न एवं शोर) आप लोग बिना वजह हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं और आप लोगों का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना है। (विघ्न एवं शोर) डॉ० इन्दौरा, आप अपना व्यवहार ठीक करें। (विघ्न एवं शोर) क्या आप लोग बजट पर बोलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। (विघ्न एवं शोर) इन्दौरा साहब, आप तथा आपके साथी अपना व्यवहार ठीक करें और अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आप बड़ी उदारता का परिचय दे रहे हैं और इनके व्यवहार से आपकी सहनशीलता की सारी सीमाएं पार हो गई हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, यह आपको पता ही है ? (विघ्न एवं शोर) जब तक वह कार्यवाही आप नहीं करेंगे ये लोग हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। वह कार्यवाही आपको करनी पड़ेगी। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, आप अपनी सीट पर जाएं। (विघ्न एवं शोर)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इनको इलाज की जरूरत है आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा नर्मी से काम न लें। इनका इलाज करने की जरूरत है। (विघ्न एवं शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप लोग अपनी सीटों पर जाएं और जो बात कहनी है वहीं से कहें। (विघ्न एवं शोर) डॉ० साहब, आप सदन की गरिमा का ध्यान रखें और सदन का समय बहुत कीमती है उसे खराब मत करें। (विघ्न एवं शोर) डॉ० साहब, अपना बिहेव ठीक करें। (विघ्न एवं शोर) Please take your seats. Nothing is to be recorded. (Interruption)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Indora Ji, please take your seat.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Indora Ji, I warn you.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Indora Ji, I again warn you.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : I warn you Indora Ji. Please go to your seat, otherwise, I will have to name you.

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, * * * * *

Mr. Speaker : I name Dr. Sushil Indora. He may please leave the House.

(Dr. Sushil Indora did not leave the House.)

Mr. Speaker : Marshal, take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took Dr. Sushil Indora out of the House.)

सदस्यों का निलम्बन

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं कि डॉ० सीता राम, श्री बलवन्त सिंह सढौरा और ज्ञान चन्द ओढ को सदन में उनकी उदण्डता एवं दुर्व्यवहार के लिए सदन की आज की कार्यवाही तक के लिए सस्पैंड कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That Dr. Sita Ram, Shri Balwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh M.L.As be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the Members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for today's sitting.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Dr. Sita Ram, Shri Balwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh M.L.As be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the Members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for today's sitting.

Mr. Speaker : Question is—

That Dr. Sita Ram, Shri Balwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh M.L.As be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the Members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for today's sitting.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम, श्री बलवन्त सिंह सढौरा और ज्ञान चन्द जी आप सदन से बाहर जाएं।

(At this stage, Dr. Sita Ram, Shri Balwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh, MLAs withdrew from the House)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक और प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I also beg to move–

That Shri Ishwar Singh Palaka, Shri Sahida Khan, Shri Ramphal Chirana and Smt. Rekha Rana, MLAs may also be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for today's sitting.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Shri Ishwar Singh Palaka, Shri Sahida Khan, Shri Ramphal Chirana and Smt. Rekha Rana, MLAs may also be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for today's sitting.

Mr. Speaker : Question is—

That Shri Ishwar Singh Palaka, Shri Sahida Khan, Shri Ramphal Chirana and Smt. Rekha Rana, MLAs may also be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for today's sitting.

The motion was carried.

(At this stage, Shri Ishwar Singh Palaka, Shri Sahida Khan, Shri Ramphal Chirana and Smt. Rekha Rana, MLAs withdrew from the House)

इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार की निन्दा करना

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That this House condemns the conduct of the Members of the Indian National Lok Dal as also their behaviour in which, they in an organized and designed manner, disrupted the proceedings of the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House condemns the conduct of the Members of the Indian National Lok Dal as also their behaviour in which, they in an organized and designed manner, disrupted the proceedings of the House.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आदरणीय स्पीकर सर, जिस प्रकार से लोकदल के सदस्यों का आज व्यवहार रहा है, जिस तरह से एक घंटे से अधिक इस महान सदन का समय उन्होंने केवल अपनी हठधर्मिता, जिद और एक सोची समझी नीति जिसका फैसला वे बाहर से ही करके आए थे, के तहत नष्ट किया, क्या वह ठीक था ? स्पीकर सर, इस सदन की कुछ परिपाटी, कुछ परम्पराएं रही हैं। इस महान सदन के पटल पर जो सामने लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए या यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सत्य बात कही जाए क्योंकि न बोलने, और गलत बोलने दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बनता है। स्पीकर सर, मुझे लगता है कि लोकदल के साथी जिनका पाप का घड़ा पहले ही भर चुका था और हरियाणा की जनता ने फरवरी, 2005 के विधान सभा के चुनावों में पहले ही उस घड़े को तोड़ दिया। इन्होंने हरियाणा की जनता के वोट की चोट से प्रजातांत्रिक मूल्यों की कोई सीख नहीं ली। स्पीकर सर, पांच छः साल तक जब ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त आप भी इस महान सदन के एक सम्मानित सदस्य थे। उस समय जिस प्रकार से इस सदन की कार्यवाही को चलाया जाता था वह आपने खुद ही देखा हुआ है। स्पीकर सर, कोई बजट सत्र ऐसा नहीं होता था जो दो से तीन दिन के अंदर समाप्त नहीं कर दिया जाता था। सोची समझी नीयत के तहत सोमवार को सत्र शुरू किया जाता था और मंगलवार, बुधवार तक सारी कार्यवाही को खत्म कर दिया जाता था और किसी

को भी उस बजट पर बोलने का मौका दिए बगैर खत्म कर दी जाती थी। स्पीकर सर, उस समय तो यह भी होता था कि आपको और विपक्ष के अन्य सम्मानित सदस्यों, यहां तक कि हमारे नेता जो उस समय विपक्ष के सम्मानित नेता थे, को भी सदन से बाहर निकालकर सदन की चटकनी को अंदर से बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार की परम्पराएं भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की की थीं। स्पीकर सर, जब आपको युनानीमसली इस सदन का अध्यक्ष चुना गया तो उस समय आपने भी और अन्य सभी सदस्यों ने भी कहा था कि हम सदन की कार्यवाही को स्वस्थ परम्पराओं के साथ चलाएंगे। उस समय आपने कहा था कि हम सभी को बोलने का मौका देंगे। स्पीकर सर, मैं आपको मुबारिकवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने उस कर्त्तव्य का पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन किया है। स्पीकर सर, इतना लम्बा बजट सत्र जिसमें तीन-तीन दिन, चार-चार दिन गवर्नर ऐड्रैस पर डिसकशन हुई और अब तीन-तीन दिन, चार-चार दिन बजट पर डिसकशन होगी, शायद ही कभी पिछले कई सालों के अंदर हरियाणा के इतिहास में इस प्रकार से हुआ होगा। स्पीकर सर, लोकदल के साथी और उनके नेता ओम प्रकाश चौटाला जिनका अपना पाप का घड़ा भर चुका है, वे विचलित हैं। भल्ला कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा की गयी है अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि वह रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है परन्तु अब तो सदन के नेता ने खड़े होकर यहां तक कह दिया कि रिपोर्ट और उस पर ऐक्शन टेकन रिपोर्ट हम कल सदन के पटल पर रखेंगे। जब सदन के नेता ने यह भी कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनको कि उनकी उदण्डता और दुर्व्यवहार की वजह से आपने सदन से निकाला था, वापस बुला लीजिए। उनका ऐसा व्यवहार होने के बावजूद भी उदारता और विशाल हृदयता दिखाते हुए आपने सदन के नेता का प्रस्ताव मान लिया और कह दिया कि चौटाला जी हाउस में आएं। (विघ्न) भल्ला कमीशन की रिपोर्ट हो या सरकार का बजट हो। चौटाला जी ने अभी तक उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। पिछले 41 साल में यह सबसे बड़ा प्लान बजट है 5400 करोड़ का यह बजट है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। विपक्ष के साथियों की केवल मात्र एक मांग थी कि हमारे नेता को वापस बुला लिया जाए। सदन के नेता ने भी उस मांग को मान लिया लेकिन उसके बावजूद भी वे भय से ग्रस्त होकर इस हाउस में नहीं आए। वे सदन को छोड़कर भाग गए और वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे कोई रचनात्मक सुझाव देते और बजट में कोई अमैंडमैंट देते तो सरकार का मन और दिमाग उनके रचनात्मक सुझाव लेने के लिए पूरी तरह खुला था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सदन की कार्यवाही में पूरी तरह से उद्दण्डतापूर्वक व्यवधान डालने की लोकदल के साथियों की प्रवृत्ति बन गई है। उनके पाप इतने अधिक हैं कि उनसे छुपाये नहीं छुप रहे हैं। स्पीकर सर, उनके इस व्यवहार को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अनुरोध करता हूं कि उनकी जो कार्यशैली है जिसके मुताबिक घंटों तक उन्होंने सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाला है। सदन के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों के पैसे और समय को जाया भी किया है, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। मेरी सदन के साथी सदस्यों से प्रार्थना है कि इस निंदा प्रस्ताव का सदन अनुमोदन करें। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है और कि मैं भी आपके माध्यम से सदन के समक्ष एक ही बात रखना चाहूंगा कि विपक्ष का व्यवहार बहुत भी निंदनीय रहा है। प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई है उस पर भी विपक्ष के साथी कुछ कह सकते थे। ये प्रदेश में हुई ओलावृष्टि पर मगरमच्छी और घड़ियाली आंसू बहाने गए थे और

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
हरियाणा के किसानों को भड़काने का काम करने गए थे। कितने दुख की बात है कि विपक्ष में रहते हुए पहली मर्तबा सदन के अंदर आए और उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं की कि किसान का बहुत नुकसान हुआ है। महज भल्ला कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जो कि सरकार का पहले से ही सदन में पेश करने का वायदा था। उसको लेकर सदन की कार्यवाही में इतना ज्यादा व्यवधान डाला गया। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि इन्होंने कैसे प्रदेश के लोगों के साथ और नौजवान बच्चों के साथ खिलवाड किया था ? इन्हीं की बदनीयती की वजह से आज हरियाणा में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं। जब चौटाला जी की काली करतूतों का जिक्र यहां होता है तो वे यहां से भाग जाते हैं। सरकार ने बिल्कुल साफ नीयत से प्रदेश के लोगों को विपक्ष के साथियों को यह दिखा दिया है कि यह सरकार किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रही है। चाहे वह खबर एक अखबार दि ट्रिब्यून ने प्रकाशित की लेकिन उसके बारे में इनको यहां पर खड़े होकर क्लेरिफाई करना चाहिए था। मैंने इस बारे में सिर्फ यह कहा था कि अब वक्त आ गया है कि यदि रिपोर्ट आ ही गई है तो सदन के पटल पर रखी जाए। इस सदन के अंदर यह इतिहास रहेगा कि किसी सदस्य को उसकी बेहूदगी की वजह से सदन से बाहर निकाला गया हो और इतनी बेहूदगी का व्यवहार करने के बावजूद सदन के नेता के कहने पर फिर वापस बुला लिया जाए तो फिर ऐसा क्या मुद्दा रह जाता है कि विपक्ष के साथी सदन में शोर शराबा करते रहें। इतने महत्वपूर्ण बिल सदन के अंदर लाये गए। उन पर साथियों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये जा सकते थे लेकिन पता नहीं ये साथी किस धरती और किस मिट्टी के बने हैं। इनके अंदर यदि जरा सी भी गैरत हो तो इनको उस व्यक्ति को अपना नेता मानने से इंकार कर देना चाहिए। जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता से खिलवाड़ किया हो ? अध्यक्ष महोदय, आज इनका बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। जिस तरीके से अपने निजी बचाव में, अपने निजी स्वार्थ में इनैलो पार्टी के नेता और उनके विधायक केवल मात्र इस लिए सदन में हंगामा करते रहे ताकि भल्ला कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा न हो सके और उनके काले कारनामों की जानकारी कहीं प्रदेश के लोगों को न मिल जाए। उस रिपोर्ट को दबाने के लिए उससे बदनामी के डर की वजह से ये लोग इस प्रकार की बेहूदगी यहां करते रहे। इस तरह की बेहूदगी ये लोग दोबारा न कर सकें इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया जाये।

प्रो० छत्तरपाल सिंह (धिराय) : स्पीकर सर, हरियाणा के लोग जनता के प्रतिनिधियों से यह उम्मीद करते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को हाउस में रखेंगे और उन समस्याओं के समाधान के बारे में सरकार को कोई ठोस सुझाव देकर और सरकार का ध्यान उस समस्या की ओर आकर्षित करेंगे। स्पीकर सर, माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार दो साल से इस प्रदेश में शासन कर रही है और आप इस सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। जो मान्यताएं आपने इस सदन में बनाई है उन मान्यताओं के तो यह इनैलो पार्टी के सदस्य लायक ही नहीं है। आपने इनके समय का आकलन खूब अच्छे तरीके से किया है वह व्यक्ति इस बात की चिन्ता जाहिर करे जिसका अपना खुद का व्यवहार कभी ठीक रहा हो। इनको न तो अच्छा व्यवहार करना आता है और न ही ये अच्छा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं। ऐसी स्थिति में वे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा किसी दूसरे से कैसे कर सकते हैं। स्पीकर सर, जैसा कि माननीय साथी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में ओले पड़ते ही आज हरियाणा प्रांत के किसानों के दुख को देखकर तुरन्त एक्शन लिया और मुआवजे के लिए गिरदावरी के आदेश दे दिए । कहने का

मतलब यह है कि जहां किसानों की जो भी समस्या दिखाई देती है उस पर सरकार तुरन्त ध्यान देती है। सरकार के दो साल के कार्यकाल में उन माननीय सदस्यों को कोई मुद्दा नहीं मिला। स्पीकर सर, आपकी पेशैन्स की भी दाद देनी पड़ेगी कि सवा तीन बजे से लेकर वे सिर्फ तीन नारे जो इनके नेता ने उन्हें लॉबी में बैठकर के समझाये थे वे ही बोलते रहे इसके सिवाय किसी चौथे नये नारे की तरफ उनका दिमाग नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आप बैठिये।

प्रो० छतरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं यह बात सदन को इनके उस्ताद के बारे में बताना चाहता हूं कि बचपन में सिरसा कल्ब में जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ताश खेला करते थे तो ये उनमें भी हेराफेरी किया करते थे ये पत्तों को काट मारा करते थे।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात सदन को बताना चाहूंगा कि कोई सदस्य तो यह कहता है कि चौधरी ओमप्रकाश चौटाला घड़ियों की चोरी करते हुए पकड़ा गया, कोई कहता है कि चौधरी देवी लाल जी ने कहा था कि यह मेरा बेटा नहीं हैं। कोई इनको अभिमानी कहते हैं और कोई इनको काली करसूतों वाला कहते हैं। कोई कहता है कि ताश खेलते हुए पत्ते चुराता था। मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ 20 साल तक रहा और उनको अच्छी तरह से मैंने देखा। चौधरी देवालाल एक बहुत ही भले और एक पंचायती आदमी थे उन जैसे आदमी के घर ऐसा खुराफाती और घटिया बेटा पैदा नहीं हो सकता जैसा ये सदस्य बता रहे हैं।

प्रो० छतरपाल सिंह : स्पीकर सर, तभी तो चौधरी देवीलाल जी ने इनको डिसओन किया और चौटाला को अपना बेटा मानने से इन्कार किया था और कहा था कि यह मेरा बेटा नहीं है। मैं तो उन से इतनी अपेक्षा नहीं करता था कि इतने लांछन उस व्यक्ति के खिलाफ लगे लेकिन वे चुप रहे। जब उनके खिलाफ इतना कुछ कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा जो इससे साफ है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। सदन में सदस्य हाजिर हो और पूरे सदन की तरफ से चर्चाएं और सवाल उठाये गये लेकिन उन्होंने उनका एक भी जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। हम उनके व्यवहार की निन्दा करते हैं। सदन के कहने पर यह निन्दा प्रस्ताव लाया गया है। उनके खिलाफ जो यह निन्दा का प्रस्ताव लाया गया है यह बिल्कुल दुरुस्त काम है। धन्यवाद।

वित्तमंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, जो निंदा प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री लेकर आये हैं उस पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से विपक्ष में सबसे बड़े दल के नेता ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपकी चेयर पर टिप्पणी की इसलिए उन्हें नारे तो आपके खिलाफ लगाने चाहिए थे लेकिन उनका यह व्यवहार भुगतना सरकार को पड़ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि केवल निंदा प्रस्ताव लाने से ही काम नहीं चलेगा। इनके लिए तो कोई हवन या यज्ञ किया जाये और ऊपर वाले से यह प्रार्थना की जाये कि जब ये लोग सदन में उपस्थित हों तो भगवान इनको इतनी बुद्धि दे कि ये सही व्यवहार करें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, परमात्मा, इन्हें बुद्धि दे या सद्बुद्धि दे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, सद्बुद्धि तो बाद की बात है, पहले इनको बुद्धि ही आ जाये। (हंसी)। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ऊपर वाला इनको इतनी बुद्धि दे कि ये लोग सदन

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

में गरिमा के साथ व्यवहार करके अपनी इज्जत बढ़ायें और सदन की भी इज्जत बढ़ायें। जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, खासतौर पर औम प्रकाश चौटाला जी से वित्तमंत्री होने के नाते मैं तो यही चाहता था कि आज बजट पर चर्चा का शुभारम्भ होना था और वे उस पर चर्चा करते लेकिन अब तो आरम्भ ही होगा, बजट के शुभारम्भ का समय निकल गया है। मैं चाहता था कि बजट चर्चा विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता इनीशियेट करते और सदन में अपने विचार रखते। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भी अफसोस है कि कम से कम हमारी जो गम्भीरता है उसको ही मद्देनजर रखते और बजट पर चर्चा करते वक्त अपनी सारी बात क्लीयर कर सकते थे। जिसके बारे में कर्ण सिंह दलाल जी ने जिक्र किया था। मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रो० छत्तर पाल जी ने ठीक ही कहा कि इसके लिए स्थाई साधन जुटाये जायें, सदस्यों को सदन से नेम करना, सस्पैंड करना या निंदा प्रस्ताव पास करना यह समाधान नहीं है। मैं 1977 में पहली बार सदन में चुनकर आया था और 20 साल का मेरा इस सदन का अनुभव है। इस सदन में हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। सदन की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि हरियाणा के अंदर जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, इन्स्टीच्यूशंज हैं, चाहे वे मार्कैटिंग कमेटियां हैं, चाहे ब्लॉक समितियां हैं, चाहे ग्राम पंचायतें हैं, चाहे जिला परिषद् हैं हमेशा इनका गला घोटकर रखा गया लेकिन अब जब स्वतंत्रता आई है तो हर आदमी को अपनी-अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जिस तरह का व्यवहार विपक्ष के साथियों ने यहां किया है यदि कोई सदस्य ऐसा व्यवहार करता है तो वह जिन दो लाख-सवा दो लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उन लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करता है तथा उन लोगों को धोखा देता है। आज ऐसी ही स्थिति चौटाला साहब ने पैदा की है। चौटाला साहब के कारनामों ने सदन को केवल एक घंटे के लिए डिस्टर्ब किया। सम्भवत: उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वे शायद ऐसा समझते हैं कि उनके पूर्व कारनामें सदन के सामने आयेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि उनको आधा घंटा और दिया जाना चाहिए था। ये प्रैस के लोग और ज्यादा गंभीरता से उनके नारों को उठाते कि चौटाला जी ने सदन के डेढ़-दो घंटे किस तरह से खराब किए। आम लोगों को यह भी मालूम पड़ता कि एक आदमी के गुनाह, एक आदमी की नाकामयाबियां, एक आदमी का घमण्ड, एक आदमी का प्रजातंत्र में विश्वास न होना, एक आदमी का ऑटोक्रेटिक राज होना और फिर सदन का समय खराब करना क्या ठीक है ? हालांकि लोगों ने इसके लिए उन्हें पहले ही सजा दे दी है। हम यह बात मानते हैं लेकिन यह पूरी सजा नहीं है। ऐसे आदमियों को सदन के अंदर बुलाकर फिर उनकी बातों का जवाब देकर उनको ज्यादा निरूत्तर कर सकते हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह से यह बात समझा सकते हैं कि उनके गुनाह लोगों तक न पहुंचे हों, ऐसी बात नहीं है। लोगों तक उनके गुनाह पहले भी पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो प्रजातंत्र की प्रणाली में, पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखने ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा मैथड ईवोल्व करें जिससे ऐसे लोग या सदस्य जब भी सदन में आयें तो नियमों और मर्यादाओं का पालन करें तो सदन की गरिमा अपने आप बढ़ेगी। ये लोग सदन की मर्यादाओं को बढ़ाने के लिए नहीं आते। नैतिकता के आधार पर लोगों ने इनको नहीं जिताया क्योंकि यह लोगों की अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में कम्पलशन हो सकती है। मेरा आपसे यह कहना है कि चड्ढा साहब जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी मैंने कहा था कि कुछ नहीं तो ओरियन्टेशन प्रोग्राम 6-7 महीने में इनके लगाने चाहिए, उससे ही ये लोग कुछ सीख पायेंगे और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को निभा पायेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें हाऊस के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि उन लोगों को कोई ट्रेनिंग दो, शिक्षा दो। इसमें शिक्षा का सवाल ही नहीं है सवाल बड़ा साफ है कि साढे 5 साल तक जिस बेहूदा तरीके से, जिस नादिरशाही ढंग से जिस चंगेजशाही अन्दाज से ओमप्रकाश चौटाला ने हरियाणा में राज किया अपनी पार्टी के मैम्बरों को धमकाया, उनके दिमाग और दिल में भय पैदा करके, डराकर जिस तरह से, राज किया है अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी वही परम्परा चल रही है। मैं दो उदाहरण दूंगा। पहले दिन जब चौटाला जी आये और आपने उन्हें बोलने की इजाजात दी तो आपने उनको कहा था कि उनका समय समाप्त हो गया है क्योंकि पार्टी के सदस्यों की संख्या के मुताबिक टाईम दिया जाता है। उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि नहीं जो 54 मिनट का समय है वह सारा वे खुद ही लेंगे। यह बात ही उस आदमी की मानसिकता दर्शाती है कि उसके लिए उसकी पार्टी कोई चीज नहीं है और उनकी पार्टी के जो बाकी के 8 सदस्य हैं वे उनके बन्धुवा मजदूर हैं, उनके गुलाम हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। आपने उस वक्त यह बिल्कुल ठीक किया। हर सदस्य की रक्षा करना और उसके अधिकार दिलवाना आपका फर्ज था। लेकिन उसने सारे सदस्यों के अधिकारों पर खुद कब्जा कर लिया था जैसे पीछे साड़े पांच साल तक उनके हकों पर कब्जा करके रखा था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने उसके अभद्र व्यवहार के कारण उसको नेम कर दिया था तो वह हाऊस पर और चेयर पर भी एसपर्सन करने लगा। जब वह बाहर चला गया तो उसकी पार्टी के जो मैम्बज थे उनको उसने यह कहा कि हाऊस की कार्यवाही को बिल्कुल नहीं चलने देना है। जिस तरह का उनका बिहेवियर रहा, वे लोग सरकार को मुर्दाबाद कह रहे थे और जैसवर आपकी तरफ कर रहे थे, इससे बेहूदा बात और क्या हो सकती है। मुंह से कुछ कह रहे थे लेकिन मन में कुछ और ही ऊरने लग रहे थे ये भी उसी की शिक्षा है। तो मैं यह कहूंगा कि इन लोगों का जो कैरेक्टर है, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो आदत है, वह इस तरह की है कि उनके हाऊस से बाहर जाने पर भी नहीं बदल सकती। उनको तो 10-20 साल के लिए जेल में जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत गुनाह कर रखे हैं जिसके काफी सबूत हैं। जो व्यक्ति समाज और सोसाईटी के लिए खतरा है वह आदमी इस हाउस के लिए भी डेंजर है। इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, मैं केवल 2-3 बातें कहूंगा। मैं इस हाऊस में पिछले करीब 8 साल से आ रहा हूं। आप और मैं पिछले सैशन में यहां पर सदस्य रहे आज जो लीडर ऑफ दी हाउस है और जो पहले लीडर ऑफ दी हाउस होते थे वे किस तरह से बात करते थे कि बैठ जाओ और ईशारा करके बाहर निकलवाया करते थे। आपने वो नेता भी देखे थे और ये जो कहते हैं वो भी देखें हैं। जब कभी भी किसी मैम्बर को सस्पैंड किया जाता था, हम भी सस्पैंड होते थे तो पूरे सैशन के लिए होते थे लेकिन यहां पर जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं वो किसी सदस्य को सिर्फ एक दिन के लिए सस्पैंड करते हैं। आपने परम्पराओं को निभाते हुए हाउस को एडजर्न भी किया, उनको बोलने का पूरा मौका भी दिया लेकिन असली बात यह है कि वे हाउस की बात और हाऊस की मर्यादा को नहीं समझते और न ही उनका लोकतंत्र में विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी वे लोग हाऊस में कोई बात नहीं करना चाहते थे। ओमप्रकाश चौटाला, महेन्द्रगढ़ के मन्डौला गांव में चले गये वहां उन्होंने 20 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने की बात कही । वहां पर लोगों ने इनको धमकाया और कहा कि जब आपकी अपनी सरकार थी तो आपने मुआवजे का एक पैसा भी नहीं बढ़ाया और

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
एक ये मुख्य मंत्री हैं जो मुआवजे के लिए इतना पैसा बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनका जनता और जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है ये दिखाने के लिए यहां पर नारेबाजी कर रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में उनकी कोई निष्ठा नहीं है।

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो निन्दा प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग किस की निन्दा कर रहे हैं। जो लोग हर तरह से इस समाज में पूर्ण रूप से निन्दनीय हैं उनकी क्या निन्दा करें। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि हवन-संध्या आदि करके कुछ शुद्धि कर ली जाए। हवन-संध्या करके शुद्धि करने का काम तो देवता प्रवृत्ति के लोग करते हैं लेकिन राक्षसों पर संध्या-हवन का कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर सर, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके राज में किस तरह से प्रदेश के अन्दर जुल्म और अत्याचार हुए हैं। इन लोगों ने झूठ बोल कर प्रदेश के लोगों को ठगा, लूटा और पूरे प्रदेश को बर्बाद किया। इस प्रदेश से उन लोगों का क्या सम्बन्ध है। स्पीकर सर, इतना जबरदस्त और बढ़िया बजट माननीय वित्तमन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री दोनों भाईयों ने मिल कर इस प्रदेश के विकास के लिए दिया है। इस बजट पर चर्चा करने का जो समय था उस कीमती समय एक घण्टा यहां पर उन्होंने बर्बाद किया। स्पीकर सर, उप-निषदों तथा वेद-शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस प्रदेश का राजा अंगहीन हुआ करता है वह प्रदेश कभी सुख-शांति से नहीं बसता जिसका उदाहरण प्रदेश में पिछले पांच साल के शासन से मिल सकता है। इस शासन के दौरान क्या हुआ । चारों तरफ हमेशा अफरा तफरी मची रही। किसी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं, किसी व्यापारी का गला सुरक्षित नहीं, किसी भाई की जान सुरक्षित नहीं। स्पीकर सर, इन लोगों ने पांच साल तक इस प्रदेश को पूर्ण रूप से हर प्रकार से बर्बाद करके रखा। आज आप देखें कि पूरा प्रदेश हर प्रकार से तरक्की और प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं। उन लोगों को यह सब सहन नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जिस दिन हाउस में बजट रखा इनकी पार्टी के दो पढ़े-लिखे आदमी सदन में हैं जो डॉक्टर कहलवाते हैं स्पीकर सर, उन दोनों सदस्यों ने उस दिन वित्त मन्त्री के पास जाकर उनको बधाई दी और कहा कि आपने आज बहुत ही बढ़िया बजट इस हरियाणा प्रदेश की जनता के लिये रखा है लेकिन अब वही लोग हाउस में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जो कि बहुत ही अशोभनीय और निन्दनीय बात है। जैसे आपने कहा कि चौधरी देवी लाल के घर पर ये पैदा हुआ है। यह ठीक है और मैं मानता हूं लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। * * * *** ****

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, जो शब्द ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है इसलिए आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवाने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो शब्द कहें हैं वे रिकार्ड न किये जाएं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, इन लोगों की जितनी निन्दा की जाए वह कम है। आप जानते हैं कि हाउस का समय कितना कीमती है उसको इस प्रकार से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। आपको इस बारे में स्टैप पहले ही लेने चाहिए थें। स्पीकर सर, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इनको सदन से निकालना भी ठीक बात नहीं है। उनको यहीं पर बैठे रहने देते ताकि उनके ऊपर जो-जो आरोप लग रहे हैं वे एक-एक आरोप को सुनते और उन आरोपों का जवाब यहां पर हाउस

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

में देते। वैसे तो जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं है इसलिए के शोर-शराबा करके सदन से बाहर भाग जाते हैं। चौधरी कर्ण सिंह दलाल ने शुरू वाले दिन जो बातें कहीं थी और जो आरोप लगाए थे उन्होंने उनकी किसी बात का आज तक कोई जवाब नहीं दिया । उन्होंने इस तरह की बात करके यहां से भागने की कोशिश की है और अपने अभद्र व्यवहार से सदन का समय भी बर्बाद किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार की बात हाउस में सहन नहीं होनी चाहिए। और उनके इस अभद्र व्यवहार की निन्दा की जानी चाहिए। इस सदन से इनको बाहर न निकाल कर यहीं पर उन सबको बुलाना चाहिए। ताकि पूरे प्रदेश की जनता को पता लगे कि किस प्रकार से झूठ बोल कर इन्होंने प्रदेश के संसाधनों को लूटा है। यह सारी बातें यहीं पर बैठकर सब के सामने स्पष्ट होनी चाहिएं थीं।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस का अनमोल समय बर्बाद हुआ और बर्बाद किया गया है। इनैलो पार्टी द्वारा सदन में इतना शोर मचाया गया कि सदन में जो बिल पास हो रहे थे उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चला कि किस वक्त कौन सा बिल पास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन में सभी सदस्य जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह व्यक्ति भारत में दुनिया के सबसे बढ़िया से बढ़िया डाक्टरों को छोड़ कर अमेरिका के डाक्टरों से दो साल तक ईलाज करवा कर आया है, उनसे सदन में यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह हमारा साथ देगा। अध्यक्ष महोदय, वे प्रैस में अपनी बात छपवाने के लिए सदन में शोर शराबा करके चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी सदस्यों से निवेदन है कि कल जब वे सदन में आएं तो 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट सदन में उनको उनकी बात बोलने दें और साथ में उनको यह भी कह दिया जाए कि वे सदन के सभी सदस्यों की बात सुनने की हिम्मत भी रखें।

Mr. Speaker : Question is—

> That this House condemns the conduct of the members of the Indian National Lok Dal as also their behaviour in which, they in an organized and designed manner, disrupted the proceedings of the House.

The motion was carried.

Unanimously.

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष एक और प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यूनाईटिड प्रोग्रेसिव अलायंस की केन्द्र की सरकार ने गेहूं के न्यूनतम भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल और बढ़ाए हैं। अब गेहूं का न्यूनतम मूल्य 850 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यह 100-100 रुपए की दो बार बढ़ोतरी हिन्दुस्तान के इतिहास में एक मुश्त बढ़ोतरी पहली बार हुई है। हिन्दुस्तान में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं लेकिन यूनाईटिड प्रोग्रैसिव अलायंस ने ही यह फैसला किया है। हां एक बार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के वक्त में 50 रुपए एक मुश्त बढ़ोतरी हुई थी। यह 200 रुपए

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

की एक मुश्त बढ़ोतरी श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और सारे यूनाईटिड प्रोग्रैसिव अलायंस के सहयोग की वजह से हुई है। इस बढ़ोतरी में हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर हाथ रहा है। इन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी को 850 रुपए का गेहूं का न्यूनतम मूल्य देने के लिए पत्र लिखा था। जिन दिनों केन्द्र में इस बारे में फैसला होना था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी मिले थे। अध्यक्ष महोदय, वह पत्र हरियाणा के रिकार्ड में आज भी दर्ज है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और उस नाते से भी उन्होंने यह काम किया है। ये मजदूरों और ग्रामीण अंचल के पक्षधर हैं और इनको उनकी बहुत चिंता थी। अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत का किसान खास करके पंजाब और हरियाणा का किसान जो सोने की शक्ल का गेहूं पैदा करता है, उसको 850 रुपए उस गेहूं का न्यूनतम मूल्य प्रति क्विंटल मिलना चाहिए ऐसी मांग हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी। मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी होती है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और भारत के प्रधान मंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने हमारे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने अपने पत्र में गेहूं के समर्थन मूल्य की जो मांग रखी थी उसे हूबहू स्वीकारा है। मैं आपकी अनुमति से सदन में एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि किसानों, मजदूरों और ग्रामीण आंचल से जुड़े लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है उसके लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया जाए। इसके साथी ही केन्द्र की सरकार ने समय-समय पर डीजल और पैट्रोल के मूल्यों में एक रुपए और 2 रुपए की कमी की है इसके लिए भी यह सदन श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और यूनाईटिड प्रोग्रैसिव अलायंस का धन्यवाद करता है।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, now, the Parliamentary Affairs Minister will move his motion.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That United Progressive Alliance has announced the increase of Rs. 100/-per quintal in the minimum support price of wheat taking the total MSP of wheat to Rs. 850/-per quintal. In this year, this is second increase in MSP of wheat by UPA Government taking the total increase to Rs. 200/- per quintal within a year.
>
> Smt. Sonia Gandhi, UPA Chairperson has her heart and soul in the problem faced by farming community, particularly, in North Indian States of Punjab and Haryana. Similar is the intent of UPA Government led by Prime Minister Dr. Manmohan Singh. It is this heartfelt feeling and deep rooted belief that has got translated into MSP of Rs. 850/- per quintal.
>
> Haryana Chief Minister, Ch. Bhupinder Singh Hooda is not only son of a farmer himself but the Chief Minister and his Government has deep rooted feeling over the interest of farmers. Chief Minister had met the Prime Minister as also the Congress President Smt. Sonia Gandhi for increase in the price of wheat by Rs. 100/-

per quintal and had demanded so by writing a letter to the Prime Minister. The Government of India has accepted the price of MSP to be fixed at Rs. 850/- per quintal as demanded by the Chief Minister, Ch. Bhupinder Singh Hooda and the present Congress Government in the State. This House resolves and records its heartfelt thanks and gratitude of the people of Haryana to Smt. Sonia Gandhi, UPA Chiarperson, Prime Minister Dr. Manmohan Singh as also UPA Government at the Centre for fixing the MSP of wheat at Rs. 850/- per quintal.

Mr. Speaker : Motion moved—

That United Prograssive Alliance has announced the increase of Rs. 100/-per quintal in the minimum support price of wheat taking the total MSP of wheat to Rs. 850/-per quintal. In this year, this is second increase in MSP of wheat by UPA Government taking the total increase to Rs. 200/- per quintal within a year.

Smt. Sonia Gandhi, UPA Chairperson has her heart and soul in the problem faced by farming community, particularly, in north Indian States of Punjab and Haryana. Similar is the intent of UPA Government led by Prime Minister Dr. Manmohan Singh. It is this heartfelt feeling and deep rooted belief that has got translated into MSP of Rs. 850/- per quintal.

Haryana Chief Minister, Ch. Bhupinder Singh Hooda is not only son of a farmer himself but the Chief Minister and his Government has deep rooted feeling over the interest of farmers. Chief Minister had met the Prime Minister as also the Congress President Smt. Sonia Gandhi for increase in the price of wheat by Rs. 100/- per quintal and had demanded so by writing a letter to the Prime Minister. The Government of India has accepted the price of MSP to be fixed at Rs. 850/- per quintal as demanded by the Chief Minister, Ch. Bhupinder Singh Hooda and the present Congress Government in the State. This House resolves and records its heartfelt thanks and gratitude of the people of Haryana to Smt. Sonia Gandhi, UPA Chiarperson, Prime Minister Dr. Manmohan Singh as also UPA Government at the Centre for fixing the MSP of wheat at Rs. 850/- per quintal.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, यह सच बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरेन्द्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और पर्सनली हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमती सोनिया जी से और प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। मैंने भी आल इंडिया किसान यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते गेहूं के समर्थन मूल्य को 100/- रु० प्रति क्विंटल बढ़ाने के लिए उनको कई बार चिट्ठिया लिखी हैं। सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा कि हरियाणा के किसान के लिए, पूरे देश के किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए, ग्रामीण भाईयों के लिए और गरीब भाईयों के लिए जो पीड़ा उनके मन में है उसके लिए वह इससे फालतू कुछ और

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

नहीं कर सकतीं कि उन्होंने पिछले डेढ़ दो साल के सरकार के कार्यकाल में ब्याज की दर 14 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत करवायी है। लेकिन हरियाणा की सरकार दिल्ली से पैसा आने के पहले ही यह रियायत अपने किसानों को दे चुकी है उन्होंने किसानों के लिए जो फैसले लिए हैं वह काबिलेतारीफ हैं। सौ रुपये उन्होंने पहले बढ़ाए थे। पचास रुपये धान की फसल में भी उन्होंने एक साल में बढ़ाए थे और अब सौ रुपये और उन्होंने किसानों को बोनल के रूप में दिए हैं। स्पीकर सर, मैंने भी इस बारे में उनको चिट्ठियां लिखीं थीं। मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे सौ रुपये बोनस के रूप में मांगे थे। जो कि उन्होंने दिए हैं; यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता था कि 50 रुपये तो बढ़ेंगे ही, 100 रुपये नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो 100/-रुपये बढ़ गए है वह काबिले तारीफ है। स्पीकर सर, मैं फिर इसके लिए सरकार को मुबारिकबाद देता हूं और श्रीमती सोनिया गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने किसान हितेषी फैसला लिया।

Mr. Speaker : Question is—

That United Progressive Alliance has announced the increase of Rs. 100/-per quintal in the minimum support price of wheat taking the total MSP of wheat to Rs. 850/-per quintal. In this year, this is second increase in MSP of wheat by UPA Government taking the total increase to Rs. 200/- per quintal within a year.

Smt. Sonia Gandhi, UPA Chairperson has her heart and soul in the problem faced by farming community, particularly, in north Indian States of Punjab and Haryana. Similar is the intent of UPA Government led by Prime Minister Dr. Manmohan Singh. It is this heartfelt feeling and deep rooted belief that has got translated into MSP of Rs. 850/- per quintal.

Haryana Chief Minister, Ch. Bhupinder Singh Hooda is not only son of a farmer himself but the Chief Minister and his Government has deep rooted feeling over the interest of farmers. Chief Minister had met the Prime Minister as also the Congress President Smt. Sonia Gandhi for increase in the price of wheat by Rs. 100/- per quintal and had demanded so by writing a letter to the Prime Minister. The Government of India has accepted the price of MSP to be fixed at Rs. 850/- per quintal as demanded by the Chief Minister, Ch. Bhupinder Singh Hooda and the present Congress Government in the State. This House resolves and records its heartfelt thanks and gratitude of the people of Haryana to Smt. Sonia Gandhi, UPA Chiarperson, Prime Minister Dr. Manmohan Singh as also UPA Government at the Centre for fixing the MSP of wheat at Rs. 850/- per quintal.

The motion was carried.

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget Estimates for the year 2006-07 will take place.

श्री के0एल0 शर्मा (शाहबाद) : स्पीकर सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सर्वप्रथम मुझे बजट डिबेट में हिस्सा लेने का मौका दिया। स्पीकर सर, अभी मेरे सभी साथियों ने इस बात की सराहना की कि किस प्रकार से सामने बैठे हुए व्यक्तियों के किरदार को आपने साफ किया। सर, इतना ही नहीं मैं दो बातें इसमें और जोड़ना चाहूंगा। आपने बहुत ही स्वस्थ परम्परा कायम की है। जैसे अभी बताया गया कि अब से पहले जब डिसकशन होती थी तो विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। डिबेट के बीच में और प्रस्ताव पास होने के बीच में विपक्ष को कोई समय ही नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे इस पूरे सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति एक दो इकोनोमिस्ट को छोड़कर, इतना सक्षम नहीं है कि जो बजट को बिना पढ़े उस पर अपने विचार व्यक्त कर सके, उस पर अपनी राय दे सके और उसकी मदों के बारे में बोल सके। स्पीकर सर, आपने तीन दिन का समय इसकी तैयारी के लिए दिया। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी पदासीन हुए)** चेयरमैन सर, चाहे वह महामहिम के अभिभाषण की बात हो या चाहे दूसरे विषयों पर बोलने की बात हो, अध्यक्ष जी आपने पूरा मौका बोलने के लिए दिया है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय बधाई के पात्र हैं। चेयरमैन सर, अभी आप अपनी पहले वाली चेयर से बोलते हुए फरमा रहे थे कि किसके लिए निंदा का प्रस्ताव लाया जाए, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनके लिए आपने कहा कि उनको यहीं पर बिठाना चाहिए था और उनको बजट पर बातें करने देनी चाहिए थीं। चेयरमैन सर, बहुत ही बढ़िया बजट पेश हुआ है, इसी बात की तो उनको तकलीफ थी इसीलिए वे यहां से भागना चाह रहे थे। इतना अच्छा बजट पेश हुआ कि इसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय, वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिन-रात मेहनत करके इस बजट का प्रारूप तैयार किया और वित्त मंत्री ने इस बजट को इतने सुन्दर तरीके से पेश किया। चेयरमैन सर, जहां तक इस बजट का सवाल है, जब हम बजट की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा ही केवल देखी जाती है। इकोनोमिक्स के हिसाब से केवल इसकी परिभाषा इतनी ही है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत हम स्टेट की बड़ी से बड़ी राशि किसी कार्य या परिकार्य के लिए एक समय के लिए नियत करते हैं और वह समय ज्यादातर एक साल का होता है। लेकिन यदि हम किसी प्रक्रिया की बात न करें और राजनीति के अनुरूप इसको देखा जाए तो मैं समझता हूं कि राजनीति में राजनीतिज्ञों का यह मत है कि यह जो बजट है यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा टूल है जिसके तहत सरकार विधायिका के सहयोग और अपनी कार्यकुशलता के बारे में जनता को एक मैसेज देती है। जहां तक मेरी अपनी पर्सनल सोच का सवाल है। ये एक विधायक का, सरकार का और खास कर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का सालाना इम्तिहान है। इस इम्तिहान की मार्किंग जनता करती है। स्पीकर सर, पहले लेखानुदान पेश हुआ और उसके बाद पहला बजट पेश हुआ, उसके बाद दूसरा पेश हुआ और अब तीसरा पेश हुआ है। तीनों की मार्किंग की गई और तीनों के लिए मार्कशीट दी, पहले जींद की रैली में, दूसरी हिसार में और तीसरी सिरसा की रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर दी। सिरसा के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने अपने व्हीकल लाकर, अपने पैसे खर्च करके और

[श्री के०एल० शर्मा]

अपना खाना साथ लाकर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह एक ऐसी मार्क शीट थी जिस पर मुझे एक बात याद आती है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद बाहर पढ़ा करते थे। वे हमेशा फर्स्ट आते थे तो वहां के लोग उनसे जलन महसूस करते थे कि हर बार बाहर से आकर हमारे यहां के लोगों से फालतू नंबर ले जाता है। उनमें से किसी ने उनके साथ एक दिन शरारत की और शरारत यह की कि उनकी घड़ी आधा घंटा पीछे कर दी जिसकी वजह से वे पेपर देने आधा घंटा लेट पहुंचे और उनको तीन की बजाय ढाई घंटे परीक्षा के लिए मिले। जिन्होंने यह शरारत की थी उनके मन में यह बात थी कि इस बार डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद हमारे यहां के आदमियों से आगे नहीं निकल पाएंगे। सभापति महोदय, कर्मयोगी का आवेग कभी रुकता नहीं है। जब उनके पर्चे देखे गए जो कि उन्होंने लेट समय में सौल्व किए थे, जब ऐग्जामिनर उनको लेकर बैठा तो उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि यह आंसर सीट नहीं है this is not an answer sheet. It is an explosion of knowledge. I can't give any marks to him. Examinee is better examiner और वहां आज भी इस बारे में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सिरसा रैली के अंदर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के मैसेज दिया है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता एकमत से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार के साथ है। अभी मेरे साथी जिनकी बात कर रहे थे कि वे भाग क्यों जाते हैं। भाग नहीं जाते हैं। शुरू-शुरू में इन्होंने एक बात कही थी। कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा नौसिखिया व्यक्ति हैं। ये कहा करते थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो व्यक्ति चुनावी वादे पूरे करने की बात करता है वह नौसिखिया होता है। इनकी ऐसी सोच है। वे यहां बैठे व्यक्तियों को फेस नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने सोचा था कि कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी, सरकार की कुछ खामियां और कमियां सामने आएंगी जिनको वे यहां उजागर करेंगे मगर उन्हें ऐसा भी कोई मौका नहीं मिला। सिरसा रैली में जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सरकार को जो मार्कशीट इशू की उसे देखकर ये लोग घबरा गए। इनकी ऐसी करतूतों पर हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति से राज छिन जाता है और जनता उसको कुर्सी के नजदीक फटकने नहीं देती तब यह व्यक्ति बौखला जाता है और उस की यही हालत होती है। जो इन लोगों की हुई है। मुझे इन पर तरस भी आता है और ऐसे व्यक्ति के आचरण पर शर्म भी आती है जो बाहर बैठकर अपने साथियों से यह कहता है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना। वह व्यक्ति हाउस के अंदर आकर ऐसी बात करता है कि हमने यह बात पूछी थी कि ये लोग ऐसा किरदार किसको सिखा रहे हैं। मैंने पहले सैशन में भी यही बात कही थी कि यह हाउस है, कोई चंडूखाना नहीं है। चेयरमैन सर, आपने सही फरमाया था कि जिसके पिताश्री खुद यह कहते हों कि यह मेरा पुत्र नहीं है तो उसके बाद उसके और गुणों का बखान करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ये वहां से भाग गये थे। सिरसा रैली में क्या हुआ था जो ये दुखिया गये थे। सिरसा में उमड़ी जनता को देखकर इनको ऐसा लगा कि आगे आने वाले समय में हम अपनी सरकार लाने में कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने एक मतर्बा चार हजार करोड़ रुपये के कर्जे के ब्याज माफ करने की बात कही उस बात को सुनने की बात तो दूर जिन व्यक्तियों ने 1700 करोड़ के बजट की संख्या को कभी पार न किया हो उनके समक्ष ही लोगों के 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों के माफ कर दिए और चार हजार करोड़ रुपये कर्जे के ब्याज के माफ कर दिए जाऐ तो वे व्यक्ति क्या महसूस करेंगे। सरकार की ऐसी कारगुजारी देखने से क्या वह आदमी अपने आपको रोक सकता है। वे यहां सदन में यह बात देखने के लिए आये थे कि 1700 करोड़ रुपये के बजट से 5300 करोड़ रुपये

के बजट पर यह सरकार कैसे पहुँच गयी ? वे इस बात को जानना चाहते थे। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि वे लोग हाउस में नहीं हैं। अगर वे माननीय सदस्य सामने बैठे होते तो अच्छा होता और उनको पता चल जाता कि सरकार की इस सफलता के पीछे क्या बात थी और जनता की उनके प्रति नाराजगी की क्या बात थी। मैं उन माननीय सदस्यों से एक क्वैश्चन पूछना चाहता था कि सरकार की इस सफलता के पीछे क्या कारण थे लेकिन वे माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं और कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 1992-1997 में जब नौंवी पंच वर्षीय योजना पास हुई थी वह 11600 करोड़ रुपये की पास हुई थी। उसमें 7986 करोड़ रुपये खर्च हुए जोकि कुल पैसे का 68.94 प्रतिशत बनता है। उस खर्चे को देखकर जब दसवीं प्लान में हमारी सरकार को केवल 12000 करोड़ रुपये मिले जोकि प्रत्येक साल के 2400 करोड़ रुपये बनते हैं। आपको याद होगा कि जिस व्यक्ति ने तीन बजट पेश किए हों उसके बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पहले वर्ष के लिए बजट था 2400 करोड़ रुपये जिसमें से केवल 2034 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदन करवाया गया। उसके बाद 1816.44 रुपये का संशोधन करवाया गया उस पैसे में से खर्चा कितना किया केवल 1776.19 करोड़ रुपये । चेयरमैन सर, वर्ष 2002-2003 में कुल 2091 करोड़ रुपये का अनुमोदन करवाया और उसके बाद संशोधन करवाया 1850 करोड़ रुपये का। खर्चा किया गया 1865 करोड़ रुपये। जबकि हर साल का बजट 2400 करोड़ रुपये होता था। जब इन्होंने तीसरा बजट पेश किया उसकी यह बड़ी भारी डींग मारते थकते नहीं थे। इस सदन में इन्दौरा साहब छाती ठोंक कर कहा करते थे कि हर बार जब सरकार बजट की बात करती है तो हमारे बजट की बात करती है। हमारी सरकार द्वारा दिए गये फिगर्ज की सराहना करती है। अगर आज वे सदन में बैठे होते तो मैं उनसे पूछता कि आपका तीसरा बजट 2108 पर खत्म हो गया अगर तीनों सालों का बजट जोड़ लिया जाए तो यह कुल 5749.44 करोड़ रुपये बनता है तीन साल की इसकी परसैंटेज बनती है 79.85 प्रतिशत जबकि उनकी यह योजना 9500-9600 करोड़ रुपये पर खत्म होती। हमारे वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे नहीं हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। यह बात माननी पड़ेगी कि हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की यह डॉक्टरी नहीं बल्कि जगलरी है कि कैसे उन्होंने बजट को मैनेज किया । वे 3000 करोड़ रुपये का परिव्यय सैंक्शन करवा कर लाये इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। उसके बाद अगले बजट में उस बजट को 3095 करोड़ तक पहुंचाया और वित्त मंत्री जी ने जो अगला बजट पेश किया वह 3300 करोड़ रुपये का पेश किया। उस समय इन्दौरा जी ने यह कहा था कि दस प्रतिशत की इन्क्रीज भी कोई इन्क्रीज होती है। पिछली इन्क्रीज 34-35 प्रतिशत थी अगर आप उसे देखें तो हमारी सरकार 42 प्रतिशत तक की इन्क्रीज करके लाई है। उस समय इन्दौरा जी ने कहा था कि अगली बार भी इतना ही बजट लाते तो हमें खुशी होती। आज अगर इन्दौरा जी यहां पर बैठे होते तो मैं उनको बताता कि किस प्रकार बजट को 3300 करोड़ रुपये से 4096 करोड़ रुपये पर लेकर गये हैं। उसके लिए आज उनका क्या कथन है। समापति महोदय, उसके साथ ही साथ जब यह देखा कि दोनों सालों का हमारा परसैंटेज, दो सालों का केवल टोटल जब लगाते हैं इनका तो है तीन साल का 79.85 हमारे दो साल का है 147.64 प्रतिशत 164 प्रतिशत पांच साल का खर्चा हम दो साल में करते हैं। सभापति महोदय, तीन साल में इनका 79 प्रतिशत खर्चा है लेकिन ये लोग फिर भी कहते हैं कि स्पीड नहीं थी मजा नहीं आया, इनको कैसे मजा आयेगा। इनको तो पता ही नहीं स्पीड क्या होती है। इनके पास कोई कार्य करने की बात नहीं

[श्री के०एल० शर्मा]

है, इनके पास कुछ कहने की बात नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य सदन में अपनी बात कहने लगता है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं और उल्टी बातें करने लगते हैं। सभापति महोदय, इनका नेता पीछे वालों को कह कर आता है कि मैं जैसे ही खड़ा होऊँ तुम शोर मचाने लगना, नारे लगाने शुरू कर दे ना ताकि मुझे नेम कर के सदन से बाहर निकाल दिया जाये और मैं सदन की कार्यवाही में भाग न लेने पाऊं। सभापति महोदय, अब इनका नेता बीमारी का बहाना भी नहीं बना सकता लेकिन कोई न कोई दूसरा बहाना बनाकर सदन से उनको भागना होता है। ये लोग बहाना बना लेते हैं और सदन से नेम होकर चले जाते हैं। सभापति महोदय, आप जब अपनी सीट पर बैठे थे। तब आपने ठीक फरमाया था कि इनको नेम न करो। इनको सदन में बिठाओ और सुनाओ कि इन्होंने किस प्रकार से इस प्रदेश का बेड़ा गर्क किया वे सारी बातें सामने आनी चाहिएं। इनको पता लगना चाहिए कि इन्होंने अपने समय में क्या किया है। सभापति महोदय, दुख की बात यह है कि ये सब करने के बाद इन्होंने सुना कि 14 हजार करोड़ अधिक का खर्चा करने के बाद 35 हजार करोड़ रुपये की अगली पंचवर्षीय योजना लेकर आना भारत वर्ष में यह पहली मिसाल होगी। मैं कहता हूं कि इस कार्य के लिए प्रदेश की जनता को,एक-एक नागरिक को हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने बताया था कि विपक्ष के साथियों में डा० इंदौरा जी और डा० सीता राम जी दो सदस्य पढ़े लिखे हैं जो डाक्टर हैं। इन दोनों ने जब बजट पढ़ा तो उनको मन ही मन लगा कि इस शानदार बजट के लिए वे वित्तमंत्री जी को बधाई दें और जैसा कि आपने बताया उन्होंने वित्तमंत्री जी की सीट पर आकर उन्हें बधाई दी भी है। सभापति महोदय, आपने ओरियन्टेशन प्रोग्राम चलाने के बारे में भी कहा था जिससे विपक्ष के साथी कुछ सीख सकें। मैंने पहले भी बोलते हुए बताया था कि ओरिएन्टेशन क्लासिज लगाई गई थीं जिनमें माननीय वित्तमंत्री जी ने, बत्तरा जी ने और हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने लैक्चर दिये थे सारा कुछ सिखाने के बाद जब इनसे पूछा गया कि अब तो आप ठीक ढंग से सदन में बिहेव करोगे तो इंदौरा जी ने मुस्कराते हुए यह बात कही थी जो मैंने नोन आफिशियल डे वाले दिन बोलते हुए भी बताई थी। कि पतनाला तो वहीं बहेगा, उनके अपने बस की बात नहीं है। पीछे से उनको जो हिदायतें मिलती हैं उसी हिसाब से वे चलते हैं। जैसे जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। सदन में ठीक व्यवहार करना उनके बस की बात नहीं है। उनमें जितनी चाबी उनके नेता द्वारा भरी जाती है। उतना ही वे चलते हैं। उससे ज्यादा चलने की उनकी हिम्मत नहीं है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी बजट का धरातल रैवेन्यू रिसीटस होती हैं। पिछली सरकार के समय में वर्ष 2001-02 में 7600.55 करोड़ रुपये की 2002-03 में 8657.02 करोड रुपये की और वर्ष 2003-04 में 9843.84 करोड़ रुपये की रैवेन्यू रिसीट्स थी। इनमें हर साल बढ़ौतरी केवल पहले वर्ष 1056.47 करोड़ रुपये की, दूसरे वर्ष 1186.46 करोड़ रुपये और तीसरे वर्ष 1305.58 करोड़ रुपये की थी। लेकिन अगले वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आई तो रैवेन्यू रिसीट्स 1385.31 करोड़ रुपये हो गई और एक साल में ही इनमें 2704.25 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी हुई जो कि डबल से भी ज्यादा बनती है। उसके बाद अगले साल इनमें 2100 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी हुई और उससे अगले साल 2000 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी हुई। सभापति महोदय, मेरे पास हमारी सरकार के समय का भी तीनों बजटों का रिकार्ड है जो मैं देखकर सदन को जानकारी दे रहा हूं। इससे पता चलता है कि what has happened with the fall of the hammer कि एक

हथोड़ा गिरने के with a twinkling of eyes क्या हुआ। what happened over their कोई जगलरी हुई। इन बातों के लिए सरकार को बधाई देना तो दूर की बात थी वे तो सदन से ही निकल गये। सभापति महोदय, जो बजट वित्तमंत्री जी ने पेश किया है। यह हरियाणा में ही नहीं बल्कि भारत वर्ष में भी एक मिसाल है। सभापति महोदय, उसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हू और मैं सारा ब्यौरा बताना चाहता हूं। ये लोग कहते थे कि अगर अच्छी बात करोगे तो हम सराहना करेंगे। सराहना करना हो दूर की बात है सर इन्होंने अखबार में ब्यान दे दिया कि यह जो कांग्रेस सरकार अपनी पीठ ठोंक रही है कांग्रेस सरकार कह रही है कि गेहूं के मूल्यों में बढ़ोतरी हमने की है उसके पीछे कहानी कुछ और है और ये लोग यह कहानी बताते हैं और कहते हैं कि वैट हमने लगाया था। चौटाला साहब ने कहा कि सरपल्स बजट हमेशा ही विकास के रास्ते में रोड़ा होता है। उनके कहने के मुताबिक नोन प्रोग्रैसिव बजट गलत बजट माना जाता है। ऐसा प्रदेश की सरकार की अकुशलता को भी प्रदर्शित करता है जिससे स्पष्ट है कि सरकार के पास धन उपलब्ध होने के बावजूद धन को विकास के कामों में खर्च करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। समापति महोदय, उनकी बात सुनकर मुझे शर्म आती है। ये लोग कहते हैं कि यह घाटा क्यों हुआ। ये रैवैन्यू डैफिसिट की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी, 2005-06 का बजट जब आपने पेश किया था तो आपको याद होगा 948 करोड़ रुपये का हमारा घाटा था और उस वक्त इन्होंने खड़े हो कर यही बात कही थी आज वे हाऊस से बाहर चले गये हैं। अगर वे यहां होते तो मैं उनको बजट पढ़कर सुनाता। उस वक्त डॉ० इन्दौरा जी ने कहा था कि यह सरकार बेड़ा गर्क करने जा रही है। 948 करोड़ रुपये के जिस घाटे को कम करके हम 258 करोड़ के ऊपर लाये थे उसको इन्होंने 948 करोड़ कर दिया है। इसे इन्होंने उस वक्त हमारा माईनस प्वाइंट बताया था। जब हम बजट को सरपलस में लेकर आये हैं तो इनके पहले कहने के मुताबिक तो हमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन फिर भी चौटाला जी को यही लगता है कि बजट का सरपल्स होना गलत है। यह तो वही बात हुई कि चित्त भी इनकी और पट भी इनकी । अगर हम घाटे को कम करते हैं तो ये कहते हैं गलत है और अगर बजटीय घाटा बढ़ता है तो भी ये कहते हैं कि गलत है। चेयरमैन सर, इनको बजट के बारे में पता ही नहीं है कि बजट किस चिड़िया का नाम है, इनको बजट की बातों का कुछ पता ही नहीं है। बजट पर बात करना इनके बस की बात ही नहीं है। इनकी तो हर बात पर ऐतराज करने की आदत है मुझे पंजाबी की एक बात याद आती है :

किसे ने ईंट उखाड़ी तो मजहब नूं खतरा,
किसे ने बन्नी दाढ़ी ते मजहब नूँ खतरा,
किसे ने लाई साड़ी ते मजहब नूँ खतरा,
ऐ मजहब न होया, होई मोमबत्ती,
पिंघल गई फौरन लगी धूप तत्ती।

चेयरमैन सर, इनके बस की कोई बात ही नहीं है। इनके जो नुमाइन्दे हैं जो लोग उनको पसन्द करते हैं वहां के लोगों की कोई मजबूरी रही होगी। जो ऐसे व्यक्तियों को चुनकर भेज दिया। आज मैं बहुत सी बातें बताना चाहता था। लेकिन आज तो माहौल ही ऐसा हुआ कि मेरा सारा जोश ठण्डा हो गया। चेयरमैन सर, मैं बहुत सारी बातें लेकर आया था। साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और कही। ये लोग हर बार यह बात कहते हैं और खास करके प्रैस में भी कहते हैं कि वैट हमने लगाया था। स्पीकर सर, मैं वैट के कागज भी लाया हूं। इन्होंने यह बात कही थी कि वैट

[श्री के०एल० शर्मा]

हमने लगाया है जिसकी वजह से हमारा रेवैन्यू बढ़ रहा है। चेयरमैन सर, मेरे सामने लाकर उनकी बात करवाओ क्योंकि मैं उनके सामने बात करना चाहता हूं। मैं एक बिजनैसमैन हूं मुझे भी बजट का थोड़ा बहुत ज्ञान है। मुझे बजट बनाना आता है। जहां पर वैट सबसे पहले लगा वैट के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी इकनोमिक कम्पनी का सर्वे है। वे लोग बैठे नहीं हैं नहीं तो मैं उनको एक-एक चीज पढ़कर बताता। वैट सबसे ज्यादा अगर किसी को गलत इफैक्ट करता है। तो वह गरीब आदमी को करता है। इस पर पैनी नजर रखने और इसे सुधारने की जरूरत है। गरीब आदमी को कैसे लगता है क्योंकि गरीब आदमी 100 रुपये कमाता है तो उसके 100 के 100 खर्च हो जाते हैं और अगर एक आदमी 5 लाख रुपये कमाता है और वो 50 हजार खर्च करता है तो उसको 10 परसेंट पर वैट लगा और गरीब आदमी को 100 परसेंट आमदनी पर लगता है। चेयरमैन सर, यह वैट जीवन स्तर को कहां लेकर जाएगा। वैट से 100% गरीब लोगों पर मार पड़ेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कहां था कि rate of VAT should be reduced. वैट लागू करने से पहले आपको पहचानना होगा कि उस गरीब की जरूरत की वस्तुएं क्या हैं। गरीब के घर में जो छोटी-छोटी चीजें हैं जिनके बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता वैट लगने से वे चीजें उसकी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। गुड, तेल, चीनी जैसी छोटी-छोटी वस्तुएं हैं जिनके बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। यहां तक कि यदि वैट के रेट को रिडयूस भी कर दें तो भी गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है। हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने पिछली बार उनको यही जवाब दिया था और यह कहा था कि हमने कभी वैट का विरोध नहीं किया था बल्कि हमने वैट इन आईसोलेशन लगाने का विरोध किया था। चेयरमैन सर, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में देश या प्रदेश के अन्दर बनाता है तो जनरली वह क्या करता है उसके ऊपर 10% टैक्स लगाता है और उसको 110 रुपये का टैक्स पेड करके बेच देता है। चेयरमैन सर, हमारे साथ लगते राज्य पंजाब में टैक्स नहीं VAT is not in Punjab. जबकि हमारे हरियाणा में वैट लगा हुआ है चण्डीगढ़ में वैट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में वैट नहीं है। हमारा यहां का जो प्रोडयूसर है, हमारा यहां का जो बिजनैसमैन है वह 100 रुपये का प्रोडक्ट 110 रुपये में नहीं बना पाएगा; वह प्रोडक्ट बिकते-बिकते जब आखिरी व्यक्ति के पास जाएगा तो यह वैल्यू ऐडिड टैक्स उसकी वैल्यू के साथ उसमें जुड़ता चला जाएगा। जब कन्जयूमर के पास वह प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उसे 50 रुपये ऐडीशनल टैक्स के देने पड़ेंगे और दूसरे को वहां पर टैक्स के 10 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि दूसरी जगह पर वैट लगा हुआ नहीं है। चेयरमैन सर, ऐसी स्थिति में मार्किट के अन्दर हमारे उस प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा। समापति महोदय, यह टैक्स स्टेट की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू नहीं किया गया था बल्कि यह टैक्स बिजनैसमैन से बदला लेने के लिए लागू किया गया था। जब पार्लियामैंट का चुनाव हुआ था तो इस टैक्स के कारण लोगों में इतना रोष था कि लोगों ने इनके दोनों बेटों को चुनाव में हरा दिया था। इनकी एक ऐसी छवि बन गई थी कि इस सदन में खड़ा होकर कहते हुए भी शर्म आती है। चेयरमैन सर, स्कूलों में एक क्विज़ टैस्ट होता था। आठवीं के एक स्कूल में मैं चीफ गैस्ट बनकर चला गया और वहां पर क्विज के दौरान मैंने स्कूल के एक बच्चे से सवाल पूछ लिया कि हरियाणा सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं। मुझे आठवीं के बच्चे से जवाब मिलता है कि दो मोटे-मोटे बेटे और एक लंगड़ा सा बाप। चेयरमैन सर, आप अन्दाजा लगाइये कि उस वक्त सरकार की क्या छवि थी। इस प्रकार की इनकी छवि बन गई थी कि लोग इनको इस नाम से पहचानने लगे थे। चेयरमैन सर, क्या उस वक्त प्रदेश के अन्दर

कोई सरकार थी उस वक्त प्रदेश में जो सरकार थी वह केवल तीन व्यक्तियों की सरकार थी यानि दो मोटे बेटों और एक बाप की सरकार थी। इनके जो मन में आता था। वे लोग किया करते थे। जो मन में आता था वे फैसला ले किया करते थे। ऐसे ही मन में आया तो वैट भी लागू कर दिया। अभी आपने देखा नहीं कि पीछे लोग बैठे हुए हैं और कहने लगे कि 54 मिनट का समय मेरी पार्टी का है और यह सारे का सारा वक्त मैं लूंगा। चेयरमैन सर, क्या वह खुदाई फौजदार है। लोगों का टाईम लेने से पहले कम से कम इन्हें अपने लोगों से पूछना तो पड़ेगा। किसी ने अपने हल्के की बात कहनी है किसी ने कोई समस्या उजागर करनी है या किसी के मन में कहने के लिए कोई बात होती है तो 54 के 54 मिनट अकेला आदमी लेगा, इस बात का क्या मतलब है। चेयरमैन सर, आपने बहुत अच्छा किया, आपने यह फैसला लिया कि नहीं हरेक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है और सभी मैम्बरों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप बार-बार उनको टोक रहे थे, हमारे ये बैठे हुए भाई इस बात पर हंस रहे हैं। यह बात ठीक थी, जब वे नहीं आते तो उनके लोग मानसिक रूप से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि जब वे यहां पर आ जाते हैं तो उनके मैम्बरों के हकों का हनन होता है। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि उनके अपने सदस्य भी उनके हाउस में न आने से खुश रहते हैं। चेयरमैन सर, जब बजट बनता है तो सबसे पहले वित्त मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस बात पर होता है कि मानव मूल्यों को नजर में रखा जाए। जो पहली मद आप बजट में लेते हैं वह मानव मूल्यों की है। मानव मूल्यों की मद क्या होती है, अभी अभी बताया जा रहा था। चेयरमैन सर, पिछली बार जब हम चुन कर आए थे तो अभी चार दिन भी नहीं हुए थे तो फील्ड से खबर आई थी कि प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है। जब ओलावृष्टि का सर्वे करवाया गया तो माननीय वित्त मन्त्री जी आपको मालूम है कि जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने देखा कि किसान के हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी तो 50% गेहूं के ऊपर और बाकी की फसलों पर भी 50% मुआवजा बढ़ा कर एक ऐसा आयाम कायम किया था जिससे यह पता लगता था कि मुख्य मन्त्री जी तथा वित्त मन्त्री जी की नीयत क्या है। चेयरमैन सर, इन्होंने एक घटना के बारे में कहा।

श्री सभापति : शर्मा जी, आप बजट पर बोलें। वित्तमंत्री जी ने बजट में क्या क्या दिया है उसके बारे में बताएं।

श्री के०एल० शर्मा : चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौटाला साहब की जब सरकार थी तो उस वक्त उनके वित्तमंत्री ने वर्ष 2003-04 का जो बजट पेश किया था उसमें वे अपनी स्पीच में कहते हैं कि यह वित्त वर्ष एक ऐसे दु:खद हादसे के साथ समाप्त होने जा रहा है जिसने न केवल हमारे राज्य व देश को, अपितु समूचे विश्व को एक गहरा आघात पहुंचाया है। पहली फरवरी, 2003 को अन्तरिक्ष यान कोलम्बिया टैक्सास के ऊपर आकाश में टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया और परिणामस्वरूप करनाल में जन्मी प्रथम भारतीय महिला अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत सभी सातों अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला के निधन से हमने एक बहादुर और प्रतिभावान बेटी को खो दिया है। हमें कल्पना चावला पर गर्व है। वे हमारे युवकों और युवतियों के स्वप्नों को साकार करने में उनके लिए प्रेरणास्त्रोत बनी रहेंगी। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हरियाणा की इस साहसिक बेटी की स्मृति में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से करनाल में एक मैडिकल कालेज तथा कुरूक्षेत्र में एक नक्षत्रशाला स्थापित करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने कल्पना चावला की याद में

[श्री के०एल० शर्मा]

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, अम्बाला का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार सहित कल्पना चावला मैमोरियल गोल्ड मैडल शुरू करने का भी निर्णय लिया है, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली दसवीं की परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इनकी स्मृति में राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पहले पांच स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को 2000 रुपए प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाएगी। चेयरमैन सर, आज मैंने वित्तमंत्री जी और टैक्नीकल एजुकेशन मंत्री जी से पूछा था कि क्या इस समय इस तरह की कोई छात्रावृत्ति चल रही है तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं चल रही है। केवल एक काम उनकी सरकार ने किया था कि अम्बाला में पोलिटैक्नीक कालेज का नाम कल्पना चावला पोलिटैक्नीक कालेज रखा था। चेयरमैन सर, वे वही काम करते रहे हैं। जिनमें उनका एक पैसा भी नहीं लगता है। आज वे सदन में बजट की बात करते हैं। चेयरमैन सर, वे 54 मिनट समय लेना चाहते हैं, वे हर बार यही बात कहते हैं कि मुझे एस०वाई०एल० नहर पर बात कहनी है। चेयरमैन सर, चेयर की तरफ से जब एक रूलिंग आ गई कि एस०वाई०एल० नहर से सम्बन्धित कोई बात सदन में नहीं की जा सकती है क्योंकि यह मामला सब-ज्यूडिस है। लेकिन फिर भी वे बार-बार यही बात दोहराते रहते हैं। चेयरमैन सर, मैंने उनके शासन काल की 3 साल की प्रोसीडिंग पढ़ी है। दो साल तो इस बारे में उनकी तरफ से कोई जिक्र ही नहीं किया गया है और एक साल की प्रोसीडिंग में सिर्फ यही बात कही थी कि यह मामला कोर्ट के पास लम्बित है। हम सैन्टर गवर्नमैंट से एक बात कह सकते हैं कि इसको जल्दी पूरा कर दिया जाए। चेयरमैन सर, मुझे पता नहीं कि इधर पहुंचने पर अब इनकी नीयत बदल गई है या क्या हुआ है। चेयरमैन सर, इनकी तो कथनी और करनी में बहुत ही अन्तर है। चेयरमैन सर, आपकी कांस्टीचुएंसी मदीना में क्या हुआ था। उस कांड को आज कौन भुला पाया है और न ही कभी कोई उस कांड को भूल सकता है। जिन्होंने उस काण्ड को देखा था उनसे आज भी पूछ कर देखो। चेयरमैन सर, सरकार और किसानों के बीच में एक समझौता होना था और कैथल में एक मीटिंग रखी गई थी और किसान भाई वहां पर इक्ट्ठे हो रहे थे। हमारे किसान भाई जैसे शिमला गांव के पास पहुंचे तो उन पर गोलियां बरसाई गईं थीं और वहां पर रामस्वरूप नाम का एक किसान पुलिस की गोली से मारा गया था। वह मारा ही नहीं जाता बल्कि उसकी लाश को उठाकर उसकी पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट को भी बदल दिया जाता है। चेयरमैन साहब, आपको उस आन्दोलन के बारे में पता ही है। कि जब किसान गुस्से में वहां पर आये थे तो क्या हुआ था।

श्री सभापति : शर्मा जी, ये सारी बातें तो सबके सामने आयी हुई हैं इसलिए आप केवल बजट पर ही बोलें।

श्री के०एल० शर्मा : चेयरमैन साहब, बजट पर तो मैं कल बात कर लूंगा। आप मुझे कल टाईम दे देना क्योंकि मैं विपक्ष के साथियों से बजट के बारे में बातें पूछना चाहता हूं। आप चाहें तो आज किसी और को बोलने के लिए समय दे दें।

श्री सभापति : शर्मा जी, ऐसा नहीं होता। आज आप बजट पर ही बोलें। बाकी बातें आप उनसे कल ही कर लेना।

श्री के०एल० शर्मा : ठीक है सर, मैं बजट पर ही बात कर लेता हूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं बजट पर ही अपनी बात कह देता हूं । मैं वे बातें कह देता हूं जो दोहरायी नहीं गयी हैं। मैं अब लॉ एंड आर्डर की बात करना चाहता हूं। अब मैं शाहबाद की बात करता हूं दूसरी बात नहीं

करता। शाहबाद के अंदर पहले जो लॉ एंड आर्डर की स्थिति हुई उसकी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। चार दिन पहले हमारे आई०जी०, सी०आई०डी०, परमवीर राठी और दूसरे अधिकारियों ने हमारे यहां पर एक साईकिल रैली निकाली थी वह रैली इसलिए निकाली गयी ताकि हमारे इलाके में पूरी तरह से नशाबन्दी हो। हमारे इलाके को नशा बेचने की धर्मस्थली कहा जाता है वहां पर स्मैक, चरस, अफीम यानी दुनिया भर का नशा होता था। जिस वक्त मैं एम०एल०ए० बना था उसके बाद एक बार हम शमशान घाट गए हुए थे वहां पर एक बुढिया ने मेरे पास आकर कहा कि शर्मा जी, परमात्मा ने आपको एम०एल०ए० बनने का मौका दिया है आपसे निवेदन है कि आप नशाबन्दी के बारे में जरूर काम करें। उसने कहा, "कि मेरे दो बेटे थे और वे दोनों की नशा करने के कारण मर गए।" चेयरमैन सर, उसने मुझसे कहा कि 'आप वायदा करें कि आप विधान सभा में जाकर इस बात को उठाओगे और नशे को बंद करवाओगे।' सर, मैंने पिछली बार भी आपसे रिक्वैस्ट की थी। मैं यह समझता था कि मेरे इलाके में पूरी तरह से नशाबन्दी हो गयी है और मैं इसके लिए बधाई भी देता था लेकिन जिस दिन यह रैली हुई उस दिन मैंने अपने एस०पी० साहब से कहा कि क्या हमारे यहां पर नशाबंदी अभी तक नहीं हुई है तो उन्होंने कहा कि 99 परसैंट तो नशाबंदी बंद हो गयी है लेकिन एक परसैंट नशाबंदी बंद नहीं हुई है। हम उस एक परसैंट को खत्म करने के लिए ही आज यह रैली निकाल रहे हैं। हम इसको बंद करने में लगे हुए हैं। इस रैली को निकालने का एक ही कारण है कि हम एक परसैंट नशे को भी बंद करना चाहते हैं। चेयरमैन सर, आप देखिए कि यह एक नीयत तो इस सरकार की है और दूसरी तरफ पिछली सरकार की नीयत थी । आप मुझे उन बातों को कहने के लिए इजाजत नहीं दे रहे हैं नहीं तो मैं आपको बताता कि उस समय क्या क्या हुआ। चेयरमैन सर, मैं बता रहा था कि इन्होंने हमारे पर इल्जाम लगाए कि रैवेन्यू किस लिए बढ़ा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि रैवेन्यू इसलिए नहीं बढ़ा कि इन्होंने वैट लगाया था बल्कि वह इसलिए बढ़ा है कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने दो साल पहले ही अपनी स्पीच में यह कहा था कि हमारी सरकार ऐसा ऐक्ट पास करने जा रही है जिसके तहत हम अपनी एफ०डीज० के बढ़े इंट्रस्ट में से छोटे इंट्रस्ट बदलेंगे। उन्होंने हमें 600 करोड़ प्लस 200 करोड़ रुपयों के होने वाले फायदे के बारे में बताया था । चेयरमैन सर, 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वह राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाए ताकि वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को कम किया जा सके और वर्ष 2009-10 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके तथा जो फिसकल डैफीसिट है उसको जी०डी०पी० के तीन परसैंट पर लाया जा सके और रैवेन्यू डैफीसिट को हम खत्म कर दें। उन्होंने इसके लिए हमें तीन चार साल का समय दिया था। चेयरमैन सर, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उन्होंने जो एफ०डीज० बदली हैं उससे हमें 1200 करोड़ रुपये का फायदा इन सालों में मिल सकता है। चेयरमैन सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रयासों से हम फिसकल डैफीसिट में उनकी सोच से बहुत आगे निकल गए हैं। वह 3 परसैंट मांगते हैं और हम 8 परसैंट पर हैं। जो उन्होंने रैवेन्यू डैफिसिट के बारे में कहा, उसमें हम सरप्लस में आ गए हैं। उसका हमें इनाम भी मिलने वाला है । अगर हम इसको पूरा करते हैं तो 1100 करोड़ रुपये का इनाम हमको फिर मिलेगा। उसको ये कैसे रोकेंगे। आज यहां पर विपक्ष के लोग बात करते हैं। उनसे 1700 करोड़ से ऊपर कभी बजट लाया नहीं गया और हम केवल 2500 करोड़ का बजट तो समाजसेवा के क्षेत्र में दे रहे हैं। चेयरमैन महोदय, अगर कल भी मुझे समय दें तो आपकी मेहरबानी होगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द-जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद शर्मा जी।

संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठौर) : चेयरमैन सर, धन्यवाद मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाए गए इस साल के शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी का जनता की तरफ से धन्यवाद करती हूं। वर्तमान सरकार ने दो साल की अल्पावधि में चहुंमुखी विकास और जनकल्याणकारी नीतियों की नई बुलंदियों को छुआ है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के ओजस्वी और कुशल नेतृत्व में जनमानस के विश्वास और उम्मीदों पर खरे उतरने का काम हरियाणा सरकार ने किया है जिससे हरियाणा के लोगों की जीवनशैली में गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का और हरियाणा को विकास की नयी बुलंदियों पर पहुंचाने का जो वादा किया था, उस पर वे खरे उतरे हैं। लोगों का लोकतांत्रिक प्रणाली और कानून-व्यवस्था पर विश्वास पुन: बहाल हुआ है। परिणामस्वरूप हरियाणा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए आर्थिक ताकत की नयी बुलंदियों को छूने लगा है। इस बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ढांचागत आर्थिक सुधार के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के लोगों की आस्था सरकार में बढ़ी है। सरकार की विकासशील नीतियों की वजह से हरियाणा में सुख-समृद्धि और विकास के नये युग का सूत्रपात हुआ है। हरियाणा सरकार ने अपने हर निर्णय में गुणवत्ता और उपलब्धियों पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्यशैली के द्वारा हरेक वर्ग को सम्मान व सुविधा प्रदान की है। मैं वित्तमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी जिनके बेहतर वित्तीय प्रबंधन की वजह से शानदार बजट प्रस्तुत हुआ है। सरकार की फिस्कल मैनेजमैंट पॉलिसी की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। इसकी प्रशंसा प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन सरदार मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने भी प्लानिंग कमीशन की बैठक में की है। ऐक्चुअल डिवैल्पमैंट ऐक्सपैंडीचर 4085 करोड़ होने की संभावना है जो अप्रूव्ड आउट-ले से 785 करोड़ ज्यादा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2011 के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का आउट-ले अप्रूव कर दिया है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हरियाणा की जनता, मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष सन् 2007-2008 में 5300 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हो चुकी है। जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। सरकार ने आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाए हैं इसके लिए वित्त मंत्री जी तथा वित्तीय प्रबन्धन से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिना कोई नया कर लगाये विकास के लिए इतना बढ़िया वित्तीय प्रबन्धन किया है। वर्ष 2006-07 के दौरान करण्ट प्राईस में जी०डी०पी० के लिए 15% से ज्यादा वृद्धि की है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री जी का हरियाणा प्रदेश को हिन्दुस्तान में नम्बर एक का प्रदेश बनाने का जो सपना है वह सपना साकार होता नजर आ रहा है। आज प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हरियाणा हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है जबकि बड़े राज्यों को अगर देखा जाऐ तो हरियाणा प्रथम स्थान पर आता है। जब यह सरकार रैवेन्यू कलैक्शन ज्यादा देती है। तो उसका नतीजा यह है कि इतना अच्छा वित्तीय प्रबन्धन सरकार ने यहां पर प्रस्तुत किया है। वर्ष 2006-07 के बजट एस्टिमेट्स 2171 करोड़ रुपये के हैं जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पिछली सरकार की बिजली निगमों की जो 2022 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं, उनको भी इस सरकार ने एक मुश्त देने का काम किया है। और उसके बाद भी 1149 करोड़ रुपये का सरप्लस रैवेन्यू भी दिया है। चेयरमैन सर, अब मैं सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारी सरकार ने कृषि से संबंधित बहुत सारी नीतियों के बारे में बहुत ही बढ़िया

निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार ने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जिनकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा रैली में की है। पहला तो जो किसानों का बैंकों के ऋण का ब्याज माफ करने का काम किया है। उससे किसानों और गरीब ग्रामीणों को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जो फसलों का ऋण है उसके लिए जो 11 प्रतिशत ब्याज होता था उस ब्याज की दर को सात प्रतिशत तक किया है जिससे हरियाणा के किसानों और गरीब ग्रामीणों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जो किसान समय पर ऋण का भुगतान कर देंगे उनको दो प्रतिशत ब्याज में छूट दी जायेगी। इसका प्रावधान भी सरकार ने किया है। पिछली सरकार केवल किसानों की हितैषी होने के दावे किया करती थी लेकिन आज उनकी पार्टी के नुमायन्दें इस बजट अभिभाषण पर बहस में भाग लेने के लिए सदन में मौजूद नहीं हैं। यह हम सब के लिए खेद की बात है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाये हैं जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ देने के लिए कटिबद्ध है। इस का एक उदाहरण गन्ने का 138 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब के भाव दिया जाना है। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने माननीय श्रीमती सोनिया गान्धी जी और माननीय प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलकर गेहूं का न्यूनतम मूल्य 850 रुपये प्रति क्विंटल करवाया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। सरसों और चने की फसल को भी सरकार ने कृषि बीमा योजना में शामिल किया है। प्राकृतिक आपदा के दौरान हाल ही में प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इतना ज्यादा मुआवजा किसी भी प्रदेश की सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान के लिए किसानों को नहीं दिया है। हमारे जिले में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी गये थे और वहां के किसानों की हमदर्दी लूटने के लिए किस प्रकार से उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए थे लेकिन आज सदन में उन्होंने किसानों के बारे में कोई बात नहीं कही और यहां तक कि उनकी बात तक सुनने के लिए वे यहां पर सदन में मौजूद नहीं हैं। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के जो किसान बढ़िया उत्पादन करते हैं उन्हें जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकार ने प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और बहुत से किसानों को प्रोत्साहित किया भी गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार के बनते ही ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन फी माफ कर दी थी। जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इसके अतिरिक्त किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल भी माफ करके किसानों को बहुत बड़ी राहत मुख्यमंत्री जी ने दी । किसानों पर बिजली के बिलों का बकाया एक तलवार की तरह उनकी गर्दन पर लटकता रहता था उन बिजली के बिलों को मुख्यमंत्री जी ने माफ करके किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि किसानों को डायरैक्ट सबसिडी देने पर हमारी सरकार विचार कर रही है और केन्द्र सरकार की भी यही मंशा है। मुझे उम्मीद है कि इसका निर्णय जल्दी ही ले लिया जायेगा जिससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा के कारण किसान या गरीब भाई अगर मर जाता है तो उसे पहले 50 हजार रुपये की सरकार की तरफ से मुआवजे के रूप में दिए जाते थे लेकिन हमारी सरकार ने उस 50 हजार रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। इसी तरह से किसानों को कर्जे राहत दिलाने के लिए हमारी सरकार ने जिला स्तर पर कर्जा राहत बोर्ड गठित किए हैं ताकि जिन डिजर्विंग लोगों को कर्जों में

[कुमारी शारदा राठौर]

राहत की जरूरत है उनको फायदा दिया जा सके । किसानों को अधिक फसल उत्पादन लेने के लिए सरकार की तरफ से विशेष ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मिट्टी की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। सभापति महोदय, जहां तक सिंचाई के पानी की बात है, पिछली सरकार ने एस०वाई०एल० के मुद्दे को लटकाए रखा और प्रदेश में जो पानी उपलब्ध था उसका भी बराबर बंटवारा नहीं किया गया। दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं करवाया। इस तरह से पिछली सरकार ने हरियाणा के किसानों के साथ भेदभाव की नीति को अपनाया जिसके कारण बहुत सारी भूमि प्रदेश में बंजर रही। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में उपलब्ध पानी के बराबर बंटवारे की बात की है। सभी को बराबर पानी का बंटवारा हो इसके लिए हमारी सरकार हांसी-बुटाना ब्रांच लिंक नहर का निर्माण करवा रही है। जिसका कार्य जोर-शोर से चल रहा है। इससे 16 जिलों के किसानों को फायदा होगा और वर्षों से प्यासी पड़ी भूमि की प्यास मिटेगी। इसी तरह से दादूपुर-नलवी नहर का काम भी शुरू हो गया है। सभापति महोदय, जहां तक पीने के पानी की बात है, आज प्रदेश में पीने के पानी की उपलब्धता में निरंतर सुधार हो रहा है। हमारी सरकार ने 1365 गांवों और 26 शहरों में पेयजल की बढ़ौतरी के लिए 359 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अकेले मेवात क्षेत्र के लिए 206 करोड़ रुपये राजीव गांधी पेयजल बढ़ौतरी योजना के तहत खर्च होंगे जिस पर काम शुरू हो गया है। मेवात क्षेत्र विकास के मामले में हमेशा आईसोलेटिड और कटा-कटा क्षेत्र रहता था। यही कारण है कि मेवात क्षेत्र विकास के मामलों में दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले पीछे रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने वहां पर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए विशेष प्रबन्ध किए हैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। इसी तरह से इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत हमारी सरकार ने एक नई अनूठी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 340 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और तीन साल की अवधि में इस योजना को पूरा किया जायेगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जन जाति के भाईयों को मुफ्त पानी के कनैक्शनों के साथ-साथ एक-एक परिवार को एक-एक पानी की टंकी और पाईप लाईन भी मुफ्त में दी जायेगी। हमारी सरकार ने निजी पेयजल कनैक्शनों के लिए गांवों में जो 500 रुपये और शहरों में जो 1000 रुपये फीस थी उसको माफ कर दिया है जिससे अनुसूचित जाति और जन-जाति के भाईयों को बहुत फायदा मिलेगा। पिछली सरकार जो चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी जिन्होंने पंच-सरपंचों के ऊपर गांवों के अन्दर विकास कमेटीज के नाम से कमेटीज बना करके लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ जो खिलवाड़ किया था हमारी सरकार ने आते ही न सिर्फ उन कमेटियों को एबोलिश किया बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों को, पंचों को, सरपंचों को, ब्लॉक समिति के सदस्यों को, म्यूनिसिपल कमेटियों के सदस्यों को मानदेय दिया है। चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाया है। उनकी हौंसला अफजाई के लिए उनकी सम्मान राशि में बढ़ौतरी की है ताकि वे अपना कर्त्तव्य निर्वाह ईमानदारी के साथ कर सकें। सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों को ही नहीं चौंकीदारों और नम्बरदारों को भी हमारी सरकार ने सम्मान राशि दी है। उनको जो सम्मान राशि मिलती थी उसमें बढ़ौतरी की है। हमारी सरकार ने नेत्रहीनों, विकलांगों, और विधवाओं की पैन्शन में भी बढ़ौतरी की है और हरियाणा में पहली बार बौनों और किन्नरों को भी पैन्शन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और स्वयं को समाज का जिम्मेदार अंग महसूस कर सकें। करनाल में एक डिफैंस कालोनी विकसित की जा रही है। हमारे शूरवीरों को भी जो सम्मान राशि दी जाती थी उसमें भी

हमारी सरकार ने बढ़ौतरी की है। भूतपूर्व विकलांग सैनिकों के लिए हमारी सरकार ने एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का फैसला किया है जो अपने आप में सराहनीय कार्य है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो बहुत कम रह गये हैं और एक-एक करके हमको छोड़ते जा रहे हैं जिन्होंने जंगे आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई उनकी सम्मान राशि 1400 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी थी और अब सीधे 5125 रुपये यह सम्मान राशि बढ़ाकर स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं हरियाणा की जनता की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। हरियाणा सरकार शहरों की तर्ज पर गांवों को भी विकसित करना चाहती है। गांवों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 59 गांवों को आदर्श गांव बनाने की सरकार ने घोषणा की है। इस कार्य पर 75 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। हमारी सरकार ने सड़क और परिवहन में भी अनेक लाभकारी योजनाएं दी हैं। आज जब हम हरियाणा के किसी भी क्षेत्र से निकलते हैं तो चारों ओर हमें विजिबल चेंज नजर आते हैं, बड़े परिवर्तन नजर आते हैं, चारों तरफ निर्माण कार्य होते नजर आते हैं। हरियाणा सरकार ने कई बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रावधान की मंजूरी केन्द्र सरकार से ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों को चौड़ा करने के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए जगह-जगह कार्य चल रहे हैं। सड़कों, बड़े पुलों के निर्माण हेतु पहले आबंटित राशि 225 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 409 करोड़ रुपये की है इसके लिए मैं सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। मैट्रो रेल जो अभी गुड़गांव तक है उसके लिए हमारी सरकार ने मुण्डका, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ तक मैट्रो रेल लाने के लिए दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार से बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इन तीनों जगह पर NCR में मैट्रो रेल अवश्य चलाई जायेगी। हमारे परिवहन विभाग ने भी अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं। बस अड्डों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रैन बसेरे बनाये जा रहे हैं। 681 बसें बदली गई हैं। बहुत सारी नई बसें खरीदी गई हैं। हरियाणा उदय, सारथी और हरियाणा गौरव जैसी अनेक ऐ०सी० बसें हमारे हरियाणा निवासियों के लिए चलाई गई हैं। लेखकों, साहित्यकारों, 100 प्रतिशत विकलांगों और जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं उनके लिए भी हमारी सरकार ने मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। इसके लिए परिवहन मंत्रालय भी बधाई का पात्र है। हमारी सरकार ने शहरों के विकास के लिए जहां-जहां जिन-जिन जिलों में मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है, जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए शहरों को विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया है। हर शहर में एक कंसलटैंट नियुक्त किया गया है। जो वहां की जरूरतों के मुताबिक जो कमियां हैं उनके बारे में अपनी रिपोर्ट देगा और सरकार वहां नीति बनाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास सुविधा के लिए सरकार ने "आशियाना" नामक योजना के तहत फलैट देने की योजना बनाई है। इस स्कीम के तहत 4 मंजिले फलैट बनाए जाने हैं जिनको आशियाना नाम दिया गया है ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सुविधा हो और उन्हें रहने के लिए आशियाना मिले। हमारे जिले फरीदाबाद पर मुख्यमंत्री जी की विशेष मेहरबानी हुई है। शहरी नवीनीकरण योजना के तहत 2200 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है जिसके लिए मैं फरीदाबाद निवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में कई अनूठी और लाभकारी योजनाएं हरियाणा सरकार ने दी हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है, शिक्षा के बिना विकास भी सम्भव नहीं है। शिक्षा को लेकर हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी बहुत संजीदा और गम्भीर हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो दूरगामी योजनाएं दी हैं उनके

[कुमारी शारदा राठौर]

परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत सकारात्मक मिलेंगे तथा इस कम्पीटीशन के दौर में, आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारे बच्चे भी दूसरी स्टेटस के बच्चों के साथ खड़े होंगे और उन्हें आउटपिच करने में कामयाब होंगे। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए और बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार ने कई अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं जिनसे परीक्षा परिणामों में भी सकारात्मक परिवर्तन नजर आएं हैं और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दाखिलों में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने शिक्षा का बजट 90 करोड़ से बढ़ा कर 540 करोड़ रुपये कर दिया है, राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय,दीनबंधू सर छोटू राम इन्जीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, सैमैस्टर प्रणाली लागू करना कुछ ऐसे फैसले हैं जो हरियाणा के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने में मददगार होंगे। उच्चशिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राईवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम भी हमारी सरकार ने लागू किया है। प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को ऐजुसैट नैटवर्क से जोड़ा गया है। सभापति महोदय, राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत पचास हजार प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत करने की सरकार की स्वागत योग्य योजना है। हर जिले में मॉडल स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं। स्टुडैंटस को किताबें, साईकलें और वर्दियां दी जा रही हैं। यहां तक कि बच्चों को नकद राशि भी प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने ज्यादातर स्कूलों को अपग्रेड किया है प्राईमरी, मिडल और मैट्रिकुलेट लैवल के स्कूलों को बहुत ज्यादा संख्या में अपग्रेड किया गया है। छः साल से चौदह साल की लड़कियों का 100% एनरोलमैंट करने वाली पंचायतों को हमारी सरकार एक लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रही है। सभी सरकारी स्कूलों में वे साईंस स्टुडैंट्स जो इन्जीनियरिंग कॉलेज में ऐडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को चाहे वह किसी भी स्कूल का प्रथम विद्यार्थी है, उसे सरकारी इन्जीनियरिंग कॉलेज में ऐडमिशन हमारी सरकार दिलवाएगी जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों में मेहनत करने की आदत डाले और उन्हें प्रोत्साहन मिले। आगामी वर्ष में छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को कम्पयूटर की शिक्षा भी उपलब्ध होगी। सभापति महोदय, शिक्षा के साथ ही साथ खेलों में भी आधारभूत संरचना के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। हर ब्लॉक में 40 लाख रुपये की लागत से बनने वाला एक-एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के गांवों को माननीय मुख्य मन्त्री जी आदर्श गांव घोषित कर रहे हैं। खिलाड़ियों को पुलिस में और अन्य नौकरियों में काफी वेटेज दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के खुराक भत्ते में भी वृद्धि की गई है। अभी राई में इनडोर हॉल बनाया जा रहा है जिससे हमारे बहुत से खिलाड़ियों को वहां पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। खेल अकादमी बनाने का हरियाणा सरकार का निर्णय भी सराहनीय है। सभापति महोदय, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न लाभकारी योजनाएं हरियाणा सरकार ने दी हैं। लड़कियों को तकनीकी संस्थानों में 2500 रुपये तक के फ्री किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन्जीनियरिंग कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ा कर 33000 कर दी गई हैं जो स्वागत योग्य हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टुडैंटस को हरियाणा में इन्जीनियरिंग करने का और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलेगा। लड़कियों को तकनीकी संस्थानों में ऐडमिशन दिलवाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण हमारी सरकार ने किया है जिसके लिए मैं हरियाणा की बालिकाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। सभापति महोदय, आज की इन्डस्ट्रीज की रिक्वायरमैंट को देखते हुए

तकनीकी संस्थानों के साथ प्राईवेट कम्पनीज के साथ एक समझौता हमारी सरकार ने किया है। जिसके तहत जो पुराने कोर्सिज चल रहे थे और अब जिनकी जरूरत नहीं थी उनको एबोलिस करके, उनको खत्म करके, आज की नई तकनीक से सम्बन्धित जो हमारे नये कोर्सिज हैं उनको शुरू किया जा सकता है। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च प्राथमिकता दी है। गत वर्ष बहुत सारे कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर्ज,बहुत सारे प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज बनाए गए थे और साथ ही साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्ज में एमरजैंसी सेवाएं चालू की गई थीं। 399 डिलीवरी हट्स भी अभी तक बनाई जा चुकी हैं। इसी तरह से 749 लाख रुपए से प्रजनन बाल स्वास्थ्य द्वितीय परियोजना शुरू की जा रही है। मातृ मृत्यु दर में और बाल मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। विकल्प नामक योजना हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाई गई है जिसका विस्तार सभी जिलों में किया जा रहा है। आशा नामक योजना के तहत 7000 वर्कर्ज हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना, आरोग्य कुष्ठ की स्थापना, 18 साल की स्कूली छात्राओं का हैल्थ का कार्ड बनाना, प्रत्येक जिले में मोबाईल यूनिट्स बनाना आदि ऐसी बहुत सी योजनाएं सरकार की हैं जो सीधे-सीधे हरियाणा के जनमानस को फायदा पहुंचा रहीं हैं। एस०सीज० और एस०टीज० के लिए जो मकान बनाए जाते थे उनमें पहले 10 हजार रुपए की सबसिडी दी जाती थी लेकिन हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उस सबसिडी को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया है जोकि स्वागत योग्य कदम है। इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत बिलो पावर्टी लाईन के परिवारों की लड़कियों को 5100 रुपए मिलते थे, उसको भी हमारी सरकार ने बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। यह हमारी सरकार का प्रशंसनीय कदम है। महिलाएं जो देश की आधी आबादी हैं उनको अगर विकास से दूर रखा जाए तो हम चहुंमुखी विकास करने का स्वप्न भी नहीं ले सकते हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के विकास और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी। पिछले वर्ष तो मुख्यमंत्री जी ने संवेदशीलता और गम्भीरता दिखाते हुए लड़कियों और लड़कों के लिंग अनुपात में जो भारी अन्तर आ गया था, उस अन्तर को पाटने के लिए वर्ष 2006 को बालिका वर्ष घोषित किया था जिसके तहत महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं दी गई थीं। इसके लिए मैं हरियाणा की बालिकाओं और महिलाओं की तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। आज गांवों में 6500 स्वयं सहायता ग्रुप महिलाओं के चल रहे हैं। जिनको हमारी सरकार 5000 रुपए प्रति ग्रुप सहायता दे रही है। इसके अलावा जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए भी साक्षर समूह बना रहे हैं ताकि हमारी पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं को विकास से सीधा सीधा जोड़ा जा सके और उन्हें उनका सम्मानित स्थान मिल सके। चेयरमैन सर, हरियाणा सरकार ने लाडली योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना और रक्षा बन्धन पर मुफ्त बस सेवा, आवासीय बोर्ड द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण, बिजली के कनैक्शनों में महिलाओं को 10 पैसे प्रतियूनिट में छूट, प्रापर्टी के हस्तांतरण में स्टाम्प ड्यूटी पर 2 प्रतिशत की छूट, टीचर्ज की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण, महिला विकास निगम से कर्जा लेने पर ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट, अनुसूचित जाति और जन-जाति की महिलाओं को बुटीक और ब्यूटीपार्लर खोलने के लिए 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की योजनाएं बनाई हैं। आज उन योजनाओं का जरूरतमंद औरतों को हरियाणा में फायदा मिल रहा है। इसके अलावा किशोरी शक्ति योजना भी सरकार द्वारा बनाई गई है। इस सरकार द्वारा सर्वोत्तम माता पुरस्कार भी दिया

[कुमारी शारदा राठौर]

जाता है और हर ब्लॉक लैवल पर जो बालिका मैट्रिक में फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड आती हैं उनको क्रमश : 2000, 1500 और 1000 रुपए का नगद पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा चेयरमैन सर, विधवाओं को जो पहले 300 रुपए पैंशन के मिला करते थे उसको हमारी सरकार ने बढाकर 350 रुपए कर दिया है। यह महिलाओं के उत्थान के लिए है, उनको सम्मान देने के लिए है। इसके अलावा और भी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की हैं। इसी तरह से दिल्ली के आसपास जो हरियाणा बसा हुआ है वह उद्योगों में एशिया में सबसे पहले नम्बर पर आता था लेकिन पिछली सरकार ने उद्योगों का भट्ठा बिठा दिया था। उस समय हरियाणा के उद्योग राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में चले गये थे लेकिन हमारी सरकार ने नयी औद्योगिक नीति जनता को दी है जिसकी वजह से उद्यमियों का और बाहर से निवेश करने वालों का हरियाणा सरकार पर विश्वास बढ़ा है और उन्होंने फिर से हरियाणा में अपने उद्योग स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की औद्योगिक नीति की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से प्रदेश में 29 बड़े और 1769 छोटे नये उद्योग आए हैं जिसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं क्योंकि इनसे हमारे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने अपनी इस अल्प अवधि में 22 हजार करोड़ रुपयों का निवेश हरियाणा में करवाया है। पानीपत में पेट्रो कैमीकल हब स्थापित होने जा रहा है जिससे पचास हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें लगभग 3500 छोटी-छोटी यूनिटस जुड़ी हुई होंगी जिसका फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा। इसी तरह से मानेसर आई०एम०टी० का भी विस्तार हो रहा है और इसी तर्ज पर फरीदाबाद, बहादुरगढ़, जगाधरी, खरखौदा और सोनीपत में नये इंडस्ट्रियल माडल टाउंज बनाये जा रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा श्रम नीति लागू करने वाला हिन्दुस्तान का पहला राज्य है। इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी, जो श्रम मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी । अभी हाल ही में यह निर्णय भी लिया गया कि श्रमिकों के न्यूनतम वेजिज 3510 रुपये होंगे। यह देश में सबसे ज्यादा हैं। मैं इस के लिए भी हरियाणा के श्रमिकों की तरफ से सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी। इसी तरह से एस०ई०जैड० बनाने की भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं। इसके तहत हमें 72 प्रस्ताव मिल चुके हैं और 49 को केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल गयी है। इसी तरह से विदेशों में हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार ने विदेशी रोजगार ब्यूरो का गठन किया है जिसका विधिवत कार्यालय पंचकूला में चालू हो गया है। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इसी मास की 6 तारीख को हमने अपने हरियाणा के युवाओं का पहला लॉट विदेश भेजा है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हजारों और नौजवानों को हम विदेश में रोजगार मुहैया करवा पाएंगे।

श्री सभापति : बहन जी, अब आप कंक्लूड करें।

कुमारी शारदा राठौर : सर, मैं कंक्लूड ही कर रही हूं। सर, इसका रजिस्ट्रेशन भी आन लाईन हो गया है और फ्री में वैबसाईट से इसकी जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा गुड़गांव में भी एक प्राईवेट प्लेसमैंट सैल की स्थापना की गयी है। जो लेबर वैलफेयर बोर्ड है उसका गठन हो चुका है। इसकी पहली मीटिंग में ही श्रमिकों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी नीतियों का फैसला किया गया है। हरियाणा सरकार ने कर प्रणाली में भी सुधार किया है। इसके लिए मैं

सरकार को बधाई देना चाहूंगी। इससे हमारा राजस्व बढ़ा है। इसी तरह से सरकारी कर्मचारी के लिए भी सरकार की जो योजनाएं हैं वह सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए भी हमारी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और उसी का नतीजा निकला है कि हरियाणा में आज कोई भी व्यक्ति बेखौफ रह सकता है और बेखौफ अपना व्यापार चला सकता है। पिछली सरकार की जो इस बारे में कारगुजारियां थीं उन पर चर्चा करने की अवश्य इच्छा होती है क्योंकि पिछली सरकार ने सैकड़ों अपराधियों को जो जेलों में थे, छोड़ दिया था। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते हुए घोषणा की थी कि हरियाणा को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी है। उन्हें इसमें कामयाबी मिली है। आज बहुत से अपराधी जेलों में हैं और जो जेलों में नहीं है वह प्रदेश को छोड़कर हरियाणा से भाग गये हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिस रामराज्य की स्थापना हमारे अच्छे लोग करते हैं आज वहीं रामराज्य हरियाणा में स्थापित हो गया है। धन्यवाद।

श्री दूड़ा राम (फतेहाबाद) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तथा वित्तमंत्री जी को वर्ष 2007-2008 का शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, गरीब, व्यापारी व कर्मचारी सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है। चेयरमैन सर, अब मैं सरकार की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगा। किसी प्रदेश का विकास उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश की स्थिति दूसरे प्रदेशों से बहुत अच्छी है। प्रति व्यक्ति आय में हमारा प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है जो कि शानदार उपलब्धि है। इसका मुख्य कारण अनुमान से 2500 करोड़ रुपये अधिक आय का होना है। किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए ऋण के काले कानून को समाप्त किया गया है और किसानों के लिए ऋण पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। किसान के लिए ब्याज माफी योजना एक सराहनीय कार्य है जिससे गरीब, ग्रामीणों तथा किसानों को लाभ होगा। सरकार ने किसानों को सबसिडी में सीधा लाभ देने की बात कही है। हरियाणा प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर गन्ने का मूल्य अन्य प्रदेशों से अधिक है। बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जो कि पिछले साल से 8 प्रतिशत अधिक हैं इंदिरा गांधी पेयजल योजना नामक नई स्कीम लागू करना भी सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पानी की आपूर्ति प्रति व्यक्ति 40 लीटर से बढ़ाकर 70 लीटर कर दी है। विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों की वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। सिंचाई के मामले में भी टेल तक पानी देने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। सड़कों के निर्माण के लिए राशि में वृद्धि करते हुए 225 करोड़ की तुलना में 409 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। शहरों की तर्ज पर गांवों के विकास के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जो कि सराहनीय कदम है। 59 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया है। शहरों के विकास के लिए 198 करोड़ रुपये की राशि जारी करना विकास का प्रतीक है। सरकार शिक्षा व खेल के क्षेत्र को भी उच्चतम प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं की शिक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हमारी सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए इस बजट में जो प्रावधान किया है, वह स्वागत योग्य है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए विशेष योजना को लाने का भी अच्छा कदम उठाया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार

[श्री दूड़ा राम]

द्वारा सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को वापिस लिया जा रहा है। व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ करों में कटौती की गई है। वैट में 135 करोड़ रुपये की राहत दी गई है जो कि बहुत अच्छा कदम है। इसके इलावा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा है इसके लिए मैं वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। चेयरमैन सर, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं का जिक्र करना चाहूंगा। फतेहाबाद जिले में खेतों में जो ढाणियां बसी हुई हैं उनके लिए बिजली की बड़ी भारी दिक्कत है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसी प्रकार से खेतों में बसी ढाणियों में लाईट देने का इन्तजाम करें क्योंकि एक घण्टा भी लाईट चली जाये तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके लिए चाहे एच०आर०डी०एफ० के तहत कोई व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के एम०पी०, खेतों में बिजली के पोल देने के लिए पैसा रिकमैण्ड कर देते हैं इसी प्रकार विधायकों के लिए भी कोई न कोई ऐसी ही व्यवस्था की जाए, यही मेरी वित्त मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है। चेयरमैन सर, फतेहाबाद जिला बनने के बाद वहां हैडक्वार्टर पर एक ही बड़ा होस्पिटल है। मैं वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस होस्पिटल को 60 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाए। फतेहाबाद जिला बनने के बाद वहां पर वाहनों की काफी आवाजाही हो गई है इसलिए फतेहाबाद शहर के लिए बाईपास बनाया जाए। शहर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एम०एम० कॉलेज में क्लासिज शुरू की जाएं। फतेहाबाद जिले में बड़ोपल गांव में बिजली घर है जिससे 15-20 गावों को बिजली सप्लाई की जाती है उस बिजली घर का दर्जा बढ़ाया जाये क्योंकि अब उन गावों में ट्यूबवैल्ज भी लगने शुरू हो गये हैं और बिजली की ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिजली घर को बड़ा बिजलीघर बनाया जाए। इसके अलावा फतेहाबाद में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाए। शहर में गन्दे पानी की निकासी के लिए डिस्पोजल की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जिला लाईब्रेरी की स्थापना की जाए। अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। बनगांव से मैन भट्ठू रोड़ तक, बीघड़ से बगूमोरी तक, मोची से दाहमान तक, धांगड़ से बरसीन तक, चौबारा से दहमान तक और धौलू से टिब्बी तक की सड़कें बनाई जाएं। जहां तक स्कूलों की बात है, इन स्कूलों का मिडिल से दसवीं तक दर्जा बढ़ाया जाए ये स्कूल सारी कंडीशनज पूरी करते हैं इनके नाम हैं चौबारा, ढाणी, ढोबा, माजरा, खजूरी जाटी, टिब्बी आदि। हाई स्कूल से बढ़ाकर 10 जमा दो के स्कूल अपग्रेड किए जायें उन गांवों के नाम हैं नाढोडी, ढिंगसरा कन्या स्कूल, भोड़िया खेड़ा, बरसीन और मोची चौबारा। अब मैं नगर पालिका के बारे में कहना चाहूंगा। नगर पालिका बनने के बाद फतेहाबाद शहर में सीवरेज की व सड़कों की हालत बहुत खराब है इसके बारे में मैंने नगरपालिका के चुनार्यदों की एक मीटिंग बुलाकर उनका एक रेजोलूशन भी सरकार को भेजा था इसलिए नगरपालिका की यह मांग पूरी की जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, जयहिन्द।

श्रीमती अनिता यादव (साल्हावास) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से हमारे काबिल वित्त मंत्री जी के बजट पर चर्चा की है। उन वक्ताओं ने अपनी बातों में यह भी दोहराया कि बड़े खेद की बात है कि विपक्ष के साथी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं भी आपके माध्यम से यह कहना

चाहती हूं कि दुर्भाग्य तो प्रदेश के उन लोगों का है जिन्होंने ऐसे नालायक लोगों को चुनकर भेजा। जिन लोगों को न किसी के हित से कुछ लेना-देना है, न सदन की मर्यादाओं से कुछ लेना देना है। उनका मकसद शोर -शराबा करके सदन का समय बर्बाद करना होता है। जिसके कारण हमारे कई सदस्यों का बोलने का समय कट जायेगा। सभापति महोदय, मैं पिछले पांच साल भी इस सदन की सदस्या थी। उस समय ये लोग सत्तापक्ष में थे और हमारे मुख्यमंत्री जी विपक्ष के नेता थे। उस समय चौटाला जी ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करते थे जो शब्द प्रजातांत्रिक प्रणाली में यूज नहीं होने चाहिएं। उस समय वे कहा करते थे कि "जब तक जीऊंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा" और ऐसा मुख्यमंत्री रहूंगा जिसके नाम के खौफ से बच्चे चारपाईयों से गिर जायें और खाना खाते अधिकारी खड़े हो जायें। सभापति महोदय, समय ने करवट बदली और आज स्थिति सभी के सामने है। सभी को मालूम है कि जिसमें रावण रूपी अहंकार हो जाये वह आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। रावण भी अपने अहंकार के कारण ही मारा गया था। उसे अपने ज्ञान का बहुत घमण्ड हो गया था। यही कारण है कि उस समय रावण ने यहां तक कह दिया था कि-

"इंद्र तो मेरे छिड़े लावे, पवन बुवारी दे से, बे माता मेरे पीसे पीसना, काल कूआ में लटके"

सभापति महोदय, चौटाला साहब में भी रावण रूपी अभिमान आ गया था। उनके राज के समय प्रदेश की जनता को जिस तरह से रौंदा जाता था और विधायकों को हैलीकोप्टरों में ले जाकर पीटा जाता था ये बातें किसी से छिपी नहीं हैं। मेरा यह मानना है कि बीजेपी के जो विधायक बड़े काबिल आदमी भी हैं, वे इस समय सदन में नहीं बैठे। कल परसों अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारी विधायिका महोदया यहां बैठी हुई हैं। उन्होंने अनपढ़ता की बात कही थी। इस तरह के अनपढ़ लोग यहां पर चुन कर आ जाते हैं जो अनपार्लियामैंटरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सदन की वैल में आ जाते हैं तथा सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देते । इस तरह के लोगों की बजाय पढ़े लिखे लोगों को जनता को चुनकर भेजना चाहिए। पार्टी के मैनीफैस्टों में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता निर्धारित करनी चाहिए अथवा हाई कमान को इस बारे में सोचना चाहिए लेकिन इनकी तो कोई हाई कमान ही नहीं है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी पार्टी की तरफ से इस सदन में 6 एडवोकेट हैं और दो एम०एस० डाक्टर हैं। मैं समझती हूं कि काफी क्वालीफाईड लोग हमारी पार्टी में विधायक या मंत्री हैं जबकि पिछली सरकार में 8वीं फेल विधायक हुआ करते थे। जिनमें 5-7 विधायक ऐसे थे जो पव्वा पीकर सदन में आया करते थे। वे विधायक रात को शराब पीते थे और सुबह पेस्ट भी शराब से ही करते थे। इस तरह के विधायकों को जनता चुनकर गलत करती है। जब कांग्रेस पार्टी ने अच्छे योग्य लोगों को टिकट दिया था तो उनको चुनकर भेजना था लेकिन उनकी अपनी कोई बात होगी जो वे चुनकर नहीं आ सके। लेकिन ऐसे लोगों को चुनकर भेजने से सभी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई लेकिन विपक्ष के साथियों ने चर्चा में भाग नहीं लिया। प्रदेश में ओलावृष्टि हुई। जिससे उनके हल्कों में भी नुक्सान हुआ है। उनको इस बारे में सदन में चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन उनका मकसद केवल शोर-शराबा करना ही था। किसी भी मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात सदन में नहीं की। मैं तो उन लोगों से इतना ही जानना चाहती हूं कि क्या उनको इस बात का पश्चाताप है कि वे कहा करते थे कि जब तब जीऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। क्या अब वे इसका प्रायश्चित कर रहे हैं। सभापति महोदय, जहां तक राम राज की बात आई जैसा कि मैंने कहा कि जब प्रजा पर संकट आते हैं तो कोई न कोई हस्ती पैदा होती है जो कष्टों का निवारण करती है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय आज पूरे

[श्रीमती अनिता यादव]

देश में हरियाणा की कष्ट निवारण हस्ती के रूप में जाने जा रहे हैं। चौटाला जी को भुगतना पड़ा है। अब हमारी सरकार बनी है तो 20 साल तक हमारा राज कहीं नहीं जायेगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने और कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में जो भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। हमारी सरकार ने किसान, मजदूर सभी को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया है और सरकार ने ऐसे अभूतपूर्व फैसले लिए हैं जिनका हमारे मैनिफैस्टों में जिक्र भी नहीं था। हमारी सरकार ने बिजली के 1600 करोड़ रुपये के बिल माफ किये। ओमप्रकाश चौटाला जी के स्वर्गीय पिता जी को पता नहीं किस तरह से लोग अच्छा आदमी मानते हैं, आज वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में जाने के बाद तो बुरे आदमी की भी लोग तारीफ कर ही देते हैं। वो लोगों को कहते थे कि तुम बिजली के बिल मत भरना। न मीटर होगा और न रीडर होगा। मेरी सरकार आयेगी और मैं सारे कर्जे माफ कर दूंगा। एक अधिकारी ने कहा कि कैसे माफ कर देंगे। उन्होंने अधिकारी को कहा कि आप ऊपर लिख देना कि बिजली के सब बिल माफ और नीचे मैं लिख दूंगा 'देवीलाल'। इस तरह से उन्होंने जनता के साथ, किसानों के साथ धोखा किया है और वे बेचारे भटक गये जिसकी वजह से आज प्रदेश पर इतना बोझा हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की यह सोच है हालांकि यह हमारे मैनिफैस्टो में भी नहीं था। हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं था, हमने कोई जिक्र भी नहीं किया था उसके बावजूद भी किसानों की भलाई के लिए 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ कर दिये। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व फैसला था और इसके साथ ही अभी तो बिजली का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने 844 करोड़ रुपये का पेश किया है वो भी सराहनीय कदम है। हमारा कोसली सब डिवीजन है उसमें अभी सिटी फीडर लगाया गया है। मेरी वित्त मंत्री जी से गुजारिश है कि उसमें भी एक दो करोड़ की बढ़ौतरी करके थर्मल प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा दें तो वहां के लोगों को सुविधा हो जायेगी। पूरे भारतवर्ष में इस बात का जिक्र है कि जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उनको जो नया जीवन मिला है उस नये जीवन के साथ उन्होंने संकल्प लिया है कि जो बाकी जिन्दगी है वह प्रदेश के हित में लगाऊंगा और जो जिन्दगी मिली है वह समाज के लिए काम करने और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने के लिए मिली है। मैं सबको साथ लेकर काम करूंगा और उनको सम्मान दूंगा। उनकी इस बात से मुझे हर्ष होता है। हरियाणा के लोगों ने जब चौटाला साहब, को नकार दिया था तब चौटाला को इस बात का पता चल गया था कि उनका बेटा एम०पी० का इलैक्शन नहीं जीत सकता तो उन्होंने अपने बेटे को राज्यसभा का मैम्बर बना दिया। आज मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी यू०पी०ए० की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और अपने मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 36 बिरादरी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए डाक्टर रामप्रकाश जैसे सम्मानित शिक्षाविद व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनित किया है। मैं सदन और अपने माननीय साथियों को इस बात के लिए बधाई देती हूं कि ऐसे 36 बिरादरी की शख्सियत को जो हमेशा ही अपनी काबलियत से पहचाने गये उनको राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनित किया गया। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो अधिकारी पिछले राज में चौटाला जी के साथ थे सदन के माध्यम से उनका भी कुछ न कुछ हिसाब करना चाहिए। जो अधिकारी उनके सामने खाना छोड़कर खड़े हो जाते थे और प्रदेश के लोगों के साथ ज्यादती करते थे तथा जनता की बातों को अनसुनी करते थे ऐसे अधिकारियों की खबर लेनी चाहिए। चौटाला जी को भी यह पता चल गया था कि इतनी भारी ज्यादती करने के बाद कोई भी इन्सान उस जगह नहीं रुक सकता। जब उनको यह पता चल गया कि प्रदेश में उनका सूपड़ा

साफ होने वाला है तो उन्होंने एच०पी०एस०सी० के मैम्बर और चेयरमैन को बदलकर दोबारा नये मैम्बर और चेयरमैन लगा दिये। इस तरह की सोची समझी चाल, जिस तरह की मक्कारी, गद्दारी, तानाशाही और इस तरह का अभद्रतापूर्ण व्यवहार प्रदेश की जनता के साथ हुआ उसका खामियाजा, जनता को भुगतना पड़ा। इसके साथ ही साथ इरिगेशन की बात आती है 718 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान जो हमारे प्रदेश में हुआ है वह सराहनीय है। आदरणीय मुख्यमन्त्री जी ने पहले दिन हाउस में आते ही यह कहा था कि मेरी जो बाकी की जिन्दगी बची है वह मैं प्रदेश के लोगों के हितों में और संसाधनों के समान बंटवारे में लगाऊंगा। एक बाप के चाहे चार बेटे हैं तो एक रोटी को सबको बांट कर देता है। उन्होंने कहा मैं चार हिस्सों में बांट कर सभी बेटों को बराबर रोटी दूंगा, यह मेरा निर्णय है और सरकार आने के बाद उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। चेयरमैन सर, इरिगेशन का जो पानी अढ़ाई जिलों में जा रहा था उस पानी को पूरे हरियाणा में समान बंटवारा करके जो इन अढ़ाई जिलों की सेम की समस्या थी इस बंटवारे से उसका निवारण हुआ है और हमारे वे इलाके जो प्यासे मर रहे थे, वहां के जो लोग तिसाए मर रहे थे उनको पानी मिला। इस तरह से 268 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा के लिए नहर बनवाई जा रही है। इस नहर का काम तेजी से चल रहा है और जब फटाफट यह नहर बन कर तैयार हो जाएगी तो आप जानते हैं कि हमें उतना पानी मिलेगा जितना हम चाहते हैं और शायद उससे भी ज्यादा पानी हमें मिलेगा। चेयरमैन सर, इस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर साहब शायद बाहर गये हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि सिंचाई के लिए 718 करोड़ रुपये की राशि का बजट में जो प्रावधान किया है उसमें खुसपुरा माईनर का मैं जिक्र करना चाहती हूं। पता नहीं किस कारण से यह माईनर इनसे मिस हो गया है। मैंने इस बारे में दो-तीन बार इनको लिख कर भी भिजवाया है तथा पिछले सैशन में भी मैंने इस बारे में आवाज उठाई थी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं खुसपुरा माईनर का जिक्र दोबारा से करना चाहती हूं कि इस माईनर की रिपेयर करवा कर इसमें पानी छोड़ा जाए ताकि वहां के किसानों को भी लाभ हो सके। इसके साथ ही साथ मैं पेयजल योजना का भी जिक्र करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार सभी वर्गों को पानी देने के लिए कृतसंकल्प है। हरिजन बस्तियों के लिए विशेष तौर से पानी का प्रावधान किया गया है। पीने के पानी की टंकी सभी हरिजन भाईयों को फ्री मुहैया करवाई जाएगी, सभी कॉलोनियों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, हरिजन कॉलोनियों में पानी पहुंचाया जाएगा और इसके साथ ही साथ पानी के कनैक्शन के साथ उनको एक टूटी भी फ्री दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की इस तरह की सोच है। मैं यह कह सकती हूं कि आज हम जहां खड़े हैं हमारे हल्के के सभी वर्गों के लोग इतने सैटिस्फाईड हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। पिछली सरकार के वक्त में वे इतने दुखी थे कि एक-एक बून्द पानी के लिए भी तरसते थे लेकिन हमें पीने के पानी की एक बून्द तक नहीं मिलती थी। आज हमारी इस सरकार ने सिंचाई के पानी के साथ ही साथ पीने के पानी की सुविधा को मुहैया करवाया है इसलिए मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी का और विशेषतौर पर फाईनैंस मिनिस्टर का भी धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने पेयजल के लिए 632 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के लिए जो राशि दी गई है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। आप भी पिछली सरकार के समय इस सदन के सदस्य थे और इस तरह की कारगुजारी आप अक्सर देखा करते थे कि मुख्य मन्त्री जिस गांव में जाते थे वहां पर एक दिन पहले कर्मचारी जो कूड़ादान होता था उस पर जे०सी०बी० लगा कर सैम्पल करवा देते थे। मेरे घर के सामने ही मेरे साल्हावास विधान सभा क्षेत्र से दो पूर्व विधायक थे और वहां पर जब भी

[श्रीमती अनिता यादव]

चौटाला साहब गये हर बार ऐसा हुआ। मैं अक्सर गांव ही जाती रहती हूं मुझे यह देखने को मिला कि जहां भी इनका दौरा होता था वहां पर मिट्टी डाल देते थे या कूड़ादान को सीधा करके एक दिन का काम चला लेते थे और कागजों में एण्ट्री पूरी कर देते थे। डा० सीता राम जी यह कह रहे थे कि उनकी कोई सैटिंग होती थी लेकिन आज मुझे यह कहते हुए भी फख्र महसूस होता है कि उनके जो विधायक और पूर्व विधायक है उनके सामने भी हमारी सरकार ने ईंटों के खड़ोंजे बनाए हैं और आज हमारी हरियाणा सरकार की गाड़ियों के साथ-साथ जहां पर किसान भाई हैं, जहां पर हमारे मजदूर भाई हैं, जहां पर हमारा गरीब तबका है, जहां पर हमारी बैलगाड़ियां हैं, जहां पर हमारी ऊंटगाड़ियां हैं, जहां पर हमारी रिक्शा हैं किसी को भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। हमारी सड़कें पूरी तरह से कामयाब हैं और अभी अधिकारी से मेरी बात भी हुई थी वे कह रहे थे कि जिन सड़कों पर मुरम्मत नहीं हुई है वह मैं लिखकर भिजवा भी दूंगी। स्पीकर सर, मुख्यमन्त्री और अधिकारियों का चोली दामन का साथ होता है। मुझे एक मिसाल याद आ गई। कई बार ऐसा होता है किसी चौधरी के यहां पोता हो जाता है तो हमारे कल्चर में आप जानते हैं कि पोता होने के बाद गुड़ की भेली लेकर जाते हैं। जब गुड़ की भेली लेकर चौधरी छोरी के घर जाता है या बहु के पीहर जाता है यानि चौधरन के घर जाता है तो उसको शॉल भी पहनाई जाती है और हल्वा तथा खीर भी परोसी जाती है। चौधरी के लिए जब हल्वा खीर परोसी गई तो चौधरी ने गर्म गर्म हल्वा मुंह में डाल लिया और मुंह जलने से बचाने के लिए ऊपर को भांप लेते हुए कहा कि चौधरन मकान तो बढ़िया बना रखा है। चौधरन ने कहा तुम्हारी भांपों से बच जाएगा तो अच्छा ही है। स्पीकर सर, अधिकारियों का रवैया ठीक रहेगा तो सरकार बहुत अच्छा कार्य करेगी। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव यह है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी की सोच बहुत अच्छी है और ये 36 बिरादरी का ध्यान रखते हैं, महिलाओं का ध्यान रखते हैं और सभी अधिकारियों का भी ध्यान रखते हैं। स्पीकर सर, आज मैं अधिकारियों के बारे में बात कहना चाहूंगी। मेरे कहने का यह भाव है कि हम एम०एल०एज० भी जब उनको फोन करते हैं तो वे हमारी फोन कॉल्ज अवश्य अटैंड कर लिया करें। हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं वे इन अधिकारियों के लैवल पर ही हो सकते हैं उन कामों के लिए हमें हमारे उदार मुख्यमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं। जो लोग आज अपोजीशन में बैठें हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत अकल होती तो आज जो सदन में बजट पर चर्चा हो रही है वे लोग उस पर चर्चा करते।

श्री अध्यक्ष : अनिता जी आफ कन्कलूड करें। आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, आज हम सत्ता पार्टी में हैं आज तो हमें बोलने का मौका दें। चौटाला जी की पिछली सरकार के वक्त में तो आपको भी पता है कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था।

स्पीकर सर, मैं शिक्षा के बारे में बोल रही थी कि उस वक्त की सरकार के समय में उनके सदस्यों को खुद को पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था और यहां पर बैठे बैठे ये इंग्लिश मैगजीन देखा करते थे। उनमें जो रंगीन चित्र होते थे उनको देखा करते थे। इस बात को किसी प्रैस वाले ने भी देख लिया था और अगले दिन वह बात अखबारों में छप गई थी। इस तरह से अनपढ़ लोग तो उस वक्त की सरकार में थे। स्पीकर सर, मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि बिहरड़ कालेज को अपग्रेड करके कन्या महाविद्यालय बना दिया जाए। (विघ्न) पिछली सरकार के वक्त में गली-सड़ी

शिक्षा मिला करती थी लेकिन आज हमारी सरकार के वक्त में बहुत ही बढ़िया शिक्षा हरियाणा में दी जा रही है। जब हमारी सरकार आई थी तो बच्चों के मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है किस तरह से समझाबुझा कर हम उन बच्चों को दोबारा से स्कूलों में लेकर आए हैं आज हमको उनको समझाना पड़ रहा है कि पिछली सरकार चली गई है। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी यहां पर बैठे हुए हैं और इन्होंने हमारे प्रदेश की कमान अच्छी तरह से सम्भाली हुई है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि नाहड़ गवर्नमैंट कालेज जो प्रोवीजन रखा जा रहा है उसमें साईंस फैकल्टी को और बढ़ाया जाए। वहां पर जो मिडिल स्कूल हैं उनको हॉयर सकैन्डरी स्कूल अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा हमारे यहां कौसली में भी एक कॉलेज खोला जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां के बच्चे शिक्षा में और गुणवत्ता हासिल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात भी करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, तूलोड़, झाल, साहत नगर और जाहूसाना ब्लॉक के स्कूल हैं उनको भी अपग्रेड करवाने का काम करें। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, पिछली सरकार के वक्त में कोई महिला शाम के समय में घर से बाहर निकल नहीं सकती थी क्योंकि जैसे ही वह बाहर निकलती थी गुण्डे लोग गले से चेन छीन कर भाग जाया करते थे। हरियाणा प्रदेश में बड़े-बड़े गुण्डे आ गए थे। पिछली सरकार के वक्त में मैं अकेली महिला एम०एल०ए० अपनी पार्टी में थी लेकिन मुझे भी यहां पर कोई कमरा या फ्लैट नहीं दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, एम०एल०ए० हास्टल में उस समय लम्बे लम्बे लड़के शराब पीकर घूमते रहते थे। स्पीकर सर, जैसे मेरे से पहले बोलते हुए पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हरियाणा को एक बाप और दो बेटे लेकर बैठ गए हैं। उनकी सरकार के जाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार की कमान सम्भाली है और हरियाणा की तरक्की के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किये हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्षम महोदय, इसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। पिछली सरकार के समय में हमने नाहड़ होस्पीटल के लिए एक कमरा मांगा था लेकिन उस समय एक कमरा ही एक साल में बनाया गया था और उसके लिए भी साफ साफ कहा गया था कि अनिता यादव वहां पर जाकर अपना इलाज करवाओ। उस समय तो सब जगहों पर पत्थर लगाकर ही छोड़ दिया जाता था। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि हमने यहां पर 35 बिस्तरों वाला होस्पीटल मांगा था जिसको उन्होंने 35 बैड का ही मंजूर किया है। जिस

[श्रीमती अनिता यादव]

नाहड़ गांव के होस्पीटल की बात हमने उनसे की थी उन्होंने उस गांव को ही फोकल गांव का दर्जा दे दिया। इस तरह से कहां हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है और कहां पिछली सरकार की सोच थी जिसके लोग प्रदेश की जनता को गुमराह किया करते थे। इस तरह से आज प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। हैल्थ मिनिस्टर साहिबा इस समय बैठी नहीं हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हैल्थ के लिए उन्होंने काफी पैसा दिया है। इसी तरह से बाल विकास के लिए भी काफी पैसा दिया गया है। लगभग 116 करोड़ रुपयों का उन्होंने इसके लिए प्रावधान किया है। इस प्रकार से जो भी हमने मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए मांगा वह उन्होंने हमें दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहती हूं कि इन कार्यों को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जाए ताकि हमारे लोग जो काफी लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं वह पूरी तरह से इनका फायदा उठा सकें और अमन चैन से रह सकें। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने किन्नरों के लिए भी, बौनों के लिए भी जिनके लिए डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं था, को राहत प्रदान की है। इसी तरह से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सरकार ने राहत प्रदान की है। इसी प्रकार से व्यापारी भाईयों को वैट से राहत प्रदान की है। विकलांगों को, नेत्रहीनों को, चौकीदारों को भी राहत प्रदान की गयी है। चौकीदारों को सरकार ने टॉर्च और लाठी देने की सुविधान प्रदान की है ताकि वे मस्त रहें और आराम से गांवों का दौरा करें। इस तरह से सभी वर्गों को रिलैक्सेशन मुख्यमंत्री जी ने दी है। हमारे फाईनेंस मिनिस्टर ने हर तरह से हर वर्ग को सुविधा प्रदान करने की पूरी पूरी कोशिश की है। आज हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कटिबद्ध है पिछली बार सरकार ने थोड़े समय के लिए ही सरसों की पर्चियां बनवायी थीं लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री जी ने अपने किसान भाईयों के लिए यह प्रावधान कर दिया है कि वे तीस तारीख तक अपनी सरसों की पर्चियां कटवा लें। उसके बाद जिस किसान भाई का नम्बर आएगा वह अपना अनाज बेच सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 20th March, 2007.

*18.34 Hrs. The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 20th March, 2007.

42842—H.V.S.—H.G.P., Chd.